राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 63

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 12 अगस्त, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

स्वतंत्रता के सारथी
महामारी से आजादी

जिद और जज्बे से खोली रक्तदान की राह

शिमला : कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश के एक संगठन ने कर्फ्यू के बीच भी जरूरतमंद लोगों के लिए रक्त की व्यवस्था की। उमंग फाउंडेशन ने सरकार से विशेष आग्रह कर रक्तदान की गाइडलाइन जारी कराई और शिविर लगे। (पेज-6)

ओबीसी पर राज्यों के अधिकार बहाल करने संबंधी विधेयक संसद से पारित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राज्यसभा में इस संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में पड़े 187 वोट, विरोध में नहीं पड़ा कोई मत
- सरकार का कांग्रेस को जवाब, सत्ता से बाहर रहने पर आती है ओबीसी की सुध, सत्ता में रहते नहीं दिया कोई हक

राज्यसभा में बुधवार को ओबीसी से जुड़े विधेयक पर बोलते केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार। प्रेट्र

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार बहाल करने संबंधी संविधान का 127वां संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया। लोकसभा एक दिन पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में सत्तापक्ष व विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। विपक्ष ने सरकार पर ओबीसी के नाम पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया और कहा, यह प्रेम विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए है। वहीं, सत्ता पक्ष ने कहा,हम विपक्ष जैसी राजनीति नहीं करते, जो ओबीसी की मदद से सत्ता में तो पहुंचे, लेकिन सत्ता में रहने के दौरान उनके लिए कुछ नहीं किया।

राज्यसभा में इस विधेयक पर पांच घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। इस दौरान सभी दलों ने विधेयक का समर्थन किया। यही वजह रही कि इसके पक्ष में कुल 187 मत पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. वीरेंद्र कुमार ने विपक्ष के उठाए सवालों का बेहद सधे ढंग से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग सामाजिक-आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, वे जब सत्ता में थे तो ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि यह रिपोर्ट उनके कार्यकाल में ही आ गई थी।

आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए: डा. वीरेंद्र कुमार ने आरक्षण की 50 फीसद तय सीमा के मुद्दे पर एक बार फिर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा, निश्चित ही इस पर नए सिरे से विचार होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में जब यह व्यवस्था दी थी, तब से 30 साल का समय हो गया है। उस समय स्थिति कुछ और थी, आज कुछ और है।

आरोप-प्रत्यारोप का चला दौर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विरोधी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को लाने के पीछे उप्र सहित कई राज्यों में होने वाले विस चुनावों में फायदा लेने की सरकार की मंशा का मुद्दा उठाया, इस पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने आपत्ति जताई और कहा, कांग्रेस की यही सोच है, वह हर चीज को सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखती है। मोदी सरकार ने इससे पहले ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। मेडिकल कालेजों में दाखिले से जुड़ी 'नीट' के आल इंडिया कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का काम किया है। इस दौरान खड़गे ने सरकार से मांग की कि वह निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करे। वह सरकार का समर्थन करेंगे। साथ ही बैकलाग के खाली पदों को भरने का मुद्दा उठाया। भूपेंद्र यादव ने कहा, विपक्ष को समझना चाहिए कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल रही है। हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी उसके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आठवले के चुटीले अंदाज पर हंगामा: चर्चा के दौरान उस समय हंगामा शुरू हो गया, जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस पर हमला बोला। जिस पर कांग्रेसी सदस्य उग्र हो गए और उनके शब्दों को कार्यवाही से हटाने की मांग पर अड़ गए। काफी देर तक सदन में शोर-शराबा होता रहा।

डर पैदा करने और समाज तोड़ने का काम करती है सपा : प्रधान पेज>>3

न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

1500 किमी रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण

बालेश्वर : भारत ने बुधवार को स्वदेशी तकनीक से बनी 1500 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे समुद्र, जमीन व मोबाइल लांचर तीनों तरीके से दागा जा सकता है। यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम तक पारंपरिक व आणविक युद्धास्त्र लेकर जाने में सक्षम है। इसकी गति ध्वनि गति से सात से नौ गुना अधिक है। बुधवार को नौवीं बार इसका परीक्षण किया गया। इसका बूस्टर इंजन भारत में ही तैयार किया गया है। निर्भय मिसाइल का वजन एक हजार 500 किलो है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 7

सरकारी-निजी क्षेत्र की भागीदारी से ही आत्मनिर्भर होगा देश

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अकेले सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इस काम में उद्योग जगत की बहुत बड़ी भागीदारी की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य ब्रांड इंडिया को मजबूत करने के साथ देश को समृद्ध करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्योग जगत के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करना होगा। उद्योग संगठन सीआइआइ के साथ संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर्फ एक पहिये से गाड़ी नहीं चल सकती। सारे पहिये ठीक से चलने चाहिए।

आज का मैच

दूसरा टेस्ट
भारत vs इंग्लैंड
दोपहर 3:30 बजे से
स्थान लंदन
प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

हंगामे के चलते मानसून सत्र समय से पहले खत्म

गतिरोध ▶ 13 अगस्त तक चलनी थी संसद, लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 28 फीसद ही हुआ कामकाज

लोकसभा अध्यक्ष ने जताया अफसोस, कहा- संसद चर्चा के लिए, गतिरोध के लिए नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- हंगामे की वजह से दोनों सदनों का ज्यादातर समय हुआ बर्बाद
- रास में आखिरी दिन विपक्ष के हंगामे के कारण सभापति के इर्दगिर्द मार्शलों ने बनाया सुरक्षा घेरा

लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में मोदी और सोनिया : संसद के मानसून सत्र के समापन के साथ बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद विभिन्न दलों के नेताओं ने लोस अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कक्ष में मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी व पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। प्रेट्र

रास में अभद्रता करने वाले सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई तय, नेता सदन ने रखा प्रस्ताव

राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों की अभद्रता पर सरकार ने बुधवार को कड़ा रुख दिखाया और इसे अक्षम्य करार दिया। मानसून सत्र की समाप्ति के मौके पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने सदन में जिस तरह का आचरण किया है, वह निंदनीय है। इन सदस्यों ने न सिर्फ सभापति की गरिमा का अपमान किया, बल्कि सदन के कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। उन्होंने सभापति से मांग की कि इन सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे सदन की गरिमा बनी रही। इसे लेकर एक स्पेशल कमेटी गठित की जाए जो पूरे मामले की गहराई से जांच करे।

विपक्ष के भारी हंगामे के चलते आखिरकार संसद का मानसून सत्र बुधवार को तय समय से दो दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। यह 13 अगस्त तक प्रस्तावित था। इस बीच सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक सहित अपने सभी जरूरी कामकाज निपटा लिए। सत्र के दौरान कुल 20 विधेयक पारित कराए गए। लेकिन कामकाज के लिहाज से स्थिति गंभीर रही। लोकसभा में 22 फीसद और राज्यसभा में 28 फीसद ही कामकाज हो पाया। 'प्रेट्र' के मुताबिक, राज्यसभा में सत्र के आखिरी दिन अभूतपूर्व नजारा दिखाई दिया जब बीमा संशोधन विधेयक पेश किया गया तो विपक्षी सदस्यों ने सभापति के आसन के समीप आकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान 50 मार्शलों ने सभापति के इर्दगिर्द सुरक्षा घेरा बना लिया। विपक्षी सदस्यों ने कुछ कागज फाड़े और सभापति व सदन के अधिकारियों की ओर उछाल दिए। मार्शलों के साथ धक्का-मुक्की भी की।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में पैदा किए गए गतिरोध के कारण वह बहुत दुखी हैं। लोगों की पीड़ा को समझते हैं क्योंकि इस बार भी लोक महत्व के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। यह पीड़ादायी है और लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। सदस्यों का समझना होगा कि संसद चर्चा के लिए है, गतिरोध के लिए नहीं। पूरे सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 17 बैठकें ही हुईं, जिसके लिए 96 घंटे का समय तय था, लेकिन व्यवधान के चलते 21 घंटे ही काम हुआ। उन्होंने कहा,सदस्यों का तख्तियां दिखाना व कूप में आकर नारेबाजी करना परंपरा के अनुरूप नहीं है। राज्यसभा में भी कुल 17 बैठकें हुईं जिसके लिए 102 घंटे का समय तय था, लेकिन सिर्फ 28 घंटे ही काम हो पाया।

बुधवार को लोस को जहां सुबह कार्यवाही शुरू होते ही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, वहीं राज्यसभा में सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक, बीमा और होम्योपैथी विधेयक को पारित कराया। ज्ञात हो, संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई, 2021 को शुरू हुआ था। (संबंधित खबरें पेज-3 पर)

कुछ लोगों के बीच अवरोध पैदा करने की प्रतिस्पर्धा : नायडू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पीड़ाजनक

- सदन की मर्यादा भंग करने वालों के आचरण पर रो पड़े वेंकैया
- कहा, तय कीजिए कि बेस्ट सांसद बनना है या फिर अवरोधक

राज्यसभा में बुधवार को कार्यवाही के संचालन के दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू। एएनआइ

बुधवार को मानसून सत्र की समाप्ति हो गई लेकिन विरोध और नारेबाजी के कारण इसे 'हुड़दंगी सत्र' के रूप में देखा जाएगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू तो कुछ सदस्यों के आचरण से क्षुब्ध होकर आखिरकार रो ही पड़े।

बुधवार को भावुक होते हुए उन्होंने कहा, मानसून सत्र में कुछ धड़ों के बीच अवरोध पैदा करने की प्रतिस्पर्धा दिखी। इस क्रम में संसदीय परंपरा और मर्यादा को तार तार किया गया। अगर इस पर गंभीरता से आत्मचिंतन नहीं होता है और आचरण में सुधार नहीं किया गया तो संसदीय लोकतंत्र अप्रासंगिक हो जाएगा। ध्यान रहे कि कुछ दिन पहले ही मंत्री के हाथ से दस्तावेज छीनकर उसे फाड़कर उछालने की घटना हुई थी। तब संबंधित सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। मंगलवार को तो हद ही हो गई। विपक्ष के कुछ सदस्य मेज पर चढ़ गए और मोबाइल से वीडियो बनाकर बाहर भेज दिए। कई बार गुत्थमगुत्था की भी स्थिति पैदा हुई।

बहरहाल मंगलवार को राज्यसभा की घटना ने सभापति नायडू को इतना व्यथित कर दिया कि सदन के अंदर उनका गला रुंध गया। उन्होंने कहा, सदन के अंदर वेल (सभापति के आसन के सामने) बहुत पवित्र होता है। उसके अंदर आना ही मर्यादा भंग होता है। लेकिन मंगलवार को जो कुछ हुआ उसने इतना परेशान कर दिया कि वह रात भर सो नहीं सके।

नायडू ने कहा, सदन में कृषि पर चर्चा होनी थी। सदस्य व्यापक चर्चा कर सकते थे लेकिन अवरोध पैदा किया गया। कुछ लोगों के बीच अवरोध पैदा करने में आगे दिखने की प्रतिस्पर्धा हो गई है। यह घातक है। यह सदस्यों को ही तय करना है कि वे बेस्ट सांसद बनना चाहते हैं या सबसे बड़ा अवरोधक। अगर यह मानसिकता नहीं बदली तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो सकता है। माना जा रहा है कि सदन में हंगामा करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

कोविशील्ड व कोवैक्सीन की मिक्स डोज पर अध्ययन को हरी झंडी

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत के दवा नियामक ने कोरोना रोधी टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज पर अध्ययन करने को अपनी मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कालेज 300 स्वास्थ्य वालंटियर पर यह अध्ययन करेगा।

▶ तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कालेज में 300 लोगों पर होगा परीक्षण

केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की विशेषज्ञ समिति ने 29 जुलाई को ही इस अध्ययन को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। इस अध्ययन का मकसद यह आकलन करना है कि क्या किसी एक ही व्यक्ति को एक डोज कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन की दी जा सकती है। अभी पूर्ण टीकाकरण में एक ही वैक्सीन की दो डोज लगाई जाती हैं।

हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने 98 लोगों पर इसी तरह का अध्ययन किया था, इनमें 18 लोग ऐसे थे, जिन्हें उप्र के सिद्धार्थनगर जिले में पहली डोज कोविशील्ड की लगाने के बाद दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई थी। इस अध्ययन के नतीजों में मिक्स डोज के नतीजे बेहतर आए थे और इससे एक ही वैक्सीन की दो डोज की तुलना में मजबूत प्रतिरक्षा पाई गई थी।

आइसीएमआर ने अपने अध्ययन में यह भी पाया था कि मिक्स डोज सुरक्षित है और उसके प्रतिकूल प्रभाव भी एक ही वैक्सीन की दो डोज की तरह ही हैं। आइसीएमआर ने भी मिक्स डोज पर और अध्ययन करने का सुझाव दिया था।

केरल में हालात बेकाबू, ओणम से पहले सख्त लाकडाउन लागू पेज>>6

'हिंसा के कारण भागे परिवारों को सुरक्षा के साथ लाएं घर वापस'

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट ने डायमंड हार्बर पुलिस को 45 दिनों में हिंसा की घटनाओं पर रिपोर्ट भी जमा करने को कहा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य प्रशासन को बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण घर छोड़कर भागने को विवश हुए डायमंड हार्बर के कई परिवारों को पूरी सुरक्षा के साथ घर लाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने वहां हुई हिंसा की घटनाओं पर 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी जमा करने को कहा है।

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा के चलते भाजपा का समर्थन करने वाले कई परिवार घर छोड़कर भाग गए थे। स्थानीय आठ वाशिंदों ने इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया था, जिस पर हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने डायमंड हार्बर पुलिस को पूरी सुरक्षा के साथ उन परिवारों को उनके घर लाने का निर्देश दिया है। साथ ही हिंसा की घटनाओं में 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है।

मजार-ए-शरीफ से भारत ने अपने 50 नागरिक निकाले

- अफगानिस्तान को भारत से मिले हेलीकाप्टर पर तालिबान का कब्जा
- भारत ने पड़ोसी मुल्क को तोहफे में दिए थे चार हेलीकाप्टर

काबुल, आइएएनएस : अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात और मजार-ए-शरीफ को तालिबान के चारों ओर से घेरने के बाद भारत ने वहां से अपने पचास नागरिक सुरक्षित निकाल लिए हैं। भारत ने इसके लिए विशेष विमान मजार-ए-शरीफ भेजा था। उधर एएनआइ के अनुसार, कुंदुज एयरबेस पर तालिबान ने एक एमआइ-35 हेलीकाप्टर पर कब्जा कर लिया। समझा जाता है यह हेलीकाप्टर अफगानिस्तान को भारत से तोहफे के तौर पर मिले चार हेलीकाप्टरों में से एक है।

नई दिल्ली पहुंचने वालों में नागरिकों के साथ राजनयिक भी हैं। भारत ने मजार-ए-शरीफ में वाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यहां से विशेष विमान के जाने से पहले महावाणिज्य दूत ने वहां फंसे नागरिकों को ट्वीट कर सुरक्षित निकलने की सूचना दी थी। मदद के लिए फोन नंबर भी जारी किए गए थे। भारत ने अफगानिस्तान में बाकी बचे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्हें तत्काल अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दी गई है। अमेरिका और ब्रिटेन भी अफगानिस्तान से अपने नागरिक सुरक्षित बाहर निकालने में लगे हैं। ज्ञात हो, पांच लाख की आबादी वाले मजार-ए-शरीफ पर कब्जे को लेकर अफगान सेना व तालिबान के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। अफगानिस्तान में करीब डेढ़ हजार भारतीय नागरिक हैं।

इस बीच एएनआइ से मिली खबर के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कहा गया है कि तालिबान ने कुंदुज एयरबेस पर एक एमआइ -35 हेलीकाप्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। भारतीय रक्षा बलों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी से इन्कार करते हुए कहा कि वे अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।

सूत्रों ने कहा कि तालिबान द्वारा जब्त हेलीकाप्टर का नंबर 123 है जो भारत द्वारा उपहार में दिए गए हेलीकाप्टरों जैसा है। ये चारो गनशिप 2016 में पठानकोट एयरबेस पर मौजूद थे, जब आतंकियों ने वहां हमला किया था।

अफगानिस्तान में संघर्ष जारी, काबुल की तरफ से तेजी से बढ़ा रहा तालिबान पेज>>11

किन्नौर में पहाड़ टूटने से 10 की मौत, 13 घायल

30 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका

- आइटीबीपी, हिमाचल पुलिस और एनडीआरएफ के जवान राहत व बचाव कार्य में जुटे

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार को पहाड़ टूटने से मलबे की चपेट में आकर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रेट्र

समर नेगी, किन्नौर

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पांच (शिमला-किन्नौर मार्ग) पर रिकांगपिओ के पास अचानक पहाड़ टूट गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे छह छोटे वाहनों के साथ ही सवारियों से भरी एक बस मलबे की चपेट में आ गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि, 13 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन 30 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। 24 सवारियां लेकर जा रही बस और एक जीप नहीं मिली है। माना जा रहा है कि दोनों वाहन मलबे के साथ सतलुज नदी में जा गिरे हैं।

जिला मुख्यालय से करीब 61 किमी दूर हुए हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस व राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान मौके पर पहुंचे और मलबे से लोगों को निकालने में जुट गए। जिला उपायुक्त आबिद हुसैन भी मौके पर पहुंच गए। प्रशासन ने रामपुर से शिमला तक के अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा। मलबे में दबे यात्रियों के स्वजन भी वहां पहुंच गए। जैसे ही किसी घायल या शव को मलबे से निकाला जाता स्वजन की तलाश में भीड़ आगे आ जाती। रात करीब साढ़े आठ बजे तक सड़क से मलबा हटा दिया गया, पर यातायात बहाल नहीं किया गया था।

पीएम मोदी ने बचाव कार्य के लिए मदद का दिया भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से फोन पर बात कर हादसे की जानकारी ली और बचाव कार्य के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने आइटीबीपी के महानिदेशक को तुरंत मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। सेना से राहत व बचाव के लिए हेलीकाप्टर मांगा है। ठाकुर गुरुवार को घटनास्थल का दौरा करेंगे।

ये जुटे बचाव में पेज>>5

अगर पद भर नहीं सकते तो उन्हें बनाते क्यों हैं : सुप्रीम कोर्ट

सख्त तेवर

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली रहने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, उपभोक्ता आयोगों के खाली पदों को आठ हफ्ते में भरने का दिया आदेश, अगर आदेश के मुताबिक रिक्त पद नहीं भरे गए तो मुख्य सचिवों को तलब करेंगे : कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में खाली पड़े पदों को न भरे जाने पर बुधवार को गहरी नाराजगी जताते हुए पूरे देश में उपभोक्ता आयोगों के खाली सभी पद आठ सप्ताह में भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, अगर तय समय में आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होने वाली अगली सुनवाई में मौजूद रहना होगा। इसी तरह केंद्र सरकार के मामले में उपभोक्ता मामलों के सचिव मौजूद रहेंगे।

पदों के रिक्त रहने के कारण उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा न होने की ओर संकेत करते हुए कोर्ट ने कहा, लोगों में उम्मीद मत जगाओ अगर उसे पूरा नहीं कर सकते। अगर आप पद भर नहीं सकते तो उन्हें बनाते क्यों हैं। पद खाली रहने से शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा है। मामलों का निपटारा करने के लिए पर्याप्त संख्या में लोग चाहिए।

ये निर्देश और टिप्पणियां जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश राय की पीठ ने दिये। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वकील आदित्य नारायण ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कुल सात पद हैं जिसमे से अभी तीन पद खाली हैं। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) अमन लेखी से पूछा कि जब चार पद भरे जा सकते हैं तो बाकी के तीन क्यों नहीं भरे जा रहे। लेखी ने ट्रिब्युनल रिफार्म एक्ट 2021 का हवाला दिया जिसमे चेयरमैन और सदस्यों के कार्यकाल की बात की गई है। कोर्ट ने कहा कि इसका नियुक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। लेखी ने कहा कि वे सरकार से कहेंगे कि जल्दी पद भरें जाएं।

कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में रिक्त पदों को राज्यों की तरह आठ सप्ताह में ही भरें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, वे उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रभाव, जिसमें उपभोक्ता अदालतों का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है, का अध्ययन करके चार सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करे। पीठ ने कहा कि जब लेजिस्लेटिव कमेटी ने बदलाव किये तो उस कानून का क्या प्रभाव होगा इसका अध्ययन होना चाहिए। यह विडंबना सभी कानूनों के साथ है कि आप कभी कानून के प्रभाव का अध्ययन नहीं करते।

न्यायमित्र वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों और अदालतों में खाली पड़े पदों का ब्योरा दिया। जिसके बाद कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के रिक्त पदों को अधिकतम आठ सप्ताह के भीतर भरने का आदेश दिया। साथ ही राज्यों से कहा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वे दो सप्ताह में विज्ञापन निकालें। कोर्ट ने आदेश दिया कि उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि के नियम अगर नोटीफाई नहीं किए गए हैं तो राज्य दो सप्ताह में उन्हें नोटीफाई करें। अगर तय समय में रूल नोटीफाई नहीं होते तो अपने आप ही केंद्र के माडल रूल्स लागू मान लिए जाएंगे। जिन राज्यों ने सेलेक्शन कमेटी गठित नहीं की है वे चार सप्ताह में गठित करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से उपभोक्ता अदालतों के कंप्यूटरीकरण के लिए दिये गए फंड के उपयोग पर भी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है।

122 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा बुधावार को दिल्ली में। गाजियाबाद में 165, नोएडा में 140, ग्रेटर नोएडा में 143, गुरुग्राम में 110 और फरीदाबाद में 122 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 12 अगस्त, 2021

नया कदम ▸ सीएम ने की परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाओं की शुरुआत, ज्यादातर काम घर बैठकर कम्प्यूटर से होंगे

रिश्वतखोरी, लंबी कतारों और दलालों से मिली मुक्ति

केजरीवाल ने कहा, 21वीं सदी के भारत निर्माण की दिशा में बड़ा क्रांतिकारी कदम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आइपी एस्टेट स्थित जोनल परिवहन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग की 33 फेसलेस (पूरी तरह से आनलाइन) सेवाओं की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवहन कार्यालय में ताला लगाकर यह संकेत भी दिया कि अब किसी काम के लिए लोगों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लर्निंग लाइसेंस से लेकर गाड़ी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) बनवाने जैसे परिवहन विभाग के सभी काम अब लोग घर बैठे आनलाइन करवा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह 21वीं सदी के भारत निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। धीरे-धीरे दिल्ली सरकार के सारे विभागों में सब कुछ फेसलेस कर दिया जाएगा। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो बिना दलालों और बिना रिश्वतखोरी के काम कर सके, यह सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम ने कहा कि पहले लाइसेंस बनवाने में बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन हमने यह परेशानी खत्म कर दी है।

उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद दिल्ली के निवासियों को रिश्वतखोरी, लंबी कतारों और दलालों से मुक्ति दिला दी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की।

डोर स्टेप डिलीवरी आफ सर्विसेज में 150 से अधिक सेवाएं : सीएम ने कहा, 'इस समय दिल्ली के कई विभागों की करीब 150 से ज्यादा सेवाएं डोर स्टेप डिलीवरी आफ सर्विसेज के तहत चल रही हैं। आप 1076 पर फोन करो, हमारा एजेंट आपके घर आएगा और वह आपके सारे कागज ले जाएगा। वह आपसे आवेदन फार्म भरवा लेगा, आपसे फीस ले जाएगा और परिवहन कार्यालय आपका काम कराकर आपके घर पर लाइसेंस दे जाएगा।'

दिल्ली में अमेरिका जैसा सिस्टम शुरू, अब देशभर में होगा लागू: मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग अमेरिका से वापस लौट के आने पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताते हैं कि वहां सारे काम घर से ही आनलाइन हो जाते हैं। लेकिन अब आप जब अमेरिका जाएंगे तो कह सकते हैं कि अपने भारत में भी यह सिस्टम शुरू हो गया। दिल्ली में अब केवल आपको परिवहन कार्यालय में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने और गाड़ी की फिटनेस की जांच कराने के लिए ही आना पड़ेगा। मुख्य सचिव विजय देव ने कहा कि परिवहन विभाग के साथ-साथ फेसलेस सेवा को अन्य विभागों में भी लागू किया जाएगा। इसके लिए अन्य विभागों में काम चल रहा है। कुछ विभागों में सेवाएं काफी हद तक आनलाइन हो चुकी हैं। जल्द ही अन्य विभागों में ऑनलाइन सेवा शुरू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आइपी एस्टेट मोटर स्थित अथारिटी कार्यालय पर ताला लगाते हुए। साथ में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और मुख्य सचिव विजय देव (बाएं)। जागरण

ये सुविधाएं मिलेंगी फेसलेस

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सुविधा: ई-लर्निंग लाइसेंस, लाइसेंस का नवीनीकरण, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, नाम-पता बदलवाना, लाइसेंस बदलना, कंडक्टर लाइसेंस प्रदान करना, पीएसवी बैज प्रदान करना, लाइसेंस की डुप्लीकेट कापी बनवाना।

आरसी से जुड़ी सेवाएं: स्वामित्व में बदलाव, आरसी की डुप्लीकेट कापी निकालना, पता बदलना आरसी विशेष, एमवी कर संग्रह।

परमिट सेवा: नया परमिट, परमिट का नवीनीकरण, डुप्लीकेट कापी, किसी अन्य के नाम पर ट्रांसफर करना और परमिट को छोड़ना।

ऐसे करना होगा आवेदन

आवेदक वेबसाइट transport.delhi.gov.in के जरिये किसी भी सेवा के लिए आनलाइन आवेदन करेगा। आवेदन के दौरान उसका आधार कार्ड भी जरूरी होगा। इसके बाद स्वतः ही फार्म में आवेदक का नाम, जन्म तिथि, पता, अभिभावक या पिता का नाम, आवेदक की फोटो रजिस्टर्ड हो जाएगी। इस तरह पर्सनल डिटेल में किसी भी तरह का फेरबदल किया जाना संभव नहीं होगा। इसके साथ आवेदक को फिजिकल फिटनेस संबंधी घोषणा आनलाइन करनी होगी। इस नई व्यवस्था में आवेदक को आनलाइन फीस जमा करने पर एसएमएस के माध्यम से पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। आवेदन सबमिट होते ही आवेदक को एसएमएस के माध्यम से आवेदन नंबर प्राप्त हो जाएगा।

लर्निंग लाइसेंस के लिए होगा आनलाइन टेस्ट

आवेदक को अपने कम्प्यूटर पर एक टेस्ट देना होगा, जिसमें 20 सवाल पूछे जाएंगे। सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक संकेतों से संबंधित इन प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा। दस में से छह नंबर पाने वाले आवेदक को पास माना जाएगा। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस स्वतः आनलाइन जारी हो जाएगा, जो आवेदक द्वारा प्रिंट किया जा सकेगा।

दिल्ली सरकार ने चार अथारिटी कार्यालय किए बंद

सरकार द्वारा 33 परिवहन सेवाओं के फेसलेस करते ही दिल्ली के चार अथारिटी कार्यालय बुधवार से बंद हो गए। इनमें सराय काले खां, आइपी एस्टेट, वसंत विहार और जनकपुरी शामिल हैं। अब ये कार्यालय साधारण सुविधा केंद्र के रूप में काम करेंगे। जिन कार्यालयों को बंद किया गया है, उनसे संबंधित सेवाओं को दूसरे जोनल दफ्तरों के साथ अटैच किया गया है। आइपी एस्टेट और सराय काले खां कार्यालय को साउथ जोन के साथ अटैच किया गया है। जनकपुरी को राजा गार्डन ट्रांसपार्ट अथारिटी के साथ और वसंत विहार को द्वारका के साथ अटैच किया गया है।

केजरीवाल–सिसोदिया को समेत नौ विधायकों को क्लीनचिट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अंशु प्रकाश से मारपीट मामला

▸ 11 विधायकों को बनाया गया था आरोपित, आप विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल पर आरोप तय करने का दिया आदेश

वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत नौ विधायकों को क्लीनचिट दे दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री का आचरण उन पर लगाए गए आरोपों के अनुरूप नहीं था। हालांकि अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। अदालत ने दोनों पर लोकसेवक के सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में बाधा डालने, उनको चोट पहुंचाने समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने के लिए कहा है।

अदालत ने केजरीवाल व सिसोदिया के अलावा आप विधायक राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज गोविंद, राजेश गुप्ता, मदन लाल और दिनेश मोहनिया को आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि पेश किए गए साक्ष्यों के अनुसार गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, आपराधिक साजिश रचने, अपराध के लिए उकसाने का मामला इन लोगों के खिलाफ नहीं बनता है।

अदालत ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान कुछ अनहोनी हुई है तो बैठक को गैरकानूनी नहीं बताया जा सकता है। वह भी तब जब मुख्यमंत्री का आचरण बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं है। यह भी नहीं कि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री समेत अन्य विधायकों ने आपराधिक साजिश के तहत काम किया हो या किसी भी तरह से उकसाने, कथित अपराध करने के लिए एकत्रित हुए हों।

केजरीवाल ने अमानतुल्लाह व जरवाल को रोका था : अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमानतुल्लाह और जरवाल को अपराध करने से रोका था। अदालत ने नोट किया कि केजरीवाल दोनों विधायकों के आचरण से खुश नहीं थे और बैठक के बाद परेशान थे। अदालत ने कहा कि फिर ऐसा व्यक्ति (केजरीवाल) किसी भी आपराधिक साजिश का हिस्सा कैसे बन गया, जैसा कि कथित मारपीट या अन्य अपराध में आरोप लगाया गया है।

राशन वितरण के मुद्दे को लेकर उपस्थित हुए थे विधायक : 59 पेज के अपने फैसले में अदालत ने कहा कि बैठक में उपस्थित सभी व्यक्ति अपराधी नहीं थे। वे चुने हुए प्रतिनिधि थे और मुख्यमंत्री के निर्देश पर घर-घर राशन वितरण योजना के मुद्दे को लेकर एक बैठक में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे। ऐसे में यह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए साजिश के सिद्धांत को मजबूत नहीं करता है जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है।

ये है मामला

तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने शिकायत दी थी कि 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में अमानतुल्लाह खान व प्रकाश जारवाल ने उन पर हमला किया था। उन्होंने केजरीवाल व सिसोदिया समेत कुल 11 विधायकों को आरोपित बनाया था। इस मामले में सभी आरोपित विधायक जमानत पर थे।

मुख्यमंत्री बोले, सत्य की जीत हुई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ तथाकथित मारपीट मामले में अदालत द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित नौ विधायकों के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने पर केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताया। अदालत के फैसले के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में ये आज न्याय और सत्य की जीत का दिन है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेसवार्ता कर कहा कि जाहिर हो गया है कि दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार को नाकाम करने के लिए यह साजिश केंद्र सरकार और भाजपा के इशारों पर रची गई थी।

सिसोदिया ने कहा कि अब जबकि सत्य सबके सामने है, तो ऐसे में केंद्र सरकार और भाजपा दिल्ली के सीएम से और उनको चुनने वाली जनता से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार को पहले दिन से ही नाकाम करने के लिए झूठी और मनगढ़ंत साजिशें की जा रही हैं। सिसोदिया ने कहा कि अपनी ईमानदारी और गुड-गवर्नेंस माडल के कारण अरविंद केजरीवाल देश में लोकप्रिय हो रहे हैं। केजरीवाल की लोकप्रियता से भाजपा डरने लगी है। इसलिए दिल्ली पुलिस का प्रयोग कर उनके खिलाफ फर्जी एफआइआर की गई। उनके दफ्तर, घर में छापा मारा गया। आजादी के बाद यह पहला वाक्या था जब एक सीएम के घर और दफ्तर पर इस तरह से छापे मारे गए।

हरिद्वार में होगा दिल्ली निगम चुनाव की रणनीति पर चिंतन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ दिल्ली भाजपा की 23 से दो दिवसीय कोर कमेटी की बैठक

दिल्ली के नगर निगमों में सत्तारूढ़ भाजपा अपना किला बचाए रखने के लिए रणनीति राष्ट्रीय राजधानी से दूर उत्तराखंड में तैयार करेगी। राज्य संगठन की कोर कमेटी की दो दिवसीय बैठक देव नगरी हरिद्वार में 23 व 24 अगस्त को है। इसे चिंतन बैठक नाम दिया गया है। वैसे, यह पहली बार है, जब प्रदेश कार्यकारिणी की इस तरह की बैठक दिल्ली से बाहर हो रही है। अमूमन ये उच्चस्तरीय बैठकें पार्टी के प्रदेश कार्यालय या दिल्ली के किसी हिस्से में होती हैं।

मामले के जानकार लोगों के मुताबिक अगले वर्ष नगर निगमों के आम चुनाव में किला बचाए रखने के लिए आक्रामक तरीके से कार्य करने की रणनीति तैयार करने का श्रीगणेश इसी माह से होने जा रहा है। इसके लिए पार्टी की दो दिन की कोर कमेटी की बैठक हरिद्वार में होगी, जहां पर केंद्रीय संगठन के साथ प्रदेश संगठन के उच्चाधिकारी निगम चुनाव को लेकर रणनीति पर समग्र मंथन करेंगे। साथ ही इसमें प्रदेश संगठन की आगामी कार्ययोजना तैयार होगी।

प्रदेश के एक पदाधिकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले केंद्रीय संगठन की ओर से इस संबंध में निर्देश आए हैं कि जिन राज्यों में अगले छह माह या एक वर्ष में चुनाव होने हैं। उन राज्यों की इकाई को अपनी रणनीति तैयार करनी है। इसी के तहत यह बैठक आयोजित की जाएगी। अगले वर्ष मार्च माह में तीनों नगर निगम के आम चुनाव होने हैं। ऐसे में 15 साल से लगातार सत्ता में काबिज भाजपा के लिए किला बचाए रखना महत्वपूर्ण है। ऐसे में पार्टी उसी हिसाब से तैयारी करना चाहती है।

खतरे की घड़ी में सेफ हाउस में महफूज रहेंगे पीएम

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

▸ पीएम आवास से लालकिला तक हर दो किमी पर बनाए सेफ हाउस

▸ स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस कर रही सुरक्षा के कड़े इंतजाम

स्वतंत्रता दिवस समारोह पर राजधानी की सुरक्षा वैसे तो हर साल बेहद कड़ी होती है, लेकिन इस बार सुरक्षा को लेकर और अधिक सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास से लालकिले तक हर दो किलोमीटर पर न सिर्फ एक सेफ हाउस बनाने का निर्णय लिया है।

दरअसल, स्वतंत्रता दिवस पर पहले सात लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से लेकर लालकिला तक 11.2 किलोमीटर के बीच कोई सेफ हाउस नहीं बनाया जाता था। लालकिला के अंदर सिर्फ एक सेफ हाउस होता था, लेकिन इस साल पहली बार ड्रोन हमले के संभावित खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास से लालकिले तक हर दो किलोमीटर पर एक सेफ हाउस बनाया गया है,यानी कुल पांच सेफ हाउस बनाए गए हैं। इन्हें अत्यंत गोपनीय तरीके से ऊंची इमारतों में बनाया गया है, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में प्रधानमंत्री को सुरक्षित किया जा सके।

सूत्रों के मुताबिक उक्त सेफ हाउस में बेहतर इलाज से लेकर हर तरह की सुविधाएं होंगी। इसमें उपलब्ध सुविधाओं को परखने के लिए अक्सर रक्षा मंत्रालय व दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां माकड्रिल कर रही है। सेफ हाउस में चाक चौबंद बंदोबस्त किए जा रहे हैं।

रास्ते में खड़े किए पत्थरों से लदे कंटेनर : 26 जनवरी की घटना से सबक लेकर इस बार रास्ते में पत्थरों से लदे लोके के कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। इन सभी कंटेनरों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह वाले दिन कमांडो व पैरा मिलिट्री के शूटरों की तैनाती की जाएगी। यह कंटेनर इस तरह से खड़े किए गए हैं, कि ट्रैक्टर या कोई अन्य वाहन इन्हें हटाकर आगे न बढ़ सके।

लालकिले पर लगाए गए दो एंटी ड्रोन रडार

लालकिले पर पहली बार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा दो एंटी ड्रोन रडार लगाए गए हैं। अगर कोई संदिग्ध ड्रोन लालकिले के तीन-चार किलोमीटर के दायरे में दिखाई देगा तो डीआरडीओ के जवान उसे वहीं जाम कर जमीन पर गिरा सकेंगे। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस बार सीसीटीवी कैमरे भी हर बार की तुलना में काफी अधिक लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री जिन मार्गो से लालकिला पर जाएंगे और वापस लोक कल्याण मार्ग जाएंगे। उन रूटों के अलावा लालकिला के चारों तरफ जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों पर निगरानी के लिए दस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।

साधु नरेशानंद पर ही हमले के लिए डासना देवी मंदिर में आए थे हमलावर

आशुतोष गुप्ता, गाजियाबाद

▸ हमलावरों को मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में थी पूरी जानकारी

▸ गारद में तैनात सिपाही के ड्यूटी से हटते ही दिया गया वारदात को अंजाम

गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में मंगलवार सुबह साधु नरेशानंद पर हमला साजिशन हुआ था। हमलावरों को मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर में तैनात गारद की ड्यूटी बदलने के समय की पूरी जानकारी थी। यही कारण है कि उन्होंने हमले के लिए वह समय चुना जब सभी गहरी नींद में थे और गारद में पोस्ट पर तैनात सिपाही नहीं था। घटना में मंदिर के किसी व्यक्ति के भी शामिल होने का अंदेशा है। पुलिस जांच में कई और अहम जानकारी भी सामने आ रही हैं। वहीं, नरेशानंद की हालत अभी भी यशोदा अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है।

दो साल पहले भी मंदिर में आए थे नरेशानंद : पुलिस के अनुसार नरेशानंद करीब दो साल पहले भी डासना देवी मंदिर में आकर रुके थे। इस बार वह सात अगस्त को मंदिर में आए थे। वह आठ अगस्त को दिल्ली जंतर-मंतर पर धरने में भी शामिल हुए थे। संभावना यह भी है कि वह यहां काफी लोगों से परिचित भी हो सकते हैं। अंदेशा है कि हमले का उद्देश्य नरेशानंद की ही हत्या करना था।

घात लगाकर किया गया हमला : घटनास्थल की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि नरेशानंद पर हमला घात लगाकर किया गया। हमलावर को मंदिर की सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी थी। उसे पता था कि मुख्यद्वार पर पीएसी के जवान व भीतर गारद है। हमलावर को यह भी पता था कि मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हैं और मुख्यद्वार पर पुलिस द्वारा लगाए गए कैमरे चालू हैं। इसके चलते वह मुख्यद्वार के कैमरों से बचकर निकला और दीवार फांदकर मंदिर में प्रवेश किया। दो बजे गारद की पोस्ट बदलती है। सिपाही धनेश ने दो बजे पोस्ट संभाली। हमलावर धनेश के पोस्ट से हटने का इंतजार कर रहा था। रात साढ़े तीन बजे धनेश अपनी पोस्ट छोड़कर लघुशंका करने गया। इसी दो से तीन मिनट के भीतर हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।

लापरवाही बरतने पर दो पुलिसकर्मी निलंबित

मसूरी थाना क्षेत्र के डासना देवी मंदिर में हुए साधु नरेशानंद पर कातिलाना हमले के मामले में एसएसपी अमित पाठक ने गारद में तैनात दो पुलिसकर्मियों की लापरवाही उजागर होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ उन्होंने विभागीय जांच भी बैठाई है। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि मंदिर परिसर में गारद जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी के समय दोनों पुलिसकर्मियों ने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। इसके चलते मुख्य आरक्षी अरविंद कुमार व आरक्षी धनेश सिंह को निलंबित किया गया है।

'नीतियों के उल्लंघन में लाक किया था राहुल का अकाउंट'

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

दुष्कर्म व हत्या मामला

▸ बच्ची के माता-पिता की तस्वीर पोस्ट करने के मामले पर ट्विटर ने हाई कोर्ट में दी जानकारी

▸ तस्वीर पोस्ट करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई है याचिका

दिल्ली के कैंट क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद नौ वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में उसके माता-पिता की तस्वीर पोस्ट करने पर ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन किया है। इसलिए उनका अकाउंट लाक कर दिया गया था। एक याचिका पर जवाब देते हुए ट्विटर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष कहा कि यह हमारी नीति के खिलाफ है और राहुल द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों को हटा दिया गया है। इस पर मुख्य पीठ ने कहा कि आपने तेजी से जिम्मेदारी भरा काम किया है।

ट्विटर के जवाब के बावजूद याचिकाकर्ता मकरंद सुरेश की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता गौतम झा ने ट्विटर को हलफनामा दायर करने का निर्देश देने पर जोर दिया। इस पर मुख्य पीठ ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर ट्विटर झूठ क्यों बोलेगा और ट्विटर की बात पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर आपका ऐसा बर्ताव है तो हम नोटिस जारी नहीं करेंगे। पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को मामले से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश ने याचिका दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ बाल अधिकार कानून एवं पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बच्ची के स्वजन की तस्वीर सार्वजनिक कर राहुल ने बाल अधिकार कानून व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पाक्सो) के कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध के मामले में पीड़ित बच्ची के स्वजन से जुड़ी जानकारी के सार्वजनिक होने से उनका दर्द और बढ़ जाता है।

शव के अवशेष का अंतिम संस्कार

जासं, नई दिल्ली: दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र में दुष्कर्म व हत्या मामले में बच्ची के शव के बचे हुए अवशेष का पुराना नांगलराया स्थित श्मशान भूमि पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बच्ची के माता-पिता व उनके नजदीकी रिश्तेदार मौजूद थे। उधर, श्मशान भूमि के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि डीडीयू अस्पताल की मोर्चरी में रखा अवशेष पीड़ित पक्ष को सौंप दिया गया। जब अवशेष का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब श्मशान भूमि के बाहर करीब 20 लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये लोग श्मशान भूमि परिसर के भीतर प्रवेश करना चाह रहे थे, लेकिन पीड़ित पक्ष ने इसके लिए उन्हें सहमति नहीं दी।

श्मशान भूमि परिसर की ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई

जासं, नई दिल्ली : नौ साल से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फोरेंसिक टीम नमूने एकत्र कर रही है, जिन्हें जांच के लिए जल्द ही गुजरात के गांधीनगर स्थित लैब में भेजा जाएगा। बुधवार को क्राइम ब्रांच ने श्मशान भूमि परिसर की ड्रोन से वीडियोग्राफी भी कराई। दो दिन पहले बच्ची के माता-पिता के भी बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सूत्रों की मानें तो बयान में स्वजन ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने बताया कि आरोपितों ने बच्ची के जल्द दाह संस्कार कर देने का दबाव बनाया, जिससे उन्होंने ऐसा किया। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक मामले में गिरफ्तार श्मशान गृह के मुख्य पुजारी राधे श्याम सहित सलीम, कुलदीप और लक्ष्मी नारायण का मंगलवार को सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल करवाकर यह पता करने की कोशिश की गई कि उनके शरीर पर कहीं ताजे चोट के निशान तो नहीं हैं?

मिशन एडमिशन

वार्ड कोटा की बढ़ी हुई सीटों पर पहली बार होंगे डीयू में दाखिले

प्रत्येक कालेज में वार्ड कोटा के तहत आठ-आठ सीटें दिल्ली विवि के शिक्षकों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए होंगी आरक्षित

संजीव कुमार मिश्र, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई हैं। डीयू में पहली बार वार्ड कोटा की बढ़ी हुई सीटों के तहत दाखिले हो रहे हैं। प्रत्येक कालेज में वार्ड कोटा के तहत आठ-आठ सीटें डीयू शिक्षकों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। छात्रों की सुविधा के लिए डीयू फार्म में सभी कालेज स्वतः चयनित होंगे।

डीयू दाखिला समिति के चेयरपर्सन प्रो. राजीव गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष बढ़ी हुई सीटों के तहत दाखिले होंगे। डीयू प्रशासन ने बताया कि वार्ड कोटा की सीटें गत वर्ष बढ़ाई गई थीं। उस समय दाखिला प्रक्रिया लगभग समाप्त होने वाली थी इसलिए स्नातक में दाखिले नहीं हो पाए थे। अब शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दाखिले में बढ़ी हुई सीटें लागू की गई हैं। वार्ड कोटे के तहत दाखिला लेने जा रहे एक पाठ्यक्रम के चार सौ में से 16 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इनमें आठ सीटें शैक्षणिक, जबकि बाकी आठ गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं। इनमें भी चार सीटें मेरिट, जबकि चार सीटें प्रवेश परीक्षा के आधार पर होने वाले दाखिले के लिए तय की गई हैं।

विभिन्न कालेजों में पाठ्यक्रम की सीटों के अनुसार वार्ड कोटा तय किया जाएगा। अधिकतम 16 सीटें कोटे के तहत आरक्षित होंगी। यदि कालेज में किसी पाठ्यक्रम में चार सौ या उससे ऊपर सीटें होंगी तो 16 सीटें आरक्षित होंगी। यदि 201 से 399 सीटें होंगी तो 12 सीटें, 101 से 200 सीटों पर आठ, 51 से 100 सीटों पर चार और 50 सीटों तक दो सीटें वार्ड कोटे के तहत आरक्षित होंगी, जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दो सीटें आवंटित की जाएंगी। इनमें एक मेरिट, जबकि दूसरी प्रवेश परीक्षा के लिए आरक्षित होंगी।

डीयू में गत वर्ष अगस्त में वार्ड कोटा की सीटें बढ़ाई गई थीं। डीयू ने 1996 से 24 साल बाद कोटा बढ़ाया था। इसके पहले डीयू के एक कालेज में सिर्फ छह सीटें वार्ड कोटा के तहत आरक्षित थीं। तीन सीटों पर शैक्षणिक, जबकि तीन सीटें गैरशैक्षणिक कर्मचारियों के बच्चों को दाखिला दिया जाता था।

स्वतः चयनित होंगे कालेज: आवेदन फार्म भरते समय कोई छात्र वार्ड कोटा का विकल्प चुनता है तो सभी कालेज स्वतः चयनित हो जाएंगे। हां, यदि कोई छात्र किसी कालेज का विकल्प हटाना चाहता है तो वह आसानी से कर सकता है। वहीं कई छात्रों ने आरोप लगाया कि डीयू प्रास्पेक्टस में वार्ड कोटा की जगह ईसीए दाखिले की जानकारी दी गई है। डीयू ने कहा है कि वह इसका संज्ञान लेगा।

डीयू के नार्थ कैंपस में नया कोविड सेंटर शुरू

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली विवि के नार्थ कैंपस में नया कोविड सेंटर बनाया गया है। परिसर स्थित कान्फ्रेंस सेंटर को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है। डीयू के कार्यवाहक कुलपति प्रो. पीसी जोशी ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कोविड सेंटर शुरू किया गया है। इसमें बेड के साथ आक्सीजन कंसंट्रेटर भी होंगे। नार्थ कैंपस में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में पहले से ही कोविड केंद्र मौजूद हैं। इस परिसर में दो आक्सीजन प्लांट, जबकि विज्ञान विभाग के पास एक आक्सीजन प्लांट हैं। जल्द एक अन्य आक्सीजन प्लांट भी लगाया जाएगा। डीयू प्रशासन ने बताया कि वर्तमान में दीन दयाल उपाध्याय कालेज व लक्ष्मीबाई कालेज में आइसोलेशन सेंटर खोले गए हैं। लक्ष्मीबाई में 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर मौजूद है। तीसरी लहर के संभावित खतरे से निपटने के लिए डीयू छात्रावासों व स्टेडियम में कोविड सेंटर खोलेगा। जानकी देवी मेमोरियल कालेज, हंसराज कालेज के छात्रावास में 100-100 बेड के कोविड सेंटर खोले जाएंगे।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा, नई फ्लाइट को तैयार हिंडन एयरपोर्ट

सौरभ पांडेय, साहिबाबाद

दिल्ली के बाद एनसीआर के दूसरे एयरपोर्ट हिंडन से भी अब लोगों को लखनऊ, बनारस व प्रयागराज जैसे शहरों के लिए सीधी फ्लाइट मिल सकेगी। एयरपोर्ट अथारिटी ने हिंडन से उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। कर्मचारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उम्मीद है कि अगले दो माह में तीनों स्थानों के लिए फ्लाइट उड़ाने का ट्रायल शुरू हो सकता है।

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के तहत हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़, कलबुर्गी व हुबली के लिए फ्लाइट शुरू की गई थी। पिथौरागढ़ की फ्लाइट कोविड के पहले लाकडाउन के बाद से लगातार निलंबित चल रही है। अब एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है।

लखनऊ, बनारस व प्रयागराज को प्राथमिकता: एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा व आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज व बनारस से आए लोग रहते हैं। वे लगातार अपने गृह जनपदों को जाते हैं। ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट के बोझ को कुछ कम करने के लिए भारत सरकार की ओर से लखनऊ, प्रयागराज व बनारस के लिए जल्द ही फ्लाइट शुरू होगी। सितंबर के अंत तक इन फ्लाइट का ट्रायल भी कर लिया जाएगा।

अभी छह दिन मिलती है विमान सेवा: हिंडन एयरपोर्ट पर वर्तमान में कर्नाटक के हुबली व कलबुर्गी के लिए दो फ्लाइट सप्ताह में छह दिन उड़ती हैं। लखनऊ के लिए सेवा सातों दिन मिलेगी।

3,623 करोड़ रुपये से अधिक की आय दिखाई है भाजपा ने वर्ष 2019-20 में। पार्टी को चुनावी बांड से 2,555 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

राज्यसभा में सरकार पर हमलावर रहा समूचा विपक्ष

ओबीसी बिल ▸ जातिगत जनगणना और आरक्षण सीमा बढ़ाने पर दिया जोर

केंद्रीय संस्थानों में नहीं भरे जा रहे ओबीसी के आरक्षित पद : सपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ओबीसी पर राज्यों के अधिकार बहाल करने संबंधी 127वें संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में बुधवार को चर्चा के दौरान विपक्ष ने जबरदस्त हमलावर तेवर अपनाए। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार से पूछा कि फिर पिछड़ी जातियों की जनगणना से सरकार पीछे क्यों हट रही है? ज्यादातर विपक्षी सदस्यों ने सामाजिक जनगणना कराने और आरक्षण की 50 फीसद की सीमा हटाने की मांग रखी।

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि राज्यों को जातियों की सूची बनाने का अधिकार होने का फायदा तब तक प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का उन्हें अधिकार नहीं मिल जाता। संविधान

संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा में बोलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी। एएनआइ

संशोधन विधेयक-2021 पर चर्चा करते हुए प्रोफेसर यादव ने आशंका जताई कि ओबीसी कोटे से तीन प्रमुख जातियों को बाहर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यादव, कुर्मी और गुर्जर को सूची से निकाला जा सकता है और यह काम राज्य विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है। सपा नेता ने कहा कि जातिगत जनगणना में उनकी शिक्षा, मकान और अन्य सभी तरह की जानकारियां जुटाई जानी चाहिए, ताकि उसके अनुरूप नीतियां बनाईं जा सकें। सदन का ध्यान खींचते हुए उन्होंने बताया कि देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को भरने में जबरदस्त कोताही बरती जा रही है। इस बारे में उन्होंने विस्तार से आंकड़े भी पेश किए।

जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य रामनाथ ठाकुर ने कहा कि सरकारी विभागों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों को भरने की तत्काल पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में ओबीसी वर्ग के लोगों के कल्याण की नीतियां तभी बन सकती हैं, जब उनकी जनगणना समय पर कराई जाए। राजद नेता मनोज कुमार झा और राकांपा की वंदना चौहान ने भी पिछड़े वर्ग के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी जनगणना कराने पर जोर दिया।

आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि आरक्षण सीमा को नहीं बढ़ाया गया तो यह विधेयक महज दिखावा बनकर रह जाएगा। इसे आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लाया गया है। शिरोमणि अकाली दल के सरदार बलविंदर सिंह भुंडर ने कहा, 'वर्ष 1947 के बाद यह पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिए हैं।'

डर पैदा करने और समाज तोड़ने का काम करती है सपा : प्रधान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ओबीसी विधेयक पर चर्चा के दौरान साधा निशाना

ओबीसी विधेयक को लेकर जहां हर ओर से राजनीतिक दांव खेलने की कोशिश रही, वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला किया। चर्चा के दौरान प्रधान ने कहा कि सपा डर पैदा कर राजनीति करती है। समाज को तोड़ने का काम करती है, जबकि भाजपा हर किसी को जोड़ती है और हर जाति को उसका अधिकार देने के लिए प्रयासरत है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मुहाने पर है। यही कारण है कि सपा भी जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा 50 फीसद से ऊपर ले जाने की मांग कर रही है। ऐसे में सरकार की ओर से बोलते हुए प्रधान सपा पर केंद्रित रहते हुए अपने गृह राज्य ओडिशा की राजनीति भी साधी। राज्यसभा में चर्चा के दौरान

धर्मेंद्र प्रधान जागरण आर्काइव

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार के पहले 10 साल तक संप्रग की सरकार थी, जिसे समाजवादी पार्टी का भी समर्थन था। फिर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्रों तक ओबीसी को आरक्षण देने से किसने मना किया था। अब मोदी सरकार इसे लागू कर रही है तो इन्हें संदेह हो रहा है। उन्होंने कहा का राम गोपाल यादव की पार्टी की राजनीति है- डर पैदा करो, राज करो। विपक्षी दलों से उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार के काल में किस जाति का आरक्षण खत्म हुआ है जो डराया जा रहा है। राम गोपाल पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वह भी पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़े हैं और मैं पेट्रोलियम मंत्री रह चुका हूं। उस वक्त भी जो 11 हजार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी गई उसमें एससी एसटी के हक के अलावा ओबीसी नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 2852 डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की गईं। प्रधान ने ओडिशा की राजनीति भी साधी और कहा कि कई राज्य 50 फीसद की सीमा से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन ओडिशा सरकार कहती है केंद्र सरकार ने हाथ बांध रखे हैं, जबकि वही राज्य मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया था।

बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाने पर केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने पीएम को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के मतुआ महासंघ के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बर घटनाओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाने का भी उन्होंने पत्र में जिक्र किया है।

गौरतलब है कि गत दिनों बांग्लादेश में खुलना जिले के शियाली गांव में मतुआ समुदाय के अराध्य श्रीश्री हरिगुरु चांद ठाकुर के मंदिर समेत कई हिंदू मंदिरों में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं और घरों में तोड़फोड़ की गई थी। कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में हरि नाम जाप से नाराज स्थानीय मुस्लिमों ने हिंदुओं के घरों, दफ्तरों और मंदिरों को निशाना बनाया है। अब केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जान खतरे में है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम पर आरोप लगाए गए हैं, जिसके तार सीधे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेस इंटेलिजेंस (आइएसआइ) से जुड़े हैं।

महिला स्व-सहायता समूहों से आज बात करेंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) से प्रोत्साहित महिला स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान देश भर से स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की सफलता की कहानी का संक्षिप्त विवरण तथा कम व छोटी जोत वाली खेती से पैदा होने वाली आजीविका पर पीएम एक पुस्तिका भी जारी करेंगे। पीएम इस अवसर पर चार लाख स्व-सहायता समूहों को 1,625 करोड़ की सहायता राशि भी जारी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीएमएफएमइ (पीएम फार्मलाइजेशन आफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज) योजना के तहत आने वाले 7,500 स्व-सहायता समूहों को 25 करोड़ की सीड मनी भी जारी करेंगे। इसी तरह मिशन के तहत आने वाले 75 एफपीओ (कृषि उत्पादक संगठनों) को प्रधानमंत्री 4.13 करोड़ की धनराशि भी प्रदान करेंगे।

बरकरार रह सकता है पूर्व केंद्रीय मंत्री निशंक का मौजूदा बंगला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री होने की नाते है उनकी पात्रता

▸ निशंक ने लोकसभा अध्यक्ष और शहरी विकास मंत्री पुरी से की बात

मोदी कैबिनेट में बदलाव के बाद लुटियंस जोन के बंगलों में भी बदलाव की कवायद तेज हो गई है। कैबिनेट में शामिल किए गए नए मंत्रियों को नए बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। जिन चेहरों को कैबिनेट मंत्री पद से मुक्त किया गया है उन्हें अपेक्षाकृत छोटे बंगलों में जाना होगा। उन्हें नोटिस भी भेजा जा चुका है, लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक अपवाद होंगे। वे पद से हटने के बावजूद टाइप आठ श्रेणी के बंगले की योग्यता रखते हैं। ऐसे में नए कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को संभवतः किसी और बंगले की तलाश करनी पड़ेगी।

नई शिक्षा नीति को सर्वसम्मति के साथ लागू करवाने में सफल रहे निशंक ने स्वास्थ्य के आधार पर पद से इस्तीफा दिया था। बताते हैं कि इस्तीफे में ही उन्होंने इसका भी जिक्र किया था कि डाक्टरों की सलाह पर वे कुछ महीने काम करने में असमर्थ हैं और नहीं चाहते हैं कि शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में कोई देरी हो।

बहरहाल, एक नियम यह भी है कि टाइप आठ के बंगले में केंद्रीय मंत्री ही रहते हैं। निशंक इससे परे हैं, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व

रमेश पोखरियाल निशंक जागरण आर्काइव

राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री में से जो दो पदों पर रहे हैं, वे भी टाइप आठ के पात्र हैं। इसके साथ ही जो आठ बार के सांसद हैं, वे टाइप आठ के बंगलों में रहने के पात्र हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष या फिर चार से सात बार के जो सांसद हैं, वे टाइप सात के बंगलों के लिए पात्र हैं। हालांकि, बंगलों का आवंटन उनकी उपलब्धता के आधार पर तय होता है। मौजूदा समय में लुटियंस जोन में बंगलों की भारी कमी है।

देश में 54 लाख से अधिक फेरी वालों की पहचान

नई दिल्ली, प्रेट्र : 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 54.70 लाख फेरी वालों की पहचान की गई है। इनमें से सबसे ज्यादा 9.87 लाख फेरी वाले उत्तर प्रदेश में हैं। शहरी विकास राज्यमंत्री कौशल किशोर ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि दिल्ली में 79,952 फेरी वालों की पहचान की गई है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में इस संबंध में कोई फेरी व्यवसाय प्रमाणपत्र (सीओवी) जारी नहीं किए गए हैं।

किशोर ने बताया कि फेरी वाले (आजीविका की सुरक्षा एवं फेरी व्यवसाय नियमन) कानून, 2014 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को फेरी वालों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करना होता है तथा सीओवी प्रमाणपत्र जारी करना होता है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से मिली सूचना के अनुसार, देश के 3,084 शहरों में फेरी वालों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फेरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि) योजना के तहत फेरी वालों के 42.92 लाख ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 22.62 लाख को कर्ज दिया गया है। उन्होंने बताया कि फेरी वाले इस योजना के तहत 10,000 रुपये का कर्ज ले सकते हैं जो एक साल के दौरान मासिक किस्तों में अदा किया जा सकता है।

पलायित कश्मीरी हिंदुओं को लौटाई जाने लगीं उनकी पुश्तैनी संपत्तियां

▸ अब तक नौ संपत्तियां उनके मूल स्वामियों को सौंपी गई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार आतंकी हिंसा के कारण राज्य छोड़कर चले गए कश्मीरी हिंदू प्रवासियों की पुश्तैनी संपत्तियों को बहाल करने के लिए कदम उठा रही है। अब तक नौ संपत्तियां उनके असली मालिकों को वापस सौंपी दी जा चुकी हैं। बुधवार को राज्यसभा को इस बात की जानकारी दी गई।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, संरक्षण और संकट बिक्री पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1997 के तहत, जम्मू और कश्मीर में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट अचल संपत्ति के कानूनी संरक्षक हैं। वे प्रवासियों की संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण के मामलों में बेदखली की कार्यवाही पर स्वतः संज्ञान लेते हैं। प्रवासी ऐसे मामलों में खुद भी डीएम से अनुरोध कर सकते हैं। एक प्रश्न

दी जानकारी : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अब तक नौ संपत्तियों को कब्जा मुक्त कर इनके वास्तविक और मूल मालिक को सौंप दिया गया है। राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, कुल 520 प्रवासी प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत नौकरी करने के लिए कश्मीर लौट आए हैं।

एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, संविधान के सभी प्रविधानों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर लागू कर दिया गया है। इसके लिए अनुकूलन आदेशों द्वारा जम्मू-कश्मीर में मौजूदा कानूनों में बदलाव की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के अनुकूलित भूमि कानूनों के अनुसार सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और धर्मार्थ उद्देश्य जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दे सकती है।

तीन साल में भारतीय एनजीओ को विदेश से 49,000 करोड़ रुपये मिले

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने कहा है कि पिछले तीन वर्षों में देश में 18,000 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेश से 49,000 करोड़ रुपये मिले। इनमें से वर्ष 2017-18 में एनजीओ को विदेश से 16,940.58 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 16,525.73 करोड़ रुपये और 2019-20 में 15,853.94 करोड़ रुपये मिले।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बुधवार को एक लिखित जवाब में बताया कि विदेशी अंशदान (नियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने से पहले एफसीआरए बैंक खाते अधिसूचित बैंकों की किसी भी शाखा में खोले जा सकते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान (नियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 में व्यवस्था दी गई है कि किसी विदेशी स्रोत से विदेशी अंशदान पहली बार भेजने या प्राप्त करने के लिए प्रत्येक एफआरसीए एनजीओ द्वारा एफसीआरए खाता अब अनिवार्य रूप से नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में में ही खोला जाना है। स्टेट बैंक ने बताया है कि 31 जुलाई 2021 तक कुल 18377 नामित एफसीआरए खाते खोले गए हैं।

▸ एफसीआरए खाता नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में ही खोला जाना है

तीन साल में पुलिस हिरासत में 348 लोगों की मौत : राय ने एक अन्य लिखित उत्तर में कहा कि तीन साल के दौरान पुलिस हिरासत में 348 लोगों, जबकि न्यायिक हिरासत में 5221 लोगों की मौत हो गई। उप में 2018-2020 में 23 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो गई जबकि न्यायिक हिरासत में 1,295 लोगों की मौत हो गई। राय ने बताया कि मध्य प्रदेश में इस अवधि के दौरान 34 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई जबकि न्यायिक हिरासत में 441 की मौत हुई। बंगाल में पुलिस हिरासत में आठ और न्यायिक हिरासत में 407 की मौत हुई और महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में 27 एवं 370 की मौत न्यायिक हिरासत में हुई।

'पोक्सो के तहत आरोपित किशोरों की आयु सीमा घटाने पर विचार नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने पोक्सो कानून के तहत गंभीर मामलों में शामिल किशोरों के लिए उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 साल करने पर बल नहीं देने का फैसला किया है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि इस आयु वर्ग के किशोरों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त हैं। सरकार ने यह प्रतिक्रिया राज्यसभा सदस्य व कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की एक टिप्पणी पर दी थी।

▸ उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 साल किए जाने के मुद्दे पर सरकार पहले ही दे चुकी है राय

समिति ने कहा था, 'प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल आफेंसेज (पोक्सो) एक्ट के तहत बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं, जहां किशोरों की उम्र कानून लागू होने के लिहाज से तय आयु सीमा से कम रही है। समिति को लगता है कि नाबालिग यौन अपराधियों को यदि सही परामर्श नहीं दिया गया तो वे और अधिक गंभीर और जघन्य अपराध कर सकते हैं। इन प्रविधानों पर पुनर्विचार अहम है।' समिति ने गृह मंत्रालय से कहा है कि इस विषय को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ उठाया जा सकता है। जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया कि बच्चों के संरक्षण तथा अपराध के आरोपित किशोरों के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम-2015 (जेजे अधिनियम) है। यह कानून आरोपित नाबालिगों के मामलों पर फैसला लेने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अधिकार प्रदान करता है। इस पर संसदीय समिति ने कहा कि सरकार की तरफ से जवाब आने के बाद वह मामले पर बल नहीं देना चाहती।

माननीयों के मुकदमे सुन रही अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा की मांगी जानकारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से ब्योरा तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई कर रही विशेष अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को इस बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस एनवी रमना, विनीत सरन और सूर्यकांत की पीठ ने सांसदों व विधायकों के मुकदमों के मामले में मंगलवार को जारी किए गए आदेश में बुधवार को एक और कालम जोड़ दिया है। इस बारे में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रारों को बताना होगा कि माननीयों के मामले सुन रही अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा है या नहीं।

मंगलवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा के बारे में केंद्र सरकार से पूछा था। लेकिन आदेश में इसके बारे में जिक्र छूट गया था। बुधवार को मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष आदेश में जिक्र न होने

सुप्रीम कोर्ट जागरण आर्काइव

की बात उठाई। इस पर पीठ ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों से विशेष अदालतों के बारे में मांगी गई जानकारी में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा के बारे में जानकारी देने का एक नया कालम जोड़ दिया।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों से सांसदों व विधायकों के केस सुन रही अदालतों के बारे में जो जानकारी मांगी है उसमें उन्हें बताना होगा कि कौन जज किस मामले की सुनवाई कर रहा है। किस जगह अदालत है। कितने दिनों से विशेष जज पद पर बने हुए हैं। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि विशेष जज के समक्ष कुल कितने केस लंबित हैं और उन्होंने कितने केस निपटाए। यह भी बताना होगा कि कितने मामलों में आदेश या फैसला सुरक्षित है। इसके साथ जो नया कालम जोड़ा गया उसमें बताना होगा कि उस अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं।

वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सांसदों व विधायकों के मामलों की जल्द सुनवाई की मांग की है। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया था जो राज्य सरकारों द्वारा लोक अभियोजक की शक्तियों का दुरुपयोग कर सांसदों व विधायकों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाने के बारे में था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि संबंधित हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर सांसदों व विधायकों के मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने ऐसे मुकदमों की सुनवाई कर रही अदालत के विशेष जज के स्थानांतरण पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।

उप राष्ट्रपति के तौर पर वेंकैया नायडू ने चार साल पूरे किए

नई दिल्ली, प्रेट्र : उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने बुधवार को अपने कार्यकाल के चार साल पूरे कर लिए। नायडू ने 11 अगस्त, 2017 को उप राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। इस मौके पर उप राष्ट्रपति के सचिवालय ने एक पुस्तिका जारी की, जिसमें नायडू के पिछले चार साल के कई कार्यक्रमों को स्थान दिया गया है। इस ई-बुक को कई भाषाओं में जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर नायडू देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर कोविड महामारी के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रबंध किए। इसका नतीजा रहा कि साल 2020-21 (बजट सत्र तक) में सदन का कामकाज 95.82 फीसद रहा जो 2017-18 में 48.17 फीसद था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यसभा में 44 विधेयक पारित किए गए जो पिछले चार साल में सर्वाधिक था।

नीट-एमडीएस दाखिले के लिए 20 अगस्त से शुरू होगी काउंसिलिंग

दी जानकारी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 10 अक्टूबर तक चलेगी काउंसिलिंग, इस बयान को रिकार्ड में शामिल कर पीठ ने मामले का किया निस्तारण

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नीट-एमडीएस दाखिले के लिए काउंसिलिंग 20 अगस्त से 10 अक्टूबर, 2021 तक करेगी। यह परीक्षा पिछले साल आयोजित की गई थी। केंद्र के बयान को रिकार्ड में शामिल करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने इस मामले का निस्तारण कर दिया।

सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह 20 अगस्त से 10 अक्टूबर, 2021 तक काउंसिलिंग करेगी। परीक्षा के आयोजन के सात महीने बाद काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षा 16 दिसंबर, 2020 को हुई थी और परिणाम की घोषणा 31 दिसंबर, 2020 को हुई थी।

गत नौ अगस्त को शीर्ष अदालत ने केंद्र से बुधवार तक यह बताने को कहा था कि वह नीट एमडीएस प्रवेश के लिए काउंसिलिंग कब आयोजित करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अब जब केंद्र सरकार ने मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है तो वह काउंसिलिंग कब कराएगी।

उल्लेखनीय है 29 जुलाई को, केंद्र ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए ओबीसी को 27 फीसद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआइक्यू) योजना में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 10 फीसद आरक्षण की घोषणा की है।

शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को, काउंसिलिंग आयोजित करने में देरी का कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा था कि केंद्र और अन्य पक्ष एक साल से ढिलाई बरत रहे हैं। बैचलर इन डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की उपाधि हासिल कर चुके करीब 30,000 अभ्यर्थी देश भर में (एमडीएस की) 6,500 से अधिक सीटों पर दाखिले के लिए पिछले साल आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-एमडीएस (मास्टर इन डेंटल सर्जरी) में शामिल हुए थे।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से होगा बीएचयू में दाखिला

जागरण संवाददाता, वाराणसी

▸ दाखिले की तैयारी को लेकर बुधवार को हुई आनलाइन बैठक, इसी माह शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा अगले माह से

मेडिकल व इंजीनियरिंग की तर्ज पर अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सभी पाठ्यक्रमों में एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से दाखिला होगा। बीएचयू में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। एनटीए और बीएचयू के अधिकारियों ने इस संबंध में बुधवार को आनलाइन बैठक की। गुरुवार को एनटीए के टीम परिसर का जायजा लेने आ सकती है। सब ठीक रहा तो अगले माह से प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

पिछले साल बीएचयू में करीब सवा पांच लाख आवेदन आए थे। यहां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की करीब 12,000 सीटों पर एडमिशन होना है। बीएचयू के पीआरओ डा. राजेश सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में पहली बार एनटीए के माध्यम से दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कोशिश है कि अक्टूबर में प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो जाएं। इसके लिए तैयारी जोरों पर चल रही है।

10वीं की मेरिट के आधार पर होगा दाखिला : बीएचयू के स्कूलों सेंट्रल हिंदू स्कूल गर्ल्स एवं ब्वायज, प्राथमिक विद्यालय कोल्हुआ और रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा में भी दाखिले की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि इस बार 11वीं में दाखिला 10वीं की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीद है इसी सप्ताह से 11वीं में प्रवेश के लिए 10वीं की मार्कशीट बीएचयू सेट (स्कूल इंट्रेंस टेस्ट) की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। छठवीं एवं नौवीं में दाखिला ई-लाटरी के माध्यम से होगा। नर्सरी में प्रवेश पहले से ही लाटरी के माध्यम से हो रहा है। इस बार ई-लाटरी से लिया जाएगा।

कह के रहेंगे माधव जोशी

1 फीसद कोटा मिला अनाथों को महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अनाथों को दिए जाने वाले आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 12 अगस्त, 2021

बिहार भाजपा में भी उभर रहे जातीय जनगणना के स्वर

राज्य ब्यूरो, पटना

- रामसूरत राय बोले, जातीय गणना हो और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून भी बने

भाजपा में भी अगले वर्ष जनगणना के साथ जातियों की गणना के पक्ष में स्वर उभर रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि जातीय जनगणना भी हो और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून भी बने, लेकिन इस पर निर्णय करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है। हम समझते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय लेगा। रामसूरत राय भाजपा कोटा के संभवतः पहले मंत्री हैं, जिन्होंने कुछ शर्तों के साथ ही सही जातीय गणना की मांग का समर्थन किया है। अब तक जदयू, राजद, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वामदल ही इस मांग का समर्थन कर रहे हैं।

रामसूरत राय ने बुधवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि जातीय गणना और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून, दोनों जरूरी है, लेकिन यह उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। उन्होंने भाजपा कोटे के ही दूसरे मंत्री नीरज कुमार की मांग पर टिप्पणी करने से इन्कार किया, जिसमें जातीय गणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की राय दी गई थी। रामसूरत राय ने जातीय गणना के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री सक्षम हैं।

जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से समाज में सद्भाव बढ़ेगा : भाजपा कोटे से ही पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बड़ा विषय यही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। कानून के माध्यम से ही हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, पार्टी या लोगों को पूरे राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से समाज में सद्भाव बढ़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से इसका बड़ा असर होगा। कानून के दायरे में लाकर हम समाज को सही दिशा दे सकते हैं।

राजद के कार्यक्रमों से जगदानंद ने बनाई दूरी

राज्य ब्यूरो, पटना

- तेजप्रताप के बयान से आहत हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष

सामान्य दिनों में राजद की बिहार प्रदेश कार्यालय में नियमित आने वाले एवं पार्टी की गतिविधियों को फ्रंट से नेतृत्व करने वाले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछले चार दिनों से नहीं दिखाई दे रहे। ऐतिहासिक शहादत दिवस पर बुधवार को शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के लिए भी सामने नहीं आए। कहा जा रहा है कि तेजप्रताप यादव के बयान से उनके सम्मान और अनुशासन को धक्का लगा है। राजद के स्थापना दिवस पर पांच जुलाई को भी तेजप्रताप के ऐसे ही बयान से खफा होकर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। हालांकि लालू प्रसाद के हस्तक्षेप के बाद मामले को संभाल लिया गया था, मगर इस बार उन्होंने दिल पर ले लिया है। लालू परिवार का मनुहार भी अभी तक काम नहीं आ रहा। किसी से मिल भी नहीं रहे। संपर्क से भी दूर हैं। राजद की ओर से बताया जा रहा कि उनकी तबीयत खराब है।

पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक बुधवार को राजद नेताओं के साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को विधानसभा के सामने स्मारक स्थल

जगदानंद सिंह। फाइल/इंटरनेट मीडिया

पहुंचना था। दोपहर एक बजे शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करना था, लेकिन जगदानंद ने उसे भी नजरअंदाज किया। उनकी अनुपस्थिति में राजद के अन्य नेताओं ने शहीदों के स्मारक पर माल्यार्पण किया। मीडिया के सवालों पर राजद नेताओं ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत खराब है, मगर सूत्रों का कहना है कि वह तेजप्रताप के बयान से आहत हैं। हालांकि राजद की ओर से कोई भी अधिकृत बयान देने के लिए तैयार नहीं है। छात्र राजद के कार्यक्रम में तेजप्रताप ने जगदानंद की तुलना हिटलर से की थी।

लालू व तेजस्वी के विश्वस्त, लेकिन तेजप्रताप कर रहे अवहेलना : जगदानंद को राजद प्रमुख का बेहद करीबी और पार्टी में रणनीतिकारों की अगली पंक्ति का नेता गिना जाता है। चारा घोटाले में लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी सरकार को संभालने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। लालू परिवार के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव का विश्वास भी उन्हें प्राप्त है। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद 2019 के आखिर में लालू प्रसाद ने जिस मकसद से उन्हें प्रदेश राजद की कमान सौंपी थी, उसे उन्होंने विधानसभा चुनाव में काफी हद तक पूरा भी किया। राजद प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, मगर तेजप्रताप की ओर से उन्हें कभी वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वह हकदार हैं। उनके खिलाफ तेजप्रताप का रुख हमेशा आक्रामक रहा है।

डैमेज कंट्रोल का प्रयास जारी : लालू परिवार से खबर है कि जगदानंद को दो स्तर पर मनाने का प्रयास जारी है। राजद प्रमुख ने स्वयं उनसे बात की है। तेजप्रताप को भी समझाया गया है। हिदायत भी दी गई है। राजद में जगदानंद के महत्व और जरूरत की बात कही गई है।

कर्नाटक में विभागों से नाखुश दो मंत्रियों ने दी इस्तीफे की धमकी

- मुख्यमंत्री बोम्मई ने जताया भरोसा, खत्म हो जाएगा असंतोष

बेंगलुरु, आइएएनएस : कर्नाटक में करीब दो हफ्ते पहले बनी बासवराज बोम्मई सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। मंत्रिमंडल गठन के तत्काल बाद मंत्री बनने से वंचित रह गए दो पूर्व मंत्रियों ने असंतोष जताया था। अब दो मंत्रियों ने पसंद वाले विभागों की मांग पूरी न होने पर इस्तीफे की धमकी दी है। इस्तीफे की धमकी देने वाले आनंद सिंह और एमटीबी नागराज 2019 में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन से आए थे और येदियुरप्पा सरकार में भी मंत्री थे।

पिछले हफ्ते हुए विभागों के वितरण में आनंद सिंह को पर्यटन और नागराज को निकाय प्रशासन विभाग दिए गए हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार आनंद सिंह ने सीएम को इस्तीफा भेज दिया है, जबकि नागराज ने साफ कर दिया है कि उन्हें पसंद का विभाग नहीं मिला तो वह इस्तीफा दे देंगे। आनंद सिंह ने विजयनगर स्थित अपना कार्यालय खाली कर दिया है और कहा है कि पसंद का विभाग न मिलने पर वह विधायक के रूप में कार्य करेंगे। फिलहाल उन्होंने अपना मोबाइल फोन आफ कर लिया है।

नुकसान बचाने में जुटे बोम्मई ने कहा, आनंद सिंह से उनकी दोस्ती तीन दशक पुरानी है और नागराज के साथ भी कोई समस्या नहीं है। आनंद से बात हुई है, जल्द ही उनसे मुलाकात होगी। उस मुलाकात में सब-कुछ सामान्य हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार आनंद सिंह ने मुख्यमंत्री से लोक निर्माण विभाग और नागराज ने आवास विभाग की मांग की है, जबकि बोम्मई ने लोक निर्माण विभाग सीसी पाटिल को दे रखा है। विभाग को लेकर मांग उठने की भनक लगते ही पाटिल दिल्ली चले गए हैं। वहां पर उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की है और अपना विभाग न बदले जाने का अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार कई अन्य मंत्री भी दिल्ली गए हुए हैं, वे भी अपना विभाग बदलवाना या बचाए रखना चाहते हैं। पता चला है कि पूर्व मंत्री सीपी योगेश्वर पहले से दिल्ली में हैं। रमेश जारकिहोली के भी जल्द ही दिल्ली जाने के संकेत हैं। येदियुरप्पा के प्रिय एमपी रेनुकाचार्य भी दिल्ली में हैं। उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है।

कृषि कानूनों पर पंजाब के सभी दलों से बात करें पीएम : कैप्टन

अपील ▸ पंजाब के मुख्यमंत्री ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात

कहा, देश विरोधी ताकतें किसानों की नाराजगी का उठा सकती हैं नाजायज फायदा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करके कृषि सुधार कानून रद करने की मांग की। कैप्टन ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वह कृषि कानूनों को लेकर पंजाब से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने के लिए समय दें। उन्होंने कृषि मुद्दों पर प्रधानमंत्री को दो अलग-अलग पत्र सौंपे। कहा कि कृषि कानूनों के कारण पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों में बड़े स्तर पर गुस्सा है।

कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि किसानों के संघर्ष से पंजाब और देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा खड़ा होने की आशंका है, क्योंकि पाकिस्तान की शह पर भारत विरोधी ताकतें सरकार के प्रति किसानों की नाराजगी का नाजायज फायदा उठाने की फिराक में हैं। इसलिए इस मुद्दे का स्थायी हल ढूंढने के लिए प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए। आंदोलन पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले कैप्टन : कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मिले। कैप्टन ने कोरोना वैक्सीन की कम सप्लाई का मुद्दा उठाते हुए राज्य में 55 लाख खुराक देने की मांग की तो केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के लिए वैक्सीन सप्लाई में 25 फीसद बढ़ोतरी के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक राज्य की जरूरत पूरी कर दी जाएगी। कैप्टन ने बठिंडा में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना पर विचार करने की अपील की।

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रेट्र

कैप्टन ने रखी ये मांगें

- पराली प्रबंधन के लिए किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल मुआवजा मिले
- खाद की कमी न होने दी जाए, क्योंकि इससे किसानों की समस्याएं बढ़ेंगी
- किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता श्रेणी में शामिल किया जाए

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश चुनाव समिति का एलान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कांग्रेस पार्टी ने उप्र विस चुनाव की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रदेश चुनाव समिति का एलान कर दिया। 38 सदस्यीय समिति के जरिये क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने की कोशिश की है। पुराने और वरिष्ठ नेताओं को इसमें तरजीह देकर अनुभवहीनता के आरोपों को भी धोने का प्रयास किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अनुमोदन के बाद पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों की सूची जारी कर दी है। लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से छह महीने पहले प्रदेश चुनाव समिति गठित की है। यह विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी आला कमान की गंभीरता का संकेत है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर को समिति में जगह नहीं मिली है। प्रदेश चुनाव समिति कांग्रेस की चुनावी गतिविधियों के संचालन में अहम भूमिका निभाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए जिलों से भेजे गए कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर विचार करने के बाद पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी।

कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उप्र के एआइसीसी फ्रंटल संगठनों/विभागों के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, सेवा दल व महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश चुनाव समिति के पदेन सदस्य होंगे। उप्र कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व महासचिव अपने जोन/क्षेत्र के लिए पदेन सदस्य होंगे। समिति में सात ब्राह्मण, तीन ठाकुर, दो कायस्थ व एक भूमिहार सदस्य हैं। एक सदस्य जैन संप्रदाय, दो बनिया बिरादरी और दो पंजाबी/खत्री हैं। समिति में पिछड़ा वर्ग के आठ, अनुसूचित जाति/जनजाति के दो और दस मुस्लिम सदस्य भी हैं।

समानांतर सरकार की शिकायत के अगले दिन ही सिद्धू ने बनाए चार सलाहकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

सियासत

- पूर्व डीजीपी ने मुस्तफा ने वापस लिया नाम
- कैप्टन अमरिंदर के लिए चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा फैसला

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच हुई मुलाकात में नवजोत सिंह सिद्धू के 'समानांतर सरकार' चलाने की चर्चा को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि की सिद्धू ने अपने चार सलाहकार नियुक्त कर लिए। पंजाब कांग्रेस के इतिहास में पहली बार है जब पार्टी अध्यक्ष ने अपने साथ चार सलाहकार नियुक्त किए हों। सिद्धू के इस फैसले को मुख्यमंत्री के लिए चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है।

सिद्धू ने जिन चार लोगों को सलाहकार बनाया है, उनमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का है। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। सिद्धू को फोन पर बता भी दिया है। हालांकि, उन्होंने अभी कारण स्पष्ट नहीं किया है। मुस्तफा 2017 के चुनाव से पहले कैप्टन के करीबी अफसरों में माने जाते थे। पूरा यकीन था कि कैप्टन सरकार में वह डीजीपी बनेंगे, लेकिन कैप्टन ने सुरेश अरोड़ा को ही इस पद बने रहने दिया। अरोड़ा रिटायर हुए तो दिनकर गुप्ता को डीजीपी बना दिया जो मुस्तफा से काफी जूनियर थे। डीजीपी के पैनल में मुस्तफा का नाम तक नहीं था। इस फैसले को मुस्तफा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताया।

दूसरे सदस्य डा. अमर सिंह फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस सांसद है। उनको सिद्धू ने अपने मंत्री रहते हुए ओएसडी

नवजोत सिंह सिद्धू। फाइल/इंटरनेट मीडिया

के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन 2018 में ही उन्हें इस पद से हटा दिया था। तीसरे सदस्य मालविंदर माली पूर्व एसजीपीसी अध्यक्ष स्व. गुरचरण सिंह टोहड़ा के मीडिया सलाहकार रहे हैं। वह पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाते रहे। किसान आंदोलन पर भी वह अलग राय रखते हैं। आतंकवाद के दौर में मारे गए युवाओं के मानवाधिकार का मामले उठाते रहे हैं। 2002 से 2007 तक कैप्टन सरकार में सीएमओ में काम करते रहे। सरकार बदली तो प्रकाश सिंह बादल के मीडिया सलाहकार हरचरण बैंस के साथ काम करते रहे। चौथे सलाहकार डा. प्यारा लाल गर्ग बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ मेडिकल साइंसिज के रजिस्ट्रार रहे हैं। वह कई वर्षों से चुनाव में सुधार की मुहिम चला रहे हैं। आजकल 'पिंड बचाओ, पंजाब बचाओ' संगठन में काम कर रहे हैं।

सीएम बदलने की मांग उठाने की तैयारी

कैलाश नाथ, चंडीगढ़ : कैप्टन अमरिंदर सिंह को कैबिनेट फेरबदल की मंजूरी मिलने के बाद सिद्धू खेमे सक्रिय हो गया है। कांग्रेस भवन में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद बाजवा के सरकारी आवास पर सिद्धू ने अपने खेमे के मंत्रियों व विधायकों के साथ बैठक की। फैसला लिया कि 2022 के विस चुनाव की तैयारी को लेकर सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई जाए और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की जाए। रणनीति बनी कि बैठक का एजेंडा 2022 का चुनाव रखा जाए। बैठक में मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, रजिया सुल्ताना के अलावा संगत सिंह गिलजियां, कुलजीत नागरा, बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा, कुलबीर जीरा, कुशलदीप सिंह ढिल्लों समेत करीब दस से बारह नेता मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक में सिद्धू कैंप का कोई विधायक इस मुद्दे को उठा सकता है। कैबिनेट फेरबदल को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी तृप्त बाजवा, सुखबिंदर सरकारिया व सुखजिंदर रंधावा में है। माना जा रहा है कि विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह को मुख्यमंत्री कैबिनेट में लाना चाहते हैं। ऐसे में उपरोक्त मंत्रियों में से एक को स्पीकर बनाया जा सकता है।

जानकार बताते हैं कि कैप्टन के शिकायत करने के बाद सोनिया गांधी ने पंजाब प्रभारी हरीश रावत को निर्देश दिए कि वह पंजाब जाकर सिद्धू की समस्याओं का समाधान करें।

गुजरात विस चुनाव में स्टार प्रचारक होंगे राहुल

राज्य ब्यूरो, अहमदाबादः प्रदेश कांग्रेस एवं विधायक दल ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक घोषित किया है। पार्टी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर फिलहाल टिप्पणी करने से इन्कार किया है।

विधायकों व पार्टी नेताओं ने मंगलवार शाम गांधीनगर में प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा की अध्यक्षता में बैठक की। नेता विपक्ष परेश धनाणी विस में पार्टी सचेतक, उप सचेतक सहित पार्टी के सभी विधायक व पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीट पर जीत दर्ज कर अपना शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पार्टी के सभी बड़े नेताओं की हार के कारण पार्टी सत्ता से वंचित रह गई थी। उस चुनाव में राहुल गांधी के साथ रणनीतिक भूमिका में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश प्रभारी के रूप में मौजूद थे।

संजय सिंह को छोड़ूंगा नहीं : भाजपा विधायक

जागरण संवाददाता, लखनऊ

- भाजपा विधायक अजय सिंह की तहरीर पर लखनऊ में दर्ज हुई थी एफआइआर
- राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की टिप्पणी को लेकर हरैया से भाजपा विधायक अजय सिंह के तेवर और सख्त हो गए हैं। 'दैनिक जागरण' से बातचीत में अजय सिंह ने कहा कि संजय सिंह को वह छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्हें बदनाम करने वाले को जेल जाना ही होगा। अजय सिंह ने कहा, संजय सिंह का स्तर यह है कि वह आरोप लगाकर दिल्ली भाग गए, अगर दम था तो यहां रहकर सच्चाई का सामना करते। उन्हें मानहानि का नोटिस दिया गया है। भाजपा विधायक ने संजय सिंह को बरसाती मेंढक बताते हुए कहा कि चुनावी जमीन तलाशने के लिए वह ऐसा करते हैं। संजय सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की जाए।

गौरतलब है कि विधायक ने संजय सिंह पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये बदनाम करने का आरोप लगाया है। इस मामले की विवेचना कर रहे उप निरीक्षक ने हरैया के विधायक अजय सिंह से दस्तावेज मांगे हैं, जिससे संजय सिंह पर शिकंजा और कसा जा सके। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली के कार्यवाहक इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने बताया कि अजय सिंह ने संजय सिंह पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर गलत बयानबाजी करने का जो आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

यह है मामला : मंगलवार को भाजपा विधायक अजय सिंह ने हजरतगंज कोतवाली में दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि संजय सिंह ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज मीडिया के सामने पेश किए थे। ऐसा उन्हें और सरकार को बदनाम करने व छवि धूमिल करने के लिए ऐसा किया था। अजय सिंह के मुताबिक संजय सिंह ने सस्ती लोकप्रियता पाने और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह साजिश रची है। भाजपा विधायक ने बताया कि संजय सिंह ने उनका प्रपत्र जलशक्ति विभाग के संबंध में दिखाया, जबकि उन्होंने जो प्रश्न विधानसभा में उठाए थे वह सपा सरकार में सिंचाई विभाग के संबंध में थे।

डा. महेंद्र सिंह ने आप सांसद को भेजा कानूनी नोटिस

उप्र के जल शक्ति मंत्री डा.महेंद्र सिंह ने राज्यसभा सदस्य आप सांसद संजय सिंह को अवमानना नोटिस भेजा है। अधिवक्ता के जरिये भेजे गए नोटिस में उन्होने कहा कि संजय सिंह ने सरकार व उन पर भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाये हैं। मंत्री ने संजय सिंह से कहा कि वह नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर माफी मांगें और इंटरनेट मीडिया से संबंधित खबरों को तत्काल हटाएं।

तृणमूल से करीबी बनाने की कोशिश में माकपा, श्रमिक संगठन साथ मिलकर आंदोलन को राजी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- बंगाल में हमेशा धुरविरोधी रही हैं दोनों पार्टियां
- माकपा का मुख्य उद्देश्य भाजपा को रोकना है

बंगाल में धुरविरोधी रही तृणमूल कांग्रेस के प्रति माकपा का नजरिया कुछ दिनों से बदला-बदला सा नजर आ रहा है। वह उसके साथ करीबी बनाने की कोशिश में दिख रही है। इसी कड़ी में अब माकपा के श्रमिक संगठन सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) को बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन के साथ आंदोलन करने में कोई परहेज नहीं है। यह बात सीटू के राज्य सचिव अनादि साहू ने कही है।

गौरतलब है कि वाममोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस व माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा ने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी केंद्रीय समिति की बैठक के बाद यही संदेश दिया था। हालांकि, सभी ने स्पष्ट कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौता राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा, लेकिन राज्य में भाजपा की तरह तृणमूल का भी माकपा विरोध करेगी।

माकपा नेताओं के ऐसा कहने के बावजूद सीटू के प्रदेश सचिव अनादि साहू ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन के सदस्यों के साथ आंदोलन में शामिल होने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कांग्रेस के श्रमिक संगठन इंटक भी सीटू के साथ संयुक्त आंदोलन में शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है। अनादि साहू ने कहा कि सीटू विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में माकपा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के प्रति लचीला रवैया दिखाया है। यहां तक कि माकपा के राज्य सचिवालय की ओर से भी एक बयान जारी कर त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस नेताओं तथा कार्यकर्ताओं पर हमले की निंदा की गई है। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या त्रिपुरा में भाजपा को हटाने के लिए तृणमूल-माकपा में गठबंधन होगा, जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर होने की संभावना दिख रही है।

सोना तस्करी मामले में केरल सरकार को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका

कोच्चि, प्रेट्रः केरल हाई कोर्ट ने सनसनीखेज सोना तस्करी मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से सात मई को जारी उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने सोना तस्करी मामले में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को फंसाने के कथित प्रयास की जांच के लिए आयोग गठित करने का निर्देश दिया था। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में यदि समानांतर जांच की जाती है, तो उससे जांच बाधित होगी और पटरी से उतर जाएगी। इसका फायदा आरोपितों को होगा।

ईडी का पक्ष रखते हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी जांच का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि संबंधित विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची में आता है। दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने दावा किया कि ईडी केंद्र सरकार का विभाग है और ऐसे में वह रिट याचिका दाखिल नहीं कर सकती है। उसने यह भी कहा कि सोना तस्करी के पीछे राजनीतिक साजिश का पता लगाने के लिए जांच आयोग गठित करने का आदेश जारी किया गया था।

हाई कोर्ट ने यह कहते हुए दलील खारिज कर दी कि ईडी सिर्फ केंद्र सरकार का विभाग ही नहीं, बल्कि एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल करने का हक है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में साजिश के सवाल का विशेष अदालत परीक्षण करेगी, जो जांच की निगरानी कर रही है।

स्वप्ना का दावा, यूएई में विजयन को भेजी गई थी विदेशी मुद्रा

आइएएनएस के अनुसार, राजनयिक माध्यम से सोना तस्करी की मुख्य आरोपित स्वप्ना सुरेश ने दावा किया है कि 2017 में जब सीएम पिनराई विजयन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दौरे पर थे, तब उन्हें विदेशी मुद्रा भेजी गई थी। उसने यह आरोप सीमा शुल्क विभाग की तरफ से गलत तरीके से डालर विदेश भेजे जाने के मामले में जारी नोटिस का जवाब देते हुए लगाया है। 29 जुलाई को भेजे गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में उसने कहा है कि विजयन व तत्कालीन विस अध्यक्ष श्रीरामकृष्णन ने महावाणिज्य दूतावास के राजनयिक अहमद अल दौखी व महावाणिज्य दूत जमाल अल जाबी के जरिये विदेशी मुद्रा मंगवाई थी।

भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री को जमानत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को जमानत दे दी। कुलकर्णी को पिछले साल नवंबर में सीबीआइ ने भाजपा कार्यकर्ता योगेश गौड़ा की हत्या में संलिप्तता के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था।

जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि कुलकर्णी को तीन दिनों के भीतर संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाए और कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के तहत उन्हें जमानत दी जाए। मामले की जांच कर रही सीबीआइ की ओर से पेश वकील ने कुलकर्णी की जमानत याचिका का विरोध किया। भाजपा के जिला पंचायत सदस्य गौड़ा की जून 2016 में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित उनके जिम में हत्या कर दी गई थी। सितंबर 2019 में राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। सीबीआइ ने पिछले साल नवंबर में कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था।

रोम में आयोजित होने वाले विश्व शांति सम्मेलन के लिए ममता को भी न्योता

कोलकाता, राज्य ब्यूरोः एक अंतरराष्ट्रीय सामाजिक संगठन द्वारा रोम में आयोजित किए जाने वाले विश्व शांति सम्मेलन के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है। दो दिवसीय सम्मेलन छह अक्टूबर से आयोजित किया जाएगा।

जिस संगठन की ओर से ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है, उसे कम्युनिटी आफ सेंट एगिडियो कहा जाता है। यह संस्था मुख्य रूप से बेघर, बीमार और गरीब लोगों के लिए काम करती है। 1986 से उन्होंने दुनिया भर में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं। पूर्व में यह सम्मेलन यूरोप और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। संगठन के पत्र के अनुसार, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और पोप फ्रांसिस सहित इटली के शीर्ष नेता पहले ही सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमती जता चुके हैं। 2016 में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रोम का दौरा किया था।

बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने पीएम मोदी से की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- राज्य के हालात से उनको कराया अवगत, केंद्रीय गृहमंत्री शाह से भी मिल सकते हैं
- ट्वीट कर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी से भी मुलाकात की दी जानकारी

दिल्ली के दौरे पर गए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को संसद भवन में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद धनखड़ ने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। वहीं, सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने पीएम को राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात से भी अवगत कराया है।

खबर है कि राज्यपाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। वह राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गृहमंत्री को रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं। वहीं दूसरी ओर धनखड़ ने बुधवार को कहा कि उन्होंने शहर के ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल एवं अन्य सांस्कृतिक केंद्रों को और अधिक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने को लेकर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी से बातचीत की है। धनखड़ ने ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्री ने विक्टोरिया मेमोरियल, भारतीय संग्रहालय, साल्टलेक स्थित एशियाटिक सोसाइटी एंड द ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर (ईजेडसीसी) में पर्यटकों के और अधिक संख्या में आने को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

बुजुर्गों के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले राज्यों में राजस्थान, हिमाचल व मिजोरम

नई दिल्ली, प्रेट्र : राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और मिजोरम अपनी बुजुर्ग आबादी के गुणवत्तापूर्ण जीवन के मामले में शीर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं। इंस्टीट्यूट फार कम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार 'बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक' शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यह सूचकांक देश की बुजुर्ग आबादी के कल्याण का आकलन करता है।

रिपोर्ट में 50 लाख बुजुर्गों की आबादी वाले राज्यों को 'बुजुर्ग' और 50 लाख से कम बुजुर्गों की आबादी वाले राज्यों को 'अपेक्षाकृत बुजुर्ग' राज्यों की श्रेणी में रखा गया है।

राजस्थान बुजुर्ग राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र और बिहार हैं। हिमाचल प्रदेश अपेक्षाकृत बुजुर्ग राज्यों की सूची में सबसे आगे है, जबकि उत्तराखंड और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चंडीगढ़ और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणियों में शीर्ष स्कोर थे।

दूसरी ओर, तेलंगाना और गुजरात ने बुजुर्ग और अपेक्षाकृत बुजुर्ग राज्यों की श्रेणियों में सबसे कम स्कोर किया। जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राज्यों के क्षेत्रों में सबसे नीचे रखा गया था।

रिपोर्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन बिबेक देबराय ने कहा, 'भारत को अक्सर एक युवा समाज के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जनसांख्यिकीय लाभ होता है। लेकिन, जैसा कि हर देश के साथ होता है भारत में भी जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण उम्र बढ़ने की समस्या है।'

चार स्तंभों पर आधारित सूचकांक : चार प्रमुख स्तंभों के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। इसमें वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा शामिल हैं। इनमें आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षिक प्राप्ति और रोजगार, सामाजिक स्थिति, शारीरिक सुरक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सक्षम वातावरण जैसे आठ उप स्तंभ भी शामिल हैं।

इंस्टीट्यूट फार कम्पिटिटिवनेस के अध्यक्ष अमित कपूर ने कहा, 'अपनी बूढ़ी होती आबादी के निहितार्थ को समझने के लिए एक उचित निदान उपकरण के बिना, बुजुर्गों के लिए योजना बनाना नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती बन सकता है।'

किस स्तंभ में कितने स्कोर : आधिकारिक बयान के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली स्तंभ का सबसे ज्यादा राष्ट्रीय औसत 66.97 था। जबकि समाज कल्याण का औसत 62.34। वित्तीय कल्याण में यह स्कोर 44.7 रहा, जो शिक्षा प्राप्ति और रोजगार स्तंभ में 21 राज्यों के कमजोर प्रदर्शन के कारण कम रहा है जिसमें सुधार की संभावना है। बयान के मुताबिक राज्यों ने विशेष रूप से आय सुरक्षा स्तंभ में बहुत खराब प्रदर्शन किया है, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों में आय सुरक्षा में राष्ट्रीय औसत यानी 33.03 से भी कम प्रदर्शन किया है जो सभी स्तंभों में सबसे कम है।

वृद्धों की जिंदगी

- बुजुर्ग आबादी के गुणवत्तापूर्ण जीवन के मामले में तेलंगाना और गुजरात फिसड्डी
- बुजुर्गों की आबादी के आधार पर राज्यों की 'बुजुर्ग' और 'अपेक्षाकृत बुजुर्ग' की श्रेणियां बनाई गई

उम्र का पड़ाव पर सहारे की जरूरत। फाइल फोटो

बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता की श्रेणी-वार रैंकिंग

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य

राज्य	स्कोर	समग्र रैंकिंग
मिजोरम	59.79	1
मेघालय	56.00	2
मणिपुर	55.71	3
असम	53.13	4
सिक्किम	50.82	5
नगालैंड	50.77	6
त्रिपुरा	49.18	7
अरुणाचल प्रदेश	39.28	8

अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्य

राज्य	स्कोर	समग्र रैंकिंग
हिमाचल प्रदेश	61.04	1
उत्तराखंड	59.47	2
हरियाणा	58.16	3
ओडिशा	53.95	4
झारखंड	53.40	5
गोवा	52.56	6
केरल	51.49	7
पंजाब	50.87	8
छत्तीसगढ़	49.78	9
गुजरात	49.00	10

बुजुर्ग आबादी वाले राज्य

राज्य	स्कोर	समग्र रैंकिंग
राजस्थान	54.61	1
महाराष्ट्र	53.31	2
बिहार	51.82	3
तमिलनाडु	47.93	4
मध्य प्रदेश	47.11	5
कर्नाटक	46.92	6
उत्तर प्रदेश	46.80	7
आंध्र प्रदेश	44.37	8
बंगाल	41.01	9
तेलंगाना	38.19	10

केंद्र शासित प्रदेश

राज्य	स्कोर	समग्र रैंकिंग
चंडीगढ़	63.78	1
दादरा-नगर हवेली	58.58	2
अंडमान	55.54	3
दिल्ली	54.39	4
लक्षद्वीप	53.79	5
दमन और दीव	53.28	6
पुडुचेरी	53.03	7
जम्मू और कश्मीर	46.16	8

(आंकड़े पीआइबी की रिपोर्ट पर आधारित)

वरिष्ठ नौकरशाही में फेरबदल, केके पंत बने एनपीपीए प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने वरिष्ठ स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल की है। इसके तहत वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंत को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 1993 बैच के अधिकारी पंत वर्तमान में अपने कैडर राज्य हिमाचल प्रदेश में तैनात हैं।

कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, उन्हें शुभ्रा सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। शुभ्रा सिंह को उनके कैडर राज्य राजस्थान वापस भेजा गया है। बिहार कैडर के 1989 बैच के आइएएस अधिकारी अमृत लाल मीणा को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव (लाजिस्टिक्स) नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ नौकरशाह सुधीर गर्ग को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अतिरिक्त सचिव तथा जयंत सिन्हा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होंगे।

कटिंग, भूकंप व बारिश से कमजोर हो रहे पहाड़

हिमाचल में हादसा ▶ निर्माणकार्यों के लिए मशीनों के इस्तेमाल से बढ़ रही है परेशानी

चट्टानें तोड़ने के लिए विस्फोटक का होता है इस्तेमाल, जिससे पहाड़ पूरी तरह से हिल चुके

हंसराज सैनी, मंडी

सड़क व पनविद्युत प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए मशीनों से हो रही कटिंग, भूकंप व बारिश से देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में तकनीक के जरिये आबादी वाले क्षेत्रों में भूस्खलन का पता लगाना आसान है।

प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, जहां सड़क या फिर पनविद्युत प्रोजेक्ट निर्माण के लिए पहाड़ों से छेड़छाड़ नहीं हो रही हो। किन्नौर जिला इस दृष्टि से अतिसंवेदनशील है। यहां पनविद्युत प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए पहाड़ों का सीना बुरी तरह से छलनी किया गया है। चट्टानें तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल होता है, जिससे यहां के पहाड़ पूरी तरह से हिल चुके हैं। कटिंग, भूकंप व बारिश के कारण पहाड़ों के अंदर हलचल लगातार बढ़ रही है। चट्टानें धीरे-धीरे खिसक रही हैं। पेड़ों के कटान से नंगे हो चुके पहाड़ों की मिट्टी तेजी से बारिश का पानी सोख रही है। इससे मिट्टी कमजोर पड़ रही है। पकड़ ढीली हो रही है। ज्यादा पानी भरने से पहाड़ में फिर हल्की सी कंपन होने पर भूस्खलन हो रहा है।

ये जिले तकनीक के चलते प्रभावित होने से बचे : 12 अगस्त 2017 को कोटरोपी हादसे के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने इस समस्या से निपटने के लिए मंडी जिला प्रशासन के आग्रह पर भूस्खलन रोधी अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित की थी। यह प्रणाली पूरी तरह कारगर साबित हुई थी। कोटरोपी के अलावा इसे हणोगी में भी स्थापित किया था। चार साल में दोनों स्थानों पर कई बार भूस्खलन हुआ, मगर अग्रिम चेतावनी प्रणाली की वजह से एक भी व्यक्ति की जान इन चार सालों में नहीं नहीं गई। भूस्खलन रोधी तकनीकी को सिरमौर जिला प्रशासन ने भी अपनाया था। पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने अपने यहां यह तकनीक लगा रखी है।

किन्नौर ने सर्वे कराना तक उचित नहीं समझा : किन्नौर जिला प्रशासन ने जर्जर हो चुके अपने क्षेत्र के पहाड़ों का कभी विशेषज्ञों से सर्वे करवाना भी उचित नहीं समझा।

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार को पहाड़ टूटने के बाद मलबे में दबा वाहन। प्रेट्र

भूस्खलन से वदरीनाथ हाईवे 38 घंटे से वंद

जासं, देहरादून : उत्तराखंड में बारिश के साथ दुश्वारियों का दौर जारी है। खासकर पहाड़ों में भूस्खलन के कारण जगह-जगह मार्ग बाधित होने से जन-जीवन प्रभावित है। बदरीनाथ हाईवे पर तोताघाटी में भारी भूस्खलन के चलते 36 घंटे से आवाजाही ठप है। गौरीकुंड मार्ग और जोशीमठ-मलारी हाईवे पर भी लगातार भूस्खलन हो रहा है।

ये जुटे बचाव में

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रशासन की ओर से 10 रोगी वाहन, चार अर्थ रिमूवर मशीनें, कई मजदूर व पोकलेन सहित अन्य मशीनें बचाव कार्य में लगाई गईं थीं। इसके अलावा आइटीबीपी के 52, पुलिस के 30 और एनडीआरएफ के 27 जवान बचाव कार्य में जुटे थे।

इनकी गई जान : हादसे में रामपुर के रोहित, सोलन के कमलेश कुमार, हमीरपुर के विजय कुमार और किन्नौर के नितिशा सुंगरा, मीरा देवी, राधिका, प्रेम कुमारी, ज्ञानदासी, वंशिका व देवी चंद की मौत हो गई।

करीब 100 मीटर तक सड़क मलबे की चपेट में आई है। 20 से 30 फीट मलबे के नीचे वाहन दबे थे। सड़क से मलबा हटा दिया गया है। तीन छोटे वाहन और टिप्पर मिल गए हैं, जबकि बस व जीप नहीं मिली। बचावकर्मी बस व बोलेरो की तलाश में नदी की ओर गए हैं।

-आबिद हुसैन, जिला उपायुक्त, किन्नौर

कमजोर मानसून का देशभर में 15 तक रहेगा असर : आइएमडी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने बुधवार को बताया कि मौजूदा कमजोर मानसून का असर 15 अगस्त तक देशभर में जारी रहेगा। हालांकि, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से व बिहार में 14 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहेगी। इसके बाद इन हिस्सों में बारिश कमजोर हो जाएगी।

विभाग ने बताया कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान), मध्य भारत व प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर हिस्सों (तमिलनाडु व केरल के बाहर) समेत महाराष्ट्र व गुजरात में 15 अगस्त तक हल्की बारिश होती रहेगी। 16 अगस्त के बाद प्रायद्वीपीय भारत में बारिश तेज हो जाएगी। तमिलनाडु व केरल में अगले पांच दिनों तक छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में 14 व केरल में 12 अगस्त तक कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालयी बंगाल व सिक्किम में 14 अगस्त तक छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश जारी रह सकती है। असम व मेघालय में 13 अगस्त तक कहीं-कहीं अत्यधिक बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व गंगा से लगे बंगाल के हिस्सों में 14 अगस्त तक व्यापक और कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

बाढ़ पीड़ित मेरी काशी के लोगों की दिल से कीजिए मदद : पीएम

जागरण संवाददाता, वाराणसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फोन कर वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ के हालात की जानकारी ली। सुबह लगभग नौ बजे काल कर उन्होंने पूछा, 'क्या स्थिति है मेरी काशी की। बाढ़ से कितनी आबादी, कितने मोहल्ले और गांव प्रभावित होंगे।' जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री के एक-एक सवाल का बिंदुवार जवाब दिया। पीएम ने निर्देशित किया कि जानमाल की क्षति नहीं होनी चाहिए। दिल से सभी की मदद करिए। सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाएं। किसी तरह की परेशानी हो तो तत्काल फोन पर बताएं।

पीएम ने राहत सामग्री वितरण के बारे में भी पूछा। डीएम ने बताया कि राहत सामग्री वितरण में प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी जुटे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित चार हजार से अधिक परिवारों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में रखा गया है। वहां दोनों वक्त खाने व दूध-फल का इंतजाम, स्वच्छ पेयजल व जेनरेटर से रोशनी की व्यवस्था की गई है। शिविर में ही स्वास्थ्य कैंप स्थापित कर डाक्टर तैनात किए गए हैं। पशुओं के लिए चारा का भी मुकम्मल इंतजाम है। डीएम ने बताया कि एनडीआरएफ का भी हर स्तर पर सहयोग मिल रहा है। इससे लोगों को काफी मदद मिल रही है।

यमुना का कहर जारी, गंगा ने बढ़ाई पूर्वांचल की धुकधुकी

जागरण टीम, लखनऊ : पूर्वांचल में गंगा में बढ़ाव से तटवर्ती इलाकों में हाहाकार मच गया है। मीरजापुर, भदोही, वाराणसी, बलिया व गाजीपुर व चंदौली में गंगा के बढ़ने से गोमती, वरुणा, सई आदि सहायक नदियां उफन पर है। वहीं, बांदा, उरई आदि जिलों में यमुना का कहर जारी है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दो दिन से वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है।

बिहार में खतरनाक हुई गंगा, सहायक नदियां बेकाबू

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सहायक नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर एवं दक्षिण बिहार की तमाम नदियों का प्रवाह तेज हो गया है। पटना के लिए खतरनाक मानी जाने वाली पुनपुन एवं सोन में भी तेजी से पानी बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर पटना में 2016 के रिकार्ड से मात्र 50 सेंटीमीटर दूर रह गया है। बीते 24 घंटे के दौरान मनेर, दानापुर, दीघा, गांधी घाट, फतुहा और हाथीदह में 14 सेंटीमीटर वृद्धि दर्ज की गई। गंगा गांधी घाट में अब तक के उच्चतम जलस्तर 50.52 मीटर से मात्र 60 सेमी नीचे रह गई है।

भड़काऊ नारेबाजी के मामले में अश्विनी उपाध्याय को जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट उदभव कुमार जैन ने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन, यह अपराध जमानती है। वहीं अदालत ने कहा कि जहां तक घृणित बयानबाजी की धारा-153ए के तहत दर्ज मामले का सवाल है तो यह संभावना पर आधारित है। अभियोजन पक्ष इससे जुड़ा कोई सुबूत या साक्ष्य नहीं पेश कर सका। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे साबित हो सके कि घृणित बयानबाजी या भड़काऊ नारेबाजी आरोपित उपाध्याय की मौजूदगी में या उनके कहने पर की गई हो।

अदालत ने सभी तथ्यों को देखते हुए उपाध्याय को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत दी जाती है। साथ ही उनको जांच में सहयोग करने और बगैर अदालत की अनुमति से देश न छोड़ने का निर्देश भी दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजक पक्ष ने दलील दी कि घटना में उपाध्याय की प्रथम दृष्टया संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी। इतना ही नहीं घटनास्थल पर घृणित बयानबाजी की गई। उपाध्याय ने खुद जंतर-मंतर पर अपनी उपस्थिति स्वीकार की है। इस पर अदालत ने कहा कि अन्य धाराओं में लगे आरोप जमानती हैं। अदालत सिर्फ यह जानना चाहती है कि क्या उपाध्याय उस स्थान पर मौजूद थे जब नारेबाजी की गई? अभियोजक पक्ष ने जवाब में कहा कि प्रथम दृष्टया संलिप्तता दिखाई दे रही है, हालांकि मामले की जांच प्रारंभिक अवस्था में है।

पूरे देश में स्लीपर सेल तैयार करना चाहता था आइएस

नीलू रंजन, नई दिल्ली

- भटकल से गिरफ्तार आतंकियों जुफरी और अमीन ने उगला राज
- पाक-अफगान सीमा पर सक्रिय सरगनाओं से मिल रहे थे निर्देश

इस्लामिक स्टेट (आइएस) पूरे भारत में स्लीपर सेल और कट्टर समर्थकों की फौज तैयार करने में जुटा था। आइएस के गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में यह राज खुला है। एनआइए के अनुसार इन आतंकियों की देश में तत्काल किसी वारदात को अंजाम देने की योजना नहीं थी, बल्कि वे लंबी कार्ययोजना के तहत काम कर रहे थे। ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान सीमा पर सक्रिय अपने आकाओं के साथ लगातार संपर्क में थे।

ध्यान देने की बात है कि 'वायस आफ हिंद' के नाम से एक आनलाइन पत्रिका निकालने वाले आइएस के माड्यूल का एनआइए ने पर्दाफाश किया था। इस सिलसिले में कर्नाटक के भटकल से जुफरी जौहर दामुदी और इसके सहयोगी अमीन जुहैब को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। जुफरी जौहर दामुदी अपनी पहचान बदल अबु हाजिर अल बदरी के नाम से सक्रिय था।

एनआइए के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आतंकियों के पास कोई विस्फोटक सामग्री या हथियार बरामद नहीं हुआ। पूछताछ में जुफरी ने बताया कि उसे फिलहाल आइएस की प्रचार सामग्री को स्थानीय भाषाओं में छपवा कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और पूरे देश में स्लीपर सेल खड़ा करने का काम मिला था। जुफरी आइएस की अरबी में भेजे गई प्रचार सामग्री का मलयालम में अनुवाद करता था और इसके जरिये युवाओं को आइएस के लिए तैयार करता था।

जुफरी और अमीन से अब तक की पूछताछ से साफ हो गया है कि वे इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) की तर्ज पर पूरे देश में संगठन खड़ा करना चाहते थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके पीछे एक वजह जुफरी का आइएम के संस्थापक आतंकी भटकल भाइयों से संबंध होना है। दरअसल जुफरी का भाई अदनान हसन दामुदी तीनों भटकल भाइयों यासीन, रियाज और इकबाल भटकल के संपर्क में था और 2017 में एनआइए ने उसे आइएस से जुड़े ही एक मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह जेल में है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन की कार्यप्रणाली और पूरे देश में फैलाव से वाकिफ जुफरी उसी तर्ज पर आइएस का ढांचा खड़ा करने की कोशिश में था। सूत्रों के अनुसार जुफरी छद्म नाम से पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर सक्रिय आइएस के आतंकी आकाओं के साथ लगातार संपर्क में था। वहीं से उसे प्रचार सामग्री भी मिलती थी। जिन आइएस आतंकियों में वह संपर्क में था, उसमें एजाज अहंगर उर्फ अबु उस्मान अल कश्मीरी भी शामिल है। ध्यान देने के बात है कि अल कश्मीरी, आइएस जम्मू-कश्मीर का वली (प्रमुख) भी है। पिछले साल काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया था।

जम्मू कश्मीर में देशविरोधी तत्वों पर पीएसए नहीं, यूएपीए की नकेल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर में राष्ट्रविरोधी तत्वों, आतंकियों और अलगाववादियों पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए प्रदेश प्रशासन अब जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के बजाय गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई कर रहा है। पांच अगस्त, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने के मामले लगातार घटे हैं, जबकि यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की संख्या बढ़ी है। अब तक करीब 2364 लोगों पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके तहत बंदी बनाए गए 2350 में से करीब 1110 भी जेल में हैं। वहीं, पांच अगस्त 2019 से पांच अगस्त 2021 तक पीएसए के तहत बंदी बनाए गए करीब 954 में से लगभग 282 ही जेलों में बंद हैं।

राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पांच अगस्त, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी, अलगाववादी, हवाला व इससे संबंधित मामलों में पकड़े गए अधिकांश आरोपितों को यूएपीए के तहत ही बंदी बनाया गया था। वर्ष 2019 में यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में 918 आरोपितों को पकड़ा गया। वर्ष 2020 में यूएपीए के तहत दर्ज 557 मामलों में 953 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस वर्ष जुलाई के अंत तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस ने 493 लोगों को यूएपीए के तहत दर्ज 275 मामलों में पकड़ा है। एडवोकेट राजेंद्र जंवाल ने कहा कि बीते तीन वर्षों में पुलिस अब राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी तत्वों के खिलाफ अपनी नीतियों में बदलाव ला रही है।

उपलब्धि

अब इंदौर बना देश का पहला वाटर प्लस शहर

चार बार से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले के साथ जुड़ा एक और सितारा, कान्ह-सरस्वती नदियों और उनसे जुड़े नालों में गंदा पानी मिलने से रोका

नईदुनिया, इंदौर

लगातार चार बार से देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत रहे इंदौर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है। बुधवार को इसकी घोषणा की गई। इंदौर नगर निगम ने वाटर प्लस सर्टिफिकेट के लिए शहर की कान्ह और सरस्वती नदियों के अलावा उनसे जुड़े छोटे-बड़े नालों में गंदे पानी को मिलने से रोककर उसे पाइपलाइन के जरिये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। उपचार के बाद पानी का अलग-अलग कार्यों में दोबारा उपयोग भी किया जा रहा था। पिछले दो साल से नगर निगम वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने के प्रयास कर रहा था।

निगम अधिकारियों का कहना है कि देश के करीब 250 शहरों ने वाटर प्लस सर्टिफिकेट के लिए दावा पेश किया था, मगर दस्तावेज की जांच में 70 शहरों को मंत्रालय ने इस सर्टिफिकेट के लायक माना है। इंदौर पहला शहर है, जिसने यह सर्टिफिकेट हासिल किया है। इंदौर को सूरत से कड़ी टक्कर मिल रही थी, लेकिन बाजी इंदौर ने मारी। माना जा रहा है कि दूसरा सर्टिफिकेट सूरत को मिल सकता है। इसके अलावा नई दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन और नवी मुंबई जैसे शहर भी वाटर प्लस सर्टिफिकेट की दौड़ में हैं। इंदौर स्वच्छता के मामले में भी देशभर में सबसे आगे है।

वाटर प्लस सर्टिफिकेट के लिए इंदौर में नदी-नालों की सफाई की गई थी। हालांकि बारिश के कारण पानी गंदा दिखाई दे रहा है। नईदुनिया

इंदौर देश का पहला शहर बना है, जिसे स्वच्छता सर्वे में वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है। अधिकारियों की पूरी टीम और जनप्रतिनिधियों के साथ जनता को भी बधाई, जिसने अपने घरों के सीवरेज आउटफाल बंद करने में पूरा सहयोग दिया। स्वच्छता के पंच (पांचवीं बार) की दिशा में शहर ने पहला अहम पड़ाव पार कर लिया है।

- प्रतिभा पाल, नगर निगम आयुक्त, इंदौर

यह है वाटर प्लस सर्वे (सर्टिफिकेट)

- स्वच्छ भारत अभियान में माइक्रो लेवल पर जाने के लिए मंत्रालय ने सफाई के साथ वाटर प्लस को शामिल किया है। इसका मकसद शहरों में जलाशयों, नदियों और तालाबों को साफ करना है। मंत्रालय चाहता है कि नदी-नालों में केवल साफ और बरसाती पानी ही बहे और सीवरेज के पानी का दोबारा उपयोग होता रहे।
- वाटर प्लस सर्वे में पानी काला नहीं दिखना चाहिए। इंदौर में कान्ह-सरस्वती नदियां और उनसे जुड़े 25 छोटे-बड़े नाले इस गंदे पानी के सबसे बड़े वाहक थे। इनमें मिलने वाले सार्वजनिक और घरेलू आउटफाल बंद करने में कामयाबी पाई गई है।
- नदी-नालों में मिलने वाले पानी को पाइप लाइन के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तक लाया गया, जहां उसे उपचारित कर विभिन्न कार्यों में उसका दोबारा उपयोग होने लगा।
- वाटर प्लस के लिए किसी भी शहर को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) होना जरूरी है। इंदौर यह उपलब्धि पहले ही हासिल कर चुका है।

1500 किमी रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण

लावा पांडे, बालेश्वर

आसमान में अपनी ताकत बढ़ाते हुए भारत ने बुधवार को स्वदेशी तकनीक से बनी 1500 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे समुद्र, जमीन व मोबाइल लांचर तीनों तरीके से दागा जा सकता है। यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम तक पारंपरिक व आणविक युद्धास्त्र लेकर जाने में सक्षम है। इसकी गति ध्वनि गति से सात से नौ गुना अधिक है। बुधवार को नौवीं बार इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसका बूस्टर इंजन भारत में ही तैयार किया गया है। निर्भय मिसाइल का वजन एक हजार 500 किलो है। इसकी लंबाई छह मीटर है, जबकि व्यास 0.52 मीटर है।

डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान विकास संगठन) ने बुधवार सुबह 9:55 बजे ओडिशा के बालेश्वर जिले के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से इस आधुनिक व शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया। इससे पूर्व निर्भय मिसाइल में टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया गया था। मिसाइल में माणिक टर्बोफैन इंजन प्रयोग किया गया। परिणाम स्वरूप डीआरडीओ की तरफ से इसको इंडीजेंस टेक्नोलाजी क्रूज मिसाइल कहा जा रहा है। इससे मिसाइल को अधिक गति मिलेगी और आवाज कम होगी।

बालेश्वर में बुधवार को स्वदेशी तकनीक से बनी 1500 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। सौ. डीआरडीओ

केरल में हालात बेकाबू, ओणम से पहले सख्त लाकडाउन लागू

चिंता ▶ एक दिन पहले के मुकाबले नए मामले 10 हजार से ज्यादा बढ़े

140 दिन बाद सक्रिय मामलों की संख्या सबसे कम 3 .86 लाख हुई

जेएनएन, नई दिल्ली

केरल में कोरोना का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले महीने से ही राज्य में देश में मिल रहे कुल मामलों के आधे से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बकरीद के मौके पर पाबंदियों में छूट देने पर सर्वोच्च अदालत से फटकार खा चुकी राज्य की विजयन सरकार ने ओणम से पहले सख्त लाकडाउन लगा दिया है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां संक्रमण दर आठ फीसद से ज्यादा है। ओणम 20 अगस्त को है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो एक दिन पहले के मुकाबले नए मामलों में करीब 10 हजार की वृद्धि हुई है, लेकिन सक्रिय मामले 140 दिन बाद सबसे नीचे आ गए हैं।

केरल में संक्रमण को काबू में करने के लिए सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 15 अगस्त तक कम से कम टीके की एक डोज लगा देने का फैसला किया है। इसके अलावा 18 साल से अधिक उम्र के ऐसे मरीजों को भी 15 अगस्त तक टीके लगाए जाएंगे जो चलने-फिरने में लाचार हैं।

सबरीमाला के लिए 15 हजार श्रद्धालुओं की सीमा तय : 15 अगस्त के बाद सबरीमाला मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर 15 हजार प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही ओणम, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम जैसे त्योहारों के लिए सिर्फ जरूरी गतिविधियों को करने की ही छूट दी गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 38 हजार से ज्यादा नए केस मिले हैं, एक दिन पहले 28 हजार मामले मिले थे। नए मामलों में 21 हजार से ज्यादा अकेले केरल से हैं। सक्रिय मामले 3.86 लाख रह गए हैं जो कुल मामलों का 1.21 फीसद है।

अब तक कोरोना वैक्सीन की 52 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई : मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना रोधी वैक्सीन की अब तक 52 करोड़ से ज्यादा डोज लगा दी गई हैं। इनमें 40.50 करोड़ से अधिक पहली और 11.50 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज शामिल हैं। 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा करीब 23 करोड़ डोज दी गई हैं। मंत्रालय के अनुसार कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 2.25 करोड़ डोज बची हैं।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बुधवार को एक अस्पताल में कोरोना जांच के लिए पहुंची महिला का स्वैब सैंपल लिया गया। एएनआइ

केरल में एक से 20 अगस्त तक मिल सकते हैं 4.6 लाख मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र : केरल के आठ जिलों का दौरा कर चुकी छह सदस्यीय एक केंद्रीय टीम ने कहा है कि एक अगस्त से 20 अगस्त तक राज्य में कोरोना संक्रमण के करीब 4.6 लाख मामले सामने आ सकते हैं। केंद्रीय टीम का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के निदेशक डा. सुजीत सिंह ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि ओणम का त्योहार (20 अगस्त) नजदीक आने के साथ पाबंदियां हटाने की गतिविधियों और पर्यटन स्थलों को खोलने से चुनौतिपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। सिंह ने कहा कि इस दक्षिणी राज्य में टीके की दोनों डोज के बाद भी अधिक संख्या में दोबारा संक्रमण के मामले मिले हैं।

देश में कोरोना की स्थिति	
24 घंटे में नए मामले	38,353
कुल सक्रिय मामले	3,86,351
24 घंटे में टीकाकरण	41.38 लाख
कुल टीकाकरण	51.90 करोड़

बुधवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति	
नए मामले	38,353
कुल मामले	3,20,36,511
सक्रिय मामले	3,86,351
मौतें (24 घंटे में)	497
कुल मौतें	4,29,179
ठीक होने की दर	97.45 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.16 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.34 फीसद
जांचें (मंगलवार)	17,17,962
कुल जांचें (मंगलवार)	48,50,56,507

उप्र में कर्फ्यू अब सिर्फ रविवार को, कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रित होने पर सरकार ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी राहत

दूसरी लहर पूरी तरह काबू में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति देने के साथ ही दो दिन की साप्ताहिक बंदी से भी जनता को राहत दे दी है। अब सिर्फ रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू रहेगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकाल का पालन हर संस्था और स्थान पर करना होगा। 15 अगस्त से माध्यमिक शिक्षा के स्कूल और एक सितंबर से उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने का आदेश सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। दुकान-बाजार आदि भी एक जून से खोल दिए गए थे।

उत्तर प्रदेश में संक्रमण के नए मामले अब गिने-चुने ही आ रहे हैं। इसे देखते हुए 'दैनिक जागरण' ने मंगलवार के अंक में साप्ताहिक बंदी में राहत संबंधी जनभावनाओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया। उन तथ्यों और तर्कों पर सरकार ने भी विचार-मंथन किया। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में वर्तमान हालात की समीक्षा कर साप्ताहिक बंदी को दो दिन से घटाकर एक दिन करने के साथ ही कोचिंग संस्थान खुलवाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके बाद इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। इसके तहत सप्ताह में छह दिन सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार को ही रहेगी। यह आदेश आगामी शनिवार से लागू होगा। रात दस से सुबह छह बजे तक की रात्रिकालीन बंदी अभी लागू रहेगी।

स्वतंत्रता के सारथी — **महामारी से आजादी**

जिद और जज्बे से खोली रक्तदान की राह

हिमाचल प्रदेश में उमंग फाउंडेशन ने कोरोना कर्फ्यू में लगाए शिविर, सरकार से जारी कराई गाइडलाइन

अनिल ठाकुर • शिमला

किसी देश की स्वतंत्रता तब पूर्ण होती है, जब वहां के नागरिक अपने कर्तव्यों से आगे बढ़कर दूसरों के मौलिक अधिकारों और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए तत्पर होते हैं। कोरोना काल में भी कई ऐसे नायक सामने आए हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी महामारी से आजादी का बिगुल बजाए रखा। इस सीरीज में आज जानिए हिमाचल प्रदेश के एक संगठन की कहानी जिसने कोरोना कर्फ्यू के बीच भी प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के लिए रक्त की व्यवस्था की।

देश के लिए बना उदाहरण: हिमाचल प्रदेश में उमंग फाउंडेशन का कार्य देश के लिए उदाहरण बन गया। पिछले साल कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों में रक्त की कमी होने लगी थी। फाउंडेशन ने मार्च 2020 से अब तक 21 रक्तदान शिविरों में 1,400 से ज्यादा यूनिट रक्त एकत्र किया। वह भी तब जब रक्तदान शिविर लगाने की अनुमति के लिए फाउंडेशन को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी।

खून की कमी हो रही थी: उमंग फाउंडेशन के संस्थापक प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों के ब्लड बैंक खाली हो रहे थे। थैलेसीमिया से पीड़ित मरीज, प्रसव के दौरान महिलाओं और हादसों में घायल लोगों के इलाज में खून की कमी होने लगी थी। उन्होंने प्रदेश के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव व स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर रक्तदान शिविर लगाने की अनुमति मांगी। अधिकारियों ने साफ कहा कि इस संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं है। उनका प्रस्ताव 20 दिन तक सचिवालय में पड़ा रहा। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री के पास मामला उठाया। इसके बाद शासन ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान रक्तदान शिविर के लिए लिए अलग से गाइडलाइन तैयार की। कोरोना कर्फ्यू में शिमला के मशोबरा में पहला रक्तदान शिविर लगाया गया। इसके बाद अलग-अलग गांवों में शिविर लगाए गए।

यह भी रही चुनौती: सरकार की अनुमति के बाद लोगों को शिविर तक पहुंचाना चुनौती थी। वाहन चलाने की अनुमति नहीं थी। फाउंडेशन के सहयोगियों ने वाहन पास बनवाकर लोगों को रक्तदान शिविर तक पहुंचाया।

रक्त चाहिए तो तेजू नेगी को आता है फोन: शिमला के समाजसेवी तेजू नेगी ने भी इस कार्य में सराहनीय भूमिका निभाई। उन्होंने ठाकुर सेन नेगी नाम से एक ग्रुप बनाया है। इसमें 500 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। वह करीब 50 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से जुड़े हैं। अस्पतालों के ब्लड बैंक में उनका फोन नंबर उपलब्ध रहता है। यदि किसी को रक्त की जरूरत होती है तो तीमारदारों को उनका फोन नंबर दिया जाता है। तेजू खुद भी 29 बार रक्तदान कर चुके हैं।

शिमला के बल्देयां में लगे शिविर में रक्तदाता • जागरण आर्काइव

केंद्र सरकार ने भी जारी किए निर्देश

हिमाचल प्रदेश में प्रो. अजय श्रीवास्तव की पहल ने एक नया रास्ता खोला। इसके बाद बंगाल ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान रक्तदान शिविर को लेकर गाइडलाइन तैयार की। केंद्र सरकार की ओर से भी इस संकटकाल में जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की व्यवस्था बनाने को गाइडलाइन जारी की गई।

प्रो. अजय श्रीवास्तव

ब्रिक्स देशों संग मिलकर कोरोना की दवा बनाएगा डीयू

संजीव कुमार मिश्र, नई दिल्ली : देश ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का वीभत्स रूप देखा। कोरोना की तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है। टीकाकरण अभियान जोरशोर से चल रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह नकेल तो दवा आने के बाद ही लगेगी। इस दिशा में विज्ञानी प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के हंसराज कालेज के विज्ञानी ने एक ड्रग मालिक्यूल विकसित करने का दावा किया है जो कोरोना वायरस पर भी प्रभावी होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हंसराज कालेज के विज्ञानी द्वारा ईजाद ड्रग मालिक्यूल समेत अन्य मालिक्यूल पर शोध करने एवं इन शोध को दवा के रूप में परिणति करने के लिए पहल की है। मंत्रालय के निर्देशानुसार हंसराज कालेज, ब्रिक्स देशों के विज्ञानियों के साथ मिलकर शोध करेगा। कुल छह विज्ञानियों की टीम गठित की गई है। इसमें ब्राजील के दो वायरोलाजिस्ट, दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध विज्ञानी प्रो. अनिल और रूस के आर्टिफिशियल एंटेलिजेंस विशेषज्ञ शामिल हैं। भारत से हंसराज कालेज के प्रो. बृजेश राठी एवं एमिटी विवि के डा. डी कुमार शामिल हैं।

आंसुओं से भी हो सकेगी आरटीपीसीआर जांच

गजाधर द्विवेदी, गोरखपुर

आंसुओं ने कोरोना जांच का नया रास्ता खोल दिया है। दूसरी लहर के दौरान गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कालेज में आंख में लाली से पीड़ित 60 मरीजों के आंसुओं की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पालीमर्स चेन रिएक्शन (आरटीपीसीआर) जांच की गई। परिणाम वही आया जो नाक व गले के स्वाब की जांच में मिला था। 20 में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। शेष की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इसके बाद माइक्रोबायोलाजी विभाग ने आंसू की आरटीपीसीआर जांच कर रिपोर्ट का अध्ययन करने का निर्णय लिया है।

दूसरी लहर के दौरान मेडिकल कालेज के नेत्र रोग विभाग में आंखों में लाली की समस्या लेकर आए मरीजों में फंगस की आशंका हुई। जांच के लिए आंसू माइक्रोबायोलाजी विभाग में भेजे गए। रिपोर्ट में फंगस के संकेत नहीं मिले, तो विभाग ने उनकी आरटीपीसीआर जांच की। 60 में से 20 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। खास बात यह है कि इन सभी की सीटी वैल्यू 25 से नीचे थी, अर्थात उनमें वायरस का लोड अधिक था। ऐसे में बीआरडी ने उन संक्रमित मरीजों के आंसुओं की भी जांच का निर्णय लिया है। यदि उनके आंसुओं में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई तो कोरोना जांच का एक नया तरीका विकसित हो सकेगा। इस अध्ययन की रिपोर्ट इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) को भेजी जाएगी। आइसीएमआर के प्लानिंग कोआर्डिनेटर डा. रजनीकांत ने कहा कि आंसुओं से आरटीपीसीआर जांच नहीं की है और न ही इस जांच को वैधता दी गई है।

दो मरीजों की एक-एक आंख की रोशनी गई

जिन 20 मरीजों के आंसुओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, उनमें से दो मरीजों की एक-एक आंख की रोशनी चली गई है। हालांकि, डाक्टरों की सतर्कता के चलते दूसरी आंख की रोशनी बचा ली गई है। इसमें एक महराजगंज और दूसरा गोरखपुर का निवासी है। उनकी उम्र क्रमश: 45 व 50 वर्ष है। नेत्र रोग विभाग के अध्यक्ष डा. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि दोनों मरीजों की स्थिति अब ठीक है।

'अब भी दे सकते हैं आक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ब्योरा'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली सरकार को साफ कर दिया है कि आक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ब्योरा देने में देरी नहीं हुई है और वे अब भी इसे दे सकते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में लोकसभा में पूछे गए सवाल का हवाला दिया, जिसके संबंध में दिल्ली सरकार से भी जानकारी मांगी गई थी। ध्यान देने की बात है कि मंगलवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि केंद्र सरकार ने दिल्ली से आक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ब्योरा मांगा ही नहीं है।

मांडविया ने लोकसभा के सवाल के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली समेत सभी राज्यों को भेजी गई ई-मेल की प्रति ट्वीट की। उन्होंने मनीष सिसोदिया को संबोधित करते हुए लिखा, '26 जुलाई को मेरे मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को जो ई-मेल भेजी है, ये रही उसकी कापी। अभी भी देरी नहीं हुई है! 13 अगस्त तक आप ब्योरा भेज सकते हैं, ताकि हम प्रश्न का उत्तर संसद को भेज सकें। कृपया, अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा करके जरूरी ब्योरा जल्द से जल्द भिजवाएं।'

राष्ट्रीय फलक

'घर में पिता को नहीं पाकर खुद को कैसे संभालूंगी'

जागरण संवाददाता, देहरादून

▶ प्रधानमंत्री के उत्साहवर्धन ने टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए किया प्रेरित

टोक्यो ओलिंपिक में हैट्रिक लगाने वाली देश की प्रथम महिला हाकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने कहा कि पिता स्व. नाहर सिंह की कमी खल रही है। अगर वह यहां होते तो अपनी लाड़ली को देश की बेटी बनता देख, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। घर के अंदर उनको ना पाकर पता नहीं मैं किस तरह अपने आप को संभाल पाऊंगी।

मालूम हो कि गत 20 मई को वंदना के पिता नाहर सिंह का देहांत हो गया था। ओलिंपिक की तैयारियों के कारण वंदना उनके अंतिम दर्शन के लिए भी घर नहीं आ सकी थीं। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर वंदना ने पिता को याद किया। कहा, जब भी कहीं से भी खेल कर घर आती, तो मना करने के बावजूद पिता एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े मिलते थे, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री की हौसलाअफजाई व देशवासियों के प्यार ने अच्छा खेलने के लिए प्रेरित किया।' उन्होंने कहा कि हाकी एक टीम गेम है, इसमें सफलता व असफलता का श्रेय सभी खिलाड़ियों को जाता है। सभी की इसमें भूमिका रहती है। जिसे सभी खिलाड़ियों ने बखूबी निभाया है। वंदना ने कहा कि सेमीफाइनल में हार और उसके बाद कांस्य पदक के लिए हुए मैच में मिली हार से पूरी टीम निराश थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने टीम का उत्साहवर्धन किया, जिसके बाद टीम ने खुद को संभाल आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

वंदना ने कहा कि कुछ समय परिवार के साथ बिताने के बाद वह वापस अपनी तैयारियों में जुट जाएंगी। कहा कि एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड कप में पदक पर उनकी निगाहें टिकी हैं।

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बड़ी बहन रचना टारिया (बाएं) ने कुछ इस तरह वंदना कटारिया (दाएं) को गले लगा लिया। राजेश बड़थ्वाल

राजीव गांधी के नाम पर शुरू किया पुरस्कार

मुंबई, प्रेट्र : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम देश के शीर्ष खेल रत्न पुरस्कार से हटाए जाने के कुछ दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को समाज की मदद करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) संगठनों को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना की है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह पुरस्कार राजीव गांधी के योगदान के स्मरण के लिए है। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में आइटी क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन दिया था। आदेश के अनुसार, यह पुरस्कार हर साल दिवंगत कांग्रेस नेता की जयंती पर 20 अगस्त को दिया जाएगा। लेकिन इस साल प्राप्तकर्ता का चयन 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। पुरस्कार के लिए स्क्रीनिंग संगठनों के लिए रूपरेखा तय करने के लिए महाराष्ट्र सूचना और प्रौद्योगिकी निगम नोडल एजेंसी होगी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, 1944 को मुंबई में हुआ था।

ट्रेन में यात्री के सूटकेस को चूहों ने कुतरा रेलवे पर लगाया पांच हजार का हर्जाना

संवाद सूत्र, जोधपुर

▶ जोधपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने सुनाया फैसला

▶ यात्री द्वारा सामान बुक नहीं कराने की दलील को आयोग ने कर दिया खारिज

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने ट्रेन में यात्रा के दौरान चूहों द्वारा यात्री का सूटकेस कुतरने पर रेलवे पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

मामले के अनुसार जोधपुर के सूरसागर निवासी महेंद्रसिंह कच्छावा ने जोधपुर रेलवे स्टेशन के डीआरएम के विरुद्ध आयोग में शिकायत प्रस्तुत कर कहा था कि दो जनवरी, 2013 को सूर्यनगरी एक्सप्रेस से अहमदाबाद से जोधपुर की यात्रा के दौरान कोच में सही पेस्ट कंट्रोल नहीं होने व गंदगी होने से चूहों ने उसके सूटकेस को काटकर उसमें छेद कर दिया। इसकी शिकायत उन्होंने ट्रेन से उतरते ही जोधपुर रेलवे स्टेशन पर भी दर्ज करवाई गई थी। रेलवे द्वारा आयोग के समक्ष अपने जवाब में कोच में गंदगी व चूहे होने से मना करने के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि सूटकेस के लिए अलग से कोई किराया अदा नहीं किया गया था। ऐसे में यात्री के द्वारा बुक नहीं करवाए गए सामान की सुरक्षा के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। आयोग के अध्यक्ष डा. श्याम सुंदर लाटा, सदस्य डा. अनुराधा व्यास व आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय में कहा कि रेल-किराए में यात्री द्वारा अपने साथ सामान ले जाने की सुविधा भी सम्मलित होती है, जिसके कारण रेलवे सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। परिवादी द्वारा स्टेशन पर दर्ज करवाई गई शिकायत की वाणिज्यिक प्रबंधक द्वारा जांच कर इसे सही मानते हुए गंदगी के लिए सफाई ठेकेदार पर जुर्माना भी लगाया गया है। आयोग ने सूटकेस की कीमत 2790 रुपये के अलावा शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार रुपये की राशि परिवादी को रेलवे को चुकाने का आदेश दिया है।

कितने वजन तक का सामान ले जा सकते हैं यात्री

फर्स्ट एसी में यात्रा करने वाले 70, सेकंड एसी वाले 50, थर्ड एसी, चेयरकार और स्लीपर वाले 40 और जनरल में सफर करने वाले 35 किलोग्राम वजन तक का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। परिवार में चार लोग (दो वयस्क व दो बच्चे) हैं तो स्लीपर में सफर करने वाले 150 किलोग्राम वजन तक का सामान लेकर यात्रा कर सकता है।

सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो और तृणमूल कार्यकर्ता गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के हावड़ा जिले में भाजपा कार्यकर्ता की मूक-बधिर पत्नी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरिफ रहमान व शेख शाहनवाज दोनों को मंगलवार देर रात पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदकुमार इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपित सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। बुधवार को दोनों को हावड़ा अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बंगाल से भाजपा सांसदों ने बुधवार को प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष की अगुआई में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को कठोर सजा देने की मांग करते हुए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया।

मोबाइल लाक हुआ तो बड़े भाई को मार कर घर में ही दफनाया

जासं, सहारनपुर

गलत पिन डालने के बाद लाक हुए मोबाइल को लेकर हुए विवाद में नाबालिग ने अपने बड़े भाई की फावड़े से काटकर हत्या कर दी और शव को घर में ही दबा दिया था। मामला 25 दिन बाद खुला। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छोटे भाई को हिरासत में लेकर मामले का राजफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह जिला गौतमबुद्धनगर भेज दिया गया।

सहारनपुर स्थित फतेहपुर ढोला गांव निवासी एक दंपती की मौत हो चुकी है। उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा 20 वर्षीय का था और छोटा बेटा 16 साल का है। दोनों साथ रहते थे। एसपी देहात अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि 18 जुलाई को छोटे भाई ने नया मोबाइल खरीदा था। मोबाइल इस्तेमाल करते समय बड़े भाई से गलत पिन डल गया था। जिसके कारण मोबाइल लाक हो गया। इसको लेकर हुए झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट दिया था। इसके बाद छोटे भाई ने फावड़े और चाकू से वार कर बड़े भाई की हत्या कर दी और घर में ही गड्ढा खोदकर शव दबा दिया।

जहां शव को दबाया, वहीं बैठकर खाता था खाना

मकान के जिस हिस्से में आरोपित ने भाई की लाश को दबाया था। वहीं बैठकर आरोपित पिछले 24 दिनों से खाना खा रहा था। आरोपित से जब बड़े भाई के बारे में पड़ोसी पूछते थे। तब वह रिश्तेदारी में जाने की बात कहकर गुमराह कर देता था।

सांसद आजम खां, पत्नी और बेटे के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट

जागरण संवाददाता, रामपुर : फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने के मामले में फंसे सांसद आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा दी। इस मामले में सुनवाई के लिए अदालत ने 13 अगस्त की तिथि नियत की है।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि को लेकर है। वर्ष 2017 में उन्होंने स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां नवेद मियां ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला की उम्र कम है और वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति खारिज कर दी। अब्दुल्ला चुनाव जीत गए, लेकिन मामला कोर्ट पहुंच गया।

खुद के बनाए हेलीकाप्टर के परीक्षण में गई युवक की जान

राज्य ब्यूरो, मुंबई

▶ महाराष्ट्र के यवतमाल निवासी मैकेनिक ने तैयार किया था छोटा हेलीकाप्टर

खुद का हेलीकाप्टर बनाकर उड़ाने का जुनून यवतमाल के 25 वर्षीय मुन्ना शेख की जान पर बन आया। हेलीकाप्टर के परीक्षण करते वक्त हुए हादसे में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी।

घटना महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के फुलसावंगी गांव की है। शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना शेख पंखा, कूलर और वाशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों की मरम्मत करनेवाला छोटा-मोटा मैकेनिक था। गांव वाले बताते हैं कि सिर्फ आठवीं तक पढ़े मुन्ना का दिमाग बहुत तेज चलता था। वह पिछले दो साल से वेल्डिंग का काम करने वाले अपने भाई के गैराज में ही एक छोटा हेलीकाप्टर बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन पहले यह हेलीकाप्टर बनकर तैयार भी हो गया। इसे देखने के लिए कुछ लोग बेंगलुरु से आने वाले थे। इससे पहले मुन्ना हेलीकाप्टर का परीक्षण करना चाहता था। वह कुछ मित्रों की मदद से हेलीकाप्टर को उठाकर गांव से बाहर ले आया। मुन्ना ने हेलीकाप्टर में बैठकर जैसे ही उसे चालू किया, पीछे का पंखा टूटकर ऊपर घूम रहे पंखे से टकराया और तेज धमाके के साथ हेलीकाप्टर पलट गया। इस दुर्घटना में हेलीकाप्टर के अंदर बैठे मुन्ना के सिर में गंभीर चोट आई। उसे बचाया नहीं जा सका।

'दीपिका पादुकोण की मैनेजर पर एनडीपीएस कानून लगाना सही'

मुंबई, प्रेट्र : एक विशेष कोर्ट ने कहा है कि करिश्मा प्रकाश के खिलाफ ड्रग्स तस्करी के संबंध में अभियोजन द्वारा एनडीपीएस कानून के कठोर कानून का प्रयोग किया जाना सही है। कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रबंधक को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इन्कार कर दिया। विशेष एनडीपीएस अदालत ने पांच अगस्त को प्रकाश की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट के आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई। प्रकाश को बांबे हाई कोर्ट जाने के लिए 25 अगस्त तक का समय दिया गया है। प्रकाश के वकील के जरिये दाखिल अर्जी में कहा गया था कि अदालत के सामने ऐसा कुछ पेश नहीं किया जिससे एनडीपीएस एक्ट की धारा 27ए के प्रविधानों के तहत प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता हो।

राष्ट्रीय संस्करण
गुरुवार 12 अगस्त, 2021
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

खाद्यान्न उत्पादन 30.8 करोड़ टन रहने का अनुमान

नई दिल्ली: देश का खाद्यान्न उत्पादन फसल वर्ष 2020-21 में 30.86 करोड़ टन रहने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय ने बुधवार को चौथे अनुमान के तहत कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार खाद्यान्न उत्पादन में 3.74 फीसद बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकार ने कहा है कि बेहतर मानसून की बदौलत चावल, गेहूं व दालों का अच्छा उत्पादन होगा। (प्रेट्र)

किसानों के अथक प्रयासों, विज्ञानियों के कौशल और किसान-हितैषी सरकार के दम पर देश खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन कर रहा है।
— नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि मंत्री

सेंसेक्स	54,525.93	▼	28.73
निफ्टी	16,282.25	▲	2.15
सोना प्रति दस ग्राम	₹45,130	▲	₹159
चांदी प्रति किलोग्राम	₹61,250	▲	₹99
डॉलर	₹74.44	▲	₹0.01
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 70.74		

करदाताओं को ब्याज व विलंब शुल्क लौटाएगा आयकर विभाग

नई दिल्ली, प्रेट्र : आयकर विभाग की वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी के चलते बहुत से करदाता वर्ष 2020-21 का रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए। आयकर विभाग ने कहा है कि इन करदाताओं से जो विलंब शुल्क और अतिरिक्त ब्याज वसूला गया है, उसे वापस कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले वित्त वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई थी। इसके बावजूद कुछ करदाताओं ने शिकायत की थी कि जब उन्होंने 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल किया तो उनसे ब्याज और विलंब शुल्क वसूला गया।

विभाग ने ट्वीट में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा-234ए के तहत ब्याज की गलत गणना और आयकर अधिनियम की धारा-234एफ के तहत विलंब शुल्क जैसी त्रुटियों का निवारण पहली अगस्त को किया जा चुका है। करदाताओं को सलाह है कि साफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का उपयोग करते हुए आनलाइन रिटर्न दाखिल करें।

सरकारी-निजी क्षेत्र की भागीदारी से ही आत्मनिर्भर होगा देश : प्रधानमंत्री

निवेश और रोजगार को गति देने के लिए उद्योग जगत से काफी उम्मीद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अकेले सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इस काम में उद्योग जगत की बहुत बड़ी भागीदारी की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य ब्रांड इंडिया को मजबूत करने के साथ देश को समृद्ध करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्योग जगत के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करना होगा।

उद्योग संगठन सीआइआइ के साथ संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर्फ एक पहिये से गाड़ी नहीं चल सकती। सारे पहिये ठीक से चलने चाहिए। इसलिए उद्योग जगत को भी जोखिम लेने के अपने नैसर्गिक रुख को थोड़ा और बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि निवेश और रोजगार की गति को बढ़ाने के लिए देश को उद्योग जगत से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। और मैं उद्योग जगत से कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है। देश में विकास के प्रति जो वातावरण बना है, अपने सामर्थ्य के प्रति जो विश्वास बना है, भारतीय उद्योग जगत को उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।

नई दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उद्योग संगठन सीआइआइ की सालाना बैठक को संबोधित किया • एएनआइ

देशवासियों की भावना भारतीय उत्पाद के साथ: प्रधानमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि अब देशवासियों की भावना भारत में बने उत्पाद के साथ है। कंपनी भारतीय हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन अब हर भारतीय भारत में बने उत्पाद को अपनाना चाहता है। देश मन बना चुका है, अब उद्योग जगत को इस मन के मुताबिक अपनी नीति बनानी है, रणनीति बनानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में इससे मदद मिलेगी। एक समय था जब हमें लगता था कि जो कुछ भी विदेशी है, वही बेहतर है। अब स्थिति तेजी से बदल रही है।

रिफार्म की गति बरकरार: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक रिफार्म और ईज आफ डूइंग बिजनेस से देश में विदेशी निवेश खूब बढ़ा है। रिफार्म की गति बरकरार है।

आत्मविश्वास से लबरेज स्टार्ट-अप्स

पीएम ने कहा कि आज यूनिकार्न भारत की पहचान बन रहे हैं। सात-आठ वर्ष पहले देश में महज तीन-चार यूनिकार्न थे, जो अब लगभग 60 हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि भारत में बदलाव हो रहा है। महामारी में भी हमारे स्टार्ट-अप्स का मनोबल ऊंचा और महत्वाकांक्षा चरम पर है।

इन्फ्रा सेक्टर में विदेशी मुद्रा भंडार के उपयोग की वकालत

इस संबंध में शीघ्र ही आरबीआइ के गवर्नर से जल्द ही बात करेंगे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सड़क परियोजनाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के बढ़ रहे विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना चाहते हैं। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कम ब्याज वाले फंड की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने इस संबंध में एक नीति तैयार करने की वकालत की है।

उद्योग संगठन सीआइआइ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के पास बिजली मंत्रालय की तरह पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) जैसी एक वित्तीय इकाई होनी चाहिए। रिजर्व बैंक के खजाने में अरबों डालर हैं। मैंने आरबीआइ गवर्नर से इस बारे में बात करने का फैसला किया है कि हम किस तरह इस भंडार का उपयोग देश के बुनियादी ढांचे के विकास में कर सकते हैं।' आरबीआइ के ताजा आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.427 अरब डालर बढ़कर 620.576 अरब डालर के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

हाल ही में एक संसदीय समिति ने कहा था कि हाल के दिनों में विदेशी मुद्रा भंडार में काफी वृद्धि हुई है और केंद्रीय बैंक अतिरिक्त पैसे का उपयोग बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में कर सकता है। समिति ने यह भी कहा था कि आधारभूत परियोजनाओं को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए आरबीआइ अतिरिक्त पैसे का एक सावरेन वेल्थ फंड बनाने की जरूरत पर भी गौर सकता है। वहीं, इसी कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि वह प्रतिदिन 100 किमी राजमार्ग बनाने का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। कोरोना-काल के दौरान एक दिन में 38 किलोमीटर सड़क बनाने का विश्व रिकार्ड पहले ही हासिल हो चुका है।

छोटी कंपनियों के शेयरों में अस्थिरता रोकेगी नई निगरानी व्यवस्था

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्माल व मिडकैप शेयरों में अचानक आई तेज अस्थिरता की घटनाएं टालने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने नई निगरानी व्यवस्था लांच की है। बीएसई के सर्कुलर के अनुसार यह व्यवस्था उन कंपनियों के लिए फायदेमंद होगी, जिनका बाजार पूंजीकरण 1,000 करोड़ से कम है। इनमें एक्स, एक्सटी, जेड, जेडपी, जेडवाई व वाई ग्रुप की सिक्युरिटीज शामिल होंगी।

नए फ्रेमवर्क के अनुसार चयनित सिक्युरिटीज में छमाही, वार्षिक, दो वर्षों व तीन वर्षों वाले प्राइस बैंड होंगे। ये सभी प्राइस बैंड इन सिक्युरिटीज के लिए लागू दैनिक प्राइस बैंड के अतिरिक्त होंगे। सोमवार को बीएसई ने कहा था कि छोटी व मझोली कंपनियों में से चुनिंदा को साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक प्राइस बैंड भी लागू किया जाएगा। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि नई निगरानी व्यवस्था लागू करने का बीएसई का फैसला उचित समय पर किया गया है।

एक नजर में

साधारण बीमा कंपनियों के निजीकरण का रास्ता साफ

नई दिल्ली : सरकारी साधारण बीमा कंपनियों के निजीकरण से जुड़ा एक विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया। सदन द्वारा साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को मंजूरी दिए जाने के बाद चार साधारण बीमा कंपनियों के निजीकरण में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो गई हैं। (प्रेट्र)

नैनो यूरिया लिक्विड का निर्यात कर सकेगा इफको

नई दिल्ली : उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ इफको को नैनो यूरिया लिक्विड को निर्यात करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने जो शर्तें लगाई हैं, उसके अनुसार कुल निर्यात उत्पादन का 20 फीसद से अधिक नहीं होना चाहिए। निर्यात की जाने वाली यूरिया में किसी तरह के सब्सिडी वाले कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जाएगा। (एएनआइ)

स्वतंत्रता दिवस पर निर्यातकों को रोडटेप का तोहफा संभव

अच्छी खबर
- इस सप्ताह के अंत तक रोडटेप की घोषणा हो सकती है
- सितंबर मध्य तक नई विदेश व्यापार नीति लाने की भी तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार इस सप्ताह के अंत तक रेमिशन आफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज आन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (रोडटेप) की घोषणा कर सकती है। सचिव ने बताया कि नई विदेश व्यापार नीति भी सितंबर मध्य तक घोषित हो जाएगी। अगस्त आखिर तक विदेश व्यापार नीति अधिसूचित हो सकती है और मध्य सितंबर में उसे लांच किया जाएगा।

रोडटेप स्कीम को इस वर्ष पहली जनवरी से लागू माना जाएगा, लेकिन अब तक इसकी दरें घोषित नहीं की गई है। इससे निर्यातकों को पिछले कई महीनों से कोई रिफंड नहीं मिल रहा है। रोडटेप के तहत निर्यात होने वाली वस्तुओं को तैयार करने में लगने वाले टैक्स निर्यातकों को रिफंड कर दिए जाएंगे। यह मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम (एमईआइएस) की जगह लेगा। बुधवार को वाणिज्य सचिव ने कहा कि रोडटेप स्कीम के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पहले कम थी। स्कीम को इस सप्ताह के अंत तक घोषित किया जा सकता है। रोडटेप के तहत माल की ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर लगने वाले वैट, मंडी टैक्स, निर्यात होने वाली वस्तुओं के उत्पादन में बिजली पर लगने वाले शुल्क व इस प्रकार के अन्य शुल्क निर्यातकों को वापस मिल जाएंगे।

पीएम फसल बीमा योजना की खामियां गिनाते हुए किनारा कर रहे हैं राज्य

सुरेंद्र प्रसाद सिंह • नई दिल्ली

सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खामियां गिनाते हुए कई राज्यों ने इससे खुद को अलग कर लिया है। इनमें से ज्यादातर राज्यों ने अपनी अलग फसल बीमा योजना लागू की है, जिसमें भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने फसल बीमा योजना की खामियों को दूर कर सभी राज्यों को उसके दायरे में लाने की सिफारिश की है।

किसानों को उनकी खेती के जोखिम से बचाने के लिए रक्षा कवच के रूप में सरकार ने जोर-शोर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इसमें किसानों को न्यूनतम प्रीमियम भुगतान के साथ कई और रियायतें दी गईं। इसके बावजूद आधा दर्जन से अधिक राज्यों ने इससे खुद को अलग कर लिया है। पंजाब वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत से ही इससे अलग रहा था। बिहार ने वर्ष 2018 में और पश्चिम बंगाल ने खरीफ सीजन, 2019 से इसे वापस ले लिया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और झारखंड ने भी वर्ष 2020 से इस योजना को बंद कर दिया है।

इनमें लगभग सभी राज्यों ने वित्तीय संकट और मौसम के सामान्य रहने के दौरान दावों का कम भुगतान होने से योजना को लागू नहीं किया। वैसे कई राज्यों में उनकी अपनी फसल बीमा योजना चली जा रही है। संसद की स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने को लेकर राज्यों के समक्ष आ रही चुनौतियों और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खामियों को दूर करने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि राज्यों की ओर से योजना के लागू न करने की वजहों का विस्तार से अध्ययन करना और जरूरी कदम उठाकर योजना को देशव्यापी बनाया जाना चाहिए।

राज्यों का यह तर्क

पंजाब की तरह अन्य राज्यों का भी तर्क है कि उनके यहां किसानों को नुकसान नहीं के बराबर होता है, लिहाजा योजना उनके लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि देशभर में इस योजना की कवरेज 37 फीसद पर पहुंच चुकी है। कई संशोधनों के तहत योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है।

आटो सेक्टर को जीएसटी में राहत दिलाने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वाहन सेक्टर पर उच्च जीएसटी दरों का बोझ जल्द घट सकता है। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने माना है कि आटो सेक्टर पर जीएसटी की दरें अभी ऊंची हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जीएसटी की दरों को और अधिक तर्कसंगत बनाए जाने की प्रक्रिया में है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में कार और दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की 28 फीसद दर को घटाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं, सरकार तैयार माल और उनसे जुड़े कच्चे माल की जीएसटी दरों की विसंगतियां भी दूर करेगी। अभी कई उत्पाद ऐसे हैं जिनके कच्चे माल पर तैयार माल की तुलना में अधिक जीएसटी है।

हाल ही में देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने कारों पर जीएसटी दर घटाने और सेस खत्म करने की गुजारिश की थी। देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकार्प दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की मौजूदा 28 फीसद की दर को 18 फीसद पर लाने की मांग पहले ही कर चुकी है।

बुधवार को उद्यमियों के साथ हुई बैठक में बजाज ने कहा कि आटोमोटिव सेक्टर पर अधिक टैक्स का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और सरकार को उस पर विचार करने की जरूरत है। बजाज ने कहा, 'आटोमोटिव सेक्टर पर टैक्स दरों को लेकर मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। आप दोपहिया वाहनों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कार पर न सिर्फ 28 फीसद जीएसटी लगता है, बल्कि हम उस पर सेस भी वसूलते हैं जो और दो वर्षों के लिए जारी रह सकता है।'

राष्ट्रीय फलक

सड़कों से हटेंगे हजारों ट्रक, बचेगा करोड़ों लीटर डीजल, सुधरेगा पर्यावरण

10 घंटे में 700 किलोमीटर। पहले तकरीबन 30 घंटे लग जाते थे एक ट्रक को इतनी दूरी तय करने में लेकिन अब डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया (डीएफसीसीआइ) उत्तर भारत में भरे ट्रकों की ढुलाई के लिए तैयार है। इसी माह न्यू रेवाड़ी से गुजरात के न्यू पालनपुर स्टेशन के बीच भरे ट्रकों की बीआरएन फ्लैट वैगन से ढुलाई शुरू होने जा रही है। इससे पहले पूर्वोत्तर में इंडियन रेलवे व दक्षिण में कोंकण रेलवे यह सुविधा शुरू कर चुका है। खास बात हजारों ट्रक सड़कों से हट जाएंगे। करोड़ों लीटर डीजल जलने से बचेगा, यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

86.2 फीसद कार्बन निकलता है डीजल से | **720** ग्राम कार्बन, प्रति लीटर डीजल में | **1920** ग्राम आक्सीजन की जरूरत पड़ती है इसे जलाने को, लाखों गैलन डीजल बचाएगा नया प्रयोग

न्यू अटेली स्टेशन के निकट डीएफसी कारिडोर पर खड़ी कंटेनर ट्रेन। कंटेनरों की तरह ही निकट भविष्य में भरे हुए ट्रकों को भेजा जाएगा • जागरण

मिलेगा लाभ ही लाभ

2 डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर देश में पूर्वी व पश्चिमी में निर्माण के अंतिम चरण में।

3000 किमी है दोनों की लंबाई।

पूर्वी कारिडोर: पंजाब के साहनेवाल से पश्चिम बंगाल के डानकुनी तक।

पश्चिमी कारिडोर: उप्र के दादरी से मुंबई तक बन रहा है।

70% मालगाड़ी डीएफसी परियोजना के सभी चरण पूरे होने पर इसी पर निर्भर हो जाएंगी।

3 गुना बढ़ेगी मालगाड़ियों की गति।

400 कंटेनर एक डीएफसी ट्रेन में।

पर्यावरण मित्र की भूमिका

- सड़कों पर दबाव कम होने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटेगा।
- 1000 से 1300 ट्रकों का लोड कम होगा सड़कों पर एक डीएफसी ट्रेन से।
- 45 करोड़ टन तक कम हो जाएगा कार्बनडाइआक्साइड का उत्सर्जन दो से तीन दशक में देश में।
- 270 उच्च क्षमता वाले ट्रकों के बराबर वजन ढो सकती है डीएफसी ट्रैक पर दौड़ने वाली मालगाड़ी।
- 14 फीसद अधिक भारत क्षमता है डीएफसी के नए वैगन की।
- रोरो का नया प्रयोग ट्रक मालिकों को बड़ी राहत देगा।
- 10 मिनट पर दौड़ सकेगी एक ट्रेन, परियोजना पूरी होने के बाद।
- डीजल लागत से कम किराए में ट्रक गंतव्य तक पहुंचने से ट्रांसपोर्टर को समय व धन की बचत होगी।
- वाहन के रखरखाव का खर्च भी घट जाएगा। पहिए नहीं घिसेंगे, इंजन ठीक रहेगा, श्रम बचेगा आदि आदि।

कोंकण में चर्चित है रोरो सेवा

भरे ट्रकों को सीधे रेलवे के वैगन पर लोड करके भेजना रोरो (रोल आन रोल आफ) सेवा कहलाता है। कोंकण रेलवे की यह सेवा चर्चित है। बिहार में भी वर्ष 2016 में ऐसा प्रयोग हो चुका है, मगर डीएफसी पर पहली बार यह शुरुआत होने जा रही है। डीएफसी पर दो कीर्तिमान पहले बन चुके हैं। पिछले वर्ष जहां पीएम मोदी ने न्यू अटेली स्टेशन से डबल स्टैक (सामान्य से दो गुना लंबाई की डबल डेकर मालगाड़ी) कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाई थी वहीं, इस वर्ष सेना की आयुध सामग्री भेजने का सफल ट्रायल हो चुका है। अब भरे हुए सामान्य ट्रकों को भेजने का ट्रायल इस माह किसी भी दिन संभव है। इसके लिए बीआरएन (बोगी ओपन फ्लैट वैगन रेल ट्रक) डिजाइन के फ्लैट वैगन देश में ही तैयार करवाए हैं। रोरो सेवा से सड़कों पर ट्रकों का दबाव कम होगा। करोड़ों लीटर डीजल बचेगा। बड़ा लक्ष्य पूरा करने के लिए डीएफसीसीआइ की टीम इसको फ्रेंडली भूमिका बढ़ाने में जुट चुकी है।

डीएफसी ट्रैक पर मालगाड़ियों से भरे ट्रकों की ढुलाई पर्यावरण संरक्षण के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। इस प्रयोग से न केवल लाखों गैलन डीजल की बचत होगी बल्कि ट्रकों व अन्य वाहनों के धुएं से निकलने वाले कार्बन का उत्सर्जन काफी कम हो जाएगा। आधुनिक तकनीक से वाहनों में इंजनों का स्तर अवश्य उन्नत हुआ है, मगर अभी भी ऐसे लाखों वाहन हैं, जो कच्चा धुंआ फेंक रहे हैं। इससे वातावरण में कार्बन मोनोक्साइड जैसी विषैली गैसें भी घुल रही हैं। -डा. डी साहा, पूर्व अधिकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

इनपुट: महेश कुमार वैद्य | जागरण इन्फो

तत्काल सुनवाई में सिर्फ वरिष्ठ वकीलों को ही नहीं मिले प्राथमिकता

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तत्काल सुनवाई के लिए, मामलों का पीठ के समक्ष सीधे उल्लेख करने के बजाय शीर्ष अदालत के अधिकारियों के सामने ऐसा करने की व्यवस्था बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वरिष्ठ वकीलों को उनके कनिष्ठ सहयोगियों की तुलना में 'विशेष प्राथमिकता' नहीं दी जाए।

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण द्वारा उक्त विषय उठाने पर यह बात कही। पीठ ने कहा कि हम वरिष्ठ वकीलों को विशेष प्राथमिकता देकर कनिष्ठ वकीलों को अवसरों से वंचित नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यह प्रणाली बनाई गई जहां सभी लोग रजिस्ट्रार के समक्ष मामले को रख सकें। पहले रजिस्ट्रार के पास जाएं। मंजूरी नहीं मिलती है तो पीठ के समक्ष उल्लेख करने का अधिकार मिल जाता है।

पर्यावरण संरक्षण व विकास में संतुलन जरूरी है : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नैनीताल

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून-दिल्ली हाईवे चौड़ीकरण में करीब ढाई हजार साल यानी साखू के पेड़ काटने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में संतुलन जरूरी है। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) से पूछा है कि साल के इन पेड़ों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता से भी पूछा कि ढाई हजार पेड़ काटने से देहरादून की क्षति कैसे होगी ओर इस क्षति की भरपाई क्या पौधरोपण करके नहीं की जा सकती। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी समाजसेवी रीना पाल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एनएचएआइ की ओर से भारतीय वन्य जीव संस्थान से कराए गए सर्वे की रिपोर्ट की कापी पेश की गई। एनएचएआइ का कहना है कि हाईवे के तीन किमी दायरे में वन्य जीवों की सुरक्षा व आवाजाही के लिए अंडरपास बनाया जा रहा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि राजाजी नेशनल पार्क स्थित मोहंड क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे के चौड़ीकरण के लिए ढाई हजार पेड़ों का कटान किया जा रहा है।

विकास के लिए अब हरियाली पर कम चलेगी आरी

शोभित श्रीवास्तव, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में अब विकास कार्यों के लिए हरे-भरे पेड़ों पर कम आरी चलेगी। योगी सरकार पेड़ों की कटान के लिए जल्द नई नीति बनाने जा रही है। विकास में बाधा बनने वाले पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें 10 किलोमीटर के दायरे में दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाएगा। इसके तहत 30 सेंटीमीटर व्यास तक के पेड़ एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाए जाएंगे। पेड़ों का प्रत्यारोपण मैनुअल व मैकेनिकल दोनों तरह से किया जाएगा।

विकास कार्यों के लिए चयनित भूमि पर पेड़ों की कटान के लिए नोडल अफसर से इजाजत लेनी पड़ती है। अभी तक एक हेक्टेयर से कम भूमि पर यदि कोई विकास कार्य हो रहा है तो वहां जितने पेड़ कटते हैं, उसका 10 गुना पौधारोपण करना होता है। यानी एक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाने के लिए पैसा वन विभाग में जमा करना होता है। यदि आरक्षित वन भूमि है तो उतनी ही भूमि दूसरे स्थान पर देनी होती है। साथ ही उसमें प्रति हेक्टेयर न्यूनतम एक हजार पौधे लगाने होते हैं। चूंकि बड़े पेड़ कटते हैं और उसके एवज में छोटे पौधे लगते हैं तो इसका असर पर्यावरण पर पड़ता है। अब सरकार बड़े पेड़ों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करेगी। नई नीति का जो मसौदा तैयार किया जा रहा है, उसके तहत पेड़ों को दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपण करने के बाद संबंधित विभाग को छह माह से लेकर एक साल तक उसकी देखभाल भी करनी होगी। कोशिश यह होगी कि 80 फीसद पेड़ प्रत्यारोपित कर दिए जाएं और केवल 20 फीसद पेड़ों को ही काटने की इजाजत दी जाए। सरकार ने उत्तर प्रदेश वन निगम को इसकी नोडल एजेंसी बनाया है।

विकास कार्यों के लिए काफी संख्या में पेड़ों की कटान हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार नई नीति बना रही है। नई नीति में पुराने पेड़ों को काटने की बजाय दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने पर फोकस किया जाएगा। इससे विकास कार्य तेज गति से होंगे और पेड़ भी कम संख्या में कटेंगे।
-मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

दिव्यांग किशोरी ने आवाज से पहचाना दुष्कर्मी, आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, अमरोहा

चार साल पहले दिव्यांग (नेत्रों से) किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसके ऊपर 52 हजार रुपये जुर्माना डाला गया। पीड़िता ने आरोपित की पहचान आवाज से की थी।

घटना उप्र के अमरोहा के एक गांव की थी। यहां पर रहने वाले किसान की बेटी जन्म से ही नेत्रों से दिव्यांग है। 22 अगस्त, 2017 की दोपहर लगभग एक बजे 15 वर्षीय किशोरी पड़ोसी के घर जा रही थी। रास्ते में उसे गांव का राहुल मिला। चूंकि राहुल उसके घर आता-जाता था, लिहाजा, आवाज से किशोरी ने उसे पहचान लिया। किशोरी को वह पड़ोसी के घर छोड़ने के बहाने अपने साथ गांव से सटे ट्यूबवेल पर ले गया। वहां ले जाकर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता किसी तरह घर पहुंची तथा स्वजन को बताया। इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हलांकि वह जमानत पर जेल से छूट गया था।

यह मामला पाक्सो एक्ट की अदालत में चल रहा था। अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की थी। अदालत ने राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। फैसले से अन्य पीड़िताओं को भी जल्द से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जागी है।

मासूम से छेड़छाड़ पर उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़ : छेड़छाड़, आजीवन कारावास की सजा का भी सबब बन सकती है। सात साल की मासूम बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को प्रतापगढ़ की पाक्सो कोर्ट ने यही सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मंगलवार को सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। अभियुक्त रेवती रमण सिंह कौशांबी का निवासी है। विशेष न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। वादी मुकदमा ने उन्नाव कोतवाली में दो मार्च, 2017 को तहरीर दी थी कि उसके कार्यालय में कार्यरत अर्दली रेवती रमण उसकी सात वर्षीय पुत्री के साथ आवास पर छेड़खानी करता आ रहा है और किसी से नहीं बताने की धमकी भी देता था। अभियुक्त का तबादला प्रतापगढ़ होने पर मुकदमा भी उन्नाव से यहां ट्रांसफर कर दिया गया था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 12 अगस्त, 2021

मोह की समाप्ति के बाद ही सत्य के प्रति आकर्षण बढ़ता है

विपक्ष की नाकामी

इस पर हैरानी नहीं कि लोकसभा तय समय से दो दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष के रवैये को देखते हुए ऐसा कुछ होने के आसार पहले ही उभर आए थे। आखिरकार जैसी आशंका थी, वैसा ही हुआ। लोकसभा की तरह राज्यसभा भी समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के इस मानसून सत्र में राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मसलों पर चर्चा होने के साथ करीब 30 विधेयक पारित होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों ही सदनों में उम्मीद से कहीं कम काम हुआ। विपक्ष इस पर अपनी पीठ थपथपा सकता है कि उसने संसद में ज्यादातर समय हंगामा किया और सरकार के एजेंडे को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन यह शाबासी नहीं, शर्मिंदगी का विषय है। इसलिए और भी, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने संसद में जब-तब ओछी हरकतें भी कीं। लज्जा की बात यह है कि उन्हें अपने अमर्यादित आचरण पर अफसोस भी नहीं। कुछ सांसद तो ऐसे हैं, जो अपनी ओछी हरकतों को जायज ठहरा रहे हैं। इस तरह का रवैया तो संसद की गरिमा को धूल-धूसरित करने का ही काम करेगा। वास्तव में विपक्ष ने संसद को लगातार बाधित करके न केवल अपना, बल्कि देश का नुकसान किया। उसने संसद के मानसून सत्र को बाधित कर एक तरह से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। उसके पास विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने, उसे जवाबदेह ठहराने के साथ विभिन्न विधेयकों में संशोधन कराने का मौका था, लेकिन उसने यह सब गंवा दिया।

क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण देश के लिए जरूरी समझे जाने वाले कामों में बाधा खड़ी हो? आखिर विपक्षी दल किस मुंह से यह दावा कर सकते हैं कि वे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जिम्मेदार हैं? यह तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ही है कि विपक्ष ने जिन मुद्दों पर चर्चा जरूरी बताई, उन पर बहस की नौबत ही नहीं आने दी। क्या विपक्ष इस पर विचार करेगा कि उसे हंगामा करके हासिल क्या हुआ, क्योंकि देश की जनता को तो यही संदेश गया है कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने अधिकतर समय हंगामा करने के अलावा और कुछ नहीं किया। निःसंदेह संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि वह विपक्ष का हुक्म बजाए। विपक्ष को सत्तापक्ष के रवैये से असहमत होने का अधिकार है, लेकिन वह सरकार को अपने मन मुताबिक चलने के लिए विवश नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से मानसून सत्र में वह यही करने पर आमादा दिखा। यह लोकतांत्रिक रवैया नहीं।

सतर्कता जरूरी

सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कोरोना के मामले मे पंजाब में यही हो रहा है। महामारी की पहली और दूसरी लहर में यही हुआ, इसलिए अब तो संभलना और सबक लेना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताते रहे हैं और साथ ही उनका यह भी अनुमान रहा है कि अगर पूरी सतर्कता बरती गई तो इसका असर ज्यादा नहीं होगा। दूसरी ओर, अगर ढील या लापरवाही बरती गई तो यह अगस्त के अंत या सितंबर तक भी दस्तक दे सकती है। दूसरी लहर थोड़ी शांत पड़ने के बाद ज्यों-ज्यों जनजीवन सामान्य होने लगा, लापरवाही फिर बढ़ने लगी है। मास्क का प्रयोग, हाथ सैनिटाइज करना या बार-बार धोना, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना कम हो गया है। इसका चिंताजनक नतीजा है कि कोरोना संक्रमण के केस पिछले कुछ समय में धीरे-धीरे बढ़ने लगे हैं। यह आवश्यक है कि जनजीवन पूरी तरह पटरी पर लौटे, इसके लिए सरकार की ओर से पाबंदियां हटाई जा रही हैं। शिक्षण संस्थान, बाजार, माल्स, सिनेमाघर इत्यादि फिर खुलने लगे हैं। इसी के साथ आम जन की जिम्मेवारी अपने व दूसरों के प्रति बढ़ जाती है। जिम्मेवारी है कोविड से बचाव के नियमों के पालन की। क्योंकि 18 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन का टीका लग चुका है इसलिए तीसरी लहर में ज्यादा खतरा बच्चों के लिए माना जा रहा है। इसी वजह से सरकार ने स्कूलों में रैपिड टेस्ट शुरू किए हैं। चिंता की बात है कि लुधियाना के स्कूल में कुछ बच्चे पाजिटिव पाए गए हैं। पहली लहर थमने के बाद जब आंशिक तौर पर स्कूल खुले थे तब भी राज्य के अनेक स्कूलों में एकाएक बच्चे व शिक्षक पाजिटिव पाए जाने लगे थे। इसलिए इस बार बहुत सजगता बरतने की जरूरत है। बच्चों को पूरी एहतियात के साथ ही स्कूल भेजना होगा। स्कूलों को भी चाहिए कि वे कोरोना प्रोटोकाल का पालन पूर्णतः करें। केवल स्कूलों में ही नहीं, सभी जगह नियमों का पालन किया जाना चाहिए। पंजाब से अनेक लोग हिमाचल के मंदिरों में जाते हैं, लेकिन वहां प्रवेश के लिए वैक्सीन के दोनों टीके लगे होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर भी कई लोग बिना इस प्रमाण पत्र के जा रहे हैं और हिमाचल-पंजाब की सीमा पर रोक दिए जा रहे हैं। इससे उन्हें ही परेशानी हो रही है। सोमवार को सीमा पर रोके गए कई लोगों ने हंगामा भी किया। ऐसा करके वे और दिक्कत पैदा करने का ही काम कर रहे हैं।

कोरोना के बाद की वैश्विक अर्थव्यवस्था

भरत झुनझुनवाला

कोविड उपरांत दुनिया में वस्तुओं के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण होगा, जबकि सूचना का वैश्वीकरण बढ़ेगा। इसलिए हमें भी खुद को उसी अनुसार ढालना होगा

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आइएमएफ द्वारा प्रकाशित फाइनेंस एंड डेवलपमेंट पत्रिका में यूरेशिया ग्रुप के प्रमुख इयान ब्रेमर का कहना है कि कोरोना संकट के बाद वैश्वीकरण की मुहिम को झटका लगेगा। कोरोना के बाद दुनिया में वैश्वीकरण के बजाय राष्ट्रीयकरण अधिक होगा। इसे उन्होंने 'डी ग्लोबलाइजेशन' की संज्ञा दी है। अब तक विचार था कि छोटी बचत के लिए भी एक देश से दूसरे देश माल को ले जाना लाभप्रद होता है। कोरोना संकट ने ऐसे व्यापार को कठिन बना दिया है। यदि किसी देश में संकट पैदा हो गया और उस देश से माल की आपूर्ति बंद हो गई तो खरीदने वाले देश को कच्चा माल मिलना बंद हो जाता है। जैसे भारत के दवा उद्योग द्वारा चीन से कच्चा माल खरीदा जाता है। इस कच्चे माल को भारत के उद्यमी स्वयं भी बना सकते हैं, लेकिन चीन से खरीदना उन्हें सस्ता पड़ता है। ब्रेमर का कहना है कि आने वाले समय में उद्यमी अपने देश में ही कच्चा माल बनाना पसंद करेंगे, जिससे उनका धंधा दूसरे देश के संकट के कारण बाधित न हो। इसके विपरीत विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ प्रमुख ओकोंजो इवेला ने कहा है कि कोरोना के समय विश्व व्यापार में जो अवरोध उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें दूर कर विश्व व्यापार को पुनः पटरी पर लाना चाहिए। उनका उद्देश्य ही वैश्विक व्यापार को बढ़ाना है। इसके बरक्स ब्रेमर का यह कहना ज्यादा सही लगता है कि उत्पादन का राष्ट्रीयकरण बढ़ेगा। आइएमएफ की इसी पत्रिका में ही मैकेंजी ग्लोबल के प्रमुख जेम्स मनीइका ने कहा है कि माल के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण होगा, जबकि सूचना का वैश्वीकरण और तेजी से होगा। यदि किसी देश में कोरोना संक्रमण बढ़ जाता है तो उससे माल की आवाजाही में अवरोध पैदा हो सकता है, लेकिन डाटा का व्यापार सुचारु रूप से चलता रहेगा। उनका यह आकलन सही प्रतीत होता है।

भविष्य में माल के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण होगा, जबकि आनलाइन शिक्षा, डाक्टर से आनलाइन परामर्श, साफ्टवेयर जैसी सेवाओं का विश्व व्यापार बढ़ेगा। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार को 400 अरब डालर की वस्तुओं के निर्यात के अपने लक्ष्य पर पुनर्विचार करना चाहिए। यदि वैश्विक स्तर पर माल के व्यापार का राष्ट्रीयकरण होने की संभावना है तो हमें निर्यात केंद्रित बनने की तरफ बढ़ने से बचना चाहिए। यह सही है कि हालिया दौर में हमारे निर्यात कोरोना पूर्व स्तर पर आ गए हैं, लेकिन इसमें भारी वृद्धि की संभावनाएं नहीं दिखतीं। भारत के पास शिक्षित लोगों की भारी उपलब्धता है। माल के उत्पादन में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना कठिन होता जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण आटोमेटिक मशीनों का उपयोग बढ़ेगा। कई उद्योगों ने अपने श्रमिकों के लिए फैक्ट्रियों में ही रहने और भोजन की व्यवस्था की है। श्रम का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। इसलिए यदि भारत सरकार के मंतव्य के अनुसार निर्यात बढ़ भी जाएं तो भी उससे नागरिकों को पर्याप्त रूप से रोजगार मिलना कठिन ही रहेगा। इसके विपरीत युवाओं को सेवाओं के निर्यात में उन्मुख करना कहीं ज्यादा आसान है। इससे सेवाओं का निर्यात भी बढ़ेगा और कोरोना का खतरा भी टलेगा। ऐसे में सरकार को वर्तमान डब्ल्यूटीओ संधि को निरस्त कर नई संधि के लिए वैश्विक मुहिम चलानी चाहिए।

अवधेश राजपूत

वर्तमान में जिन वस्तुओं के व्यापार का संकुचन हो रहा है, वे डब्ल्यूटीओ के दायरे में हैं और जिन सेवाओं का विस्तार होने की संभावना है, वे डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर हैं। इसलिए सरकार को विश्व समुदाय के समक्ष कहना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ की वर्तमान संधि अप्रासंगिक होती जा रही है। इसके स्थान पर सेवाओं के निर्यात की एक नई संधि की जानी चाहिए।

डब्ल्यूटीओ संधि लागू होने से पहले भारत समेत कई देशों में प्रक्रिया यानी 'प्रोसेस' पेटेंट की व्यवस्था थी। आविष्कार करने वाले व्यक्ति को किसी माल या 'प्रोडक्ट' पर पेटेंट नहीं दिया जाता था। आविष्कार करने वाले को केवल उस विशेष प्रोसेस का पेटेंट दिया जाता था, जिससे उसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया हो। जैसे फाइजर कंपनी ने कोविड का टीका बनाया। पूर्व के हमारे प्रोसेस पेटेंट के अंतर्गत भारत की कोई भी कंपनी किसी दूसरे प्रोसेस से ऐसा टीका बनाने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन डब्ल्यूटीओ संधि के अंतर्गत उस टीके पर ही पेटेंट दे दिया गया। यानी कोविड के ऐसे टीके को किसी दूसरे प्रोसेस से बनाने की छूट अन्य लोगों को नहीं रह गई। परिणामस्वरूप टीका उपलब्ध होने में देर हुई। इसकी कीमत मानवता को चुकानी पड़ी। इसलिए समय आ गया है कि हम डब्ल्यूटीओ संधि के अंतर्गत प्रोडक्ट पेटेंट व्यवस्था को निरस्त करने की मांग उठाएं। अपने देश में जिन दवाओं के उत्पादन का पिछली सदी के आठवें-नौवें दशक में जो विस्तार हुआ, वह प्रोसेस पेटेंट के कारण ही संभव हो सका था। दूसरी कंपनियों द्वारा खोजी गई दवाओं को भारतीय उद्यमियों ने दूसरे प्रोसेस से बनाकर विश्व बाजार में सस्ते में उपलब्ध कराया। इसलिए डब्ल्यूटीओ की मौजूदा व्यवस्था पर पुनर्विचार आवश्यक है।

सेवाओं के निर्यात में बन रही संभावनाओं को भुनाने के लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे। अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अंग्रेजी के विरोध में तर्क दिया जाता है कि उससे हमारी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। पहले सिंधु घाटी की भाषा थी, जिसे अभी तक पढ़ना संभव नहीं हो पाया। उसके बाद प्राकृत भाषा आई और फिर देवनागरी, लेकिन हमारी संस्कृति की निरंतरता बनी रही। इसके अतिरिक्त यदि हमें अपनी संस्कृति का वैश्वीकरण करना है तो अंग्रेजी अपनानी ही होगी। आज पश्चिमी देशों ने लैटिन भाषा को पकड़ नहीं रखा है। वे अंग्रेजी में आगे बढ़ गए और लैटिन में उपलब्ध संस्कृति को भी संजोये हुए हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी संस्कृति को अंग्रेजी भाषा में सही रूप में प्रस्तुत करें, जिससे हम अंग्रेजी आधारित सेवाओं का भारी मात्रा में विस्तार कर सकें और साथ ही अपनी संस्कृति की रक्षा भी कर सकें। बेहतर हो कि सरकार 400 अरब डालर के माल निर्यात का लक्ष्य बनाने के स्थान पर 4,000 अरब डालर सेवाओं के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित करे। कोरोना के बाद की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयारी अभी से करनी चाहिए।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

सुरक्षा परिषद में नए भारत की मौजूदगी

पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की उच्चस्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही कहा कि महासागर दुनिया की साझा विरासत और समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जीवनरेखा हैं। उन्होंने समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत पांच सिद्धांत भी पेश किए। पहला, हमें वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना चाहिए। दूसरा, समुद्री विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर किया जाना चाहिए। तीसरा, वैश्विक समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं और आतंकियों द्वारा उत्पन्न समुद्री खतरों का एक साथ मिलकर सामना करना चाहिए। चौथा, समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए और पांचवां समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना चाहिए।

यह पहली बार है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की कमान संभाली है। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत को एक अगस्त से महीने भर के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान मिली है। इस दौरान वह सुरक्षा परिषद में तीन बड़े मुद्दों-समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और आतंकवाद रोकथाम के संबंध में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। देश के लिए यह पल और भी गर्वित करने वाला बन जाता है, क्योंकि इसी साल हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में स्वतंत्रता दिवस की महत्ता बढ़ना स्वाभाविक है। इसी पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के दो साल भी पूरे हुए हैं। साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं वापस लौट रही हैं और तालिबानी प्रभाव फिर बढ़ता दिख रहा है। ऐसे समय में दुनिया की निगाहें भारत पर हैं। वैसे समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर भारत का सोच दुनिया के सामने जगजाहिर है। समुद्री सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वहीं भारत शांतिरक्षकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। साथ ही आतंकवाद की रोकथाम के प्रयासों पर भी लगातार बल देता रहा है। भारत

ऋतुराज सिन्हा

जब देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तब विश्व के सबसे ताकतवर मंच की अध्यक्षता गौरव को और बढ़ा देती है

मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की धमक। फाइल

हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। इसलिए अध्यक्षता के नाते भी भारत पहले की तरह ही सुरक्षा परिषद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को लेकर अपने रुख पर कायम रहेगा। वास्तव में आज नए भारत का नया नेतृत्व सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि दुनिया का भी नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसने दुनिया को यह भी अहसास करा दिया है कि राष्ट्रीय हितों से कभी कोई समझौता नहीं होगा। आज भारत का युवा क्षमता, तकनीक कौशल, विशेषज्ञता और दृढ़संकल्प से भरा हुआ है। वह जो ठान लेता है, उसे पूरा करके ही दम लेता है। ऐसे में दुनिया को भारत के अनुकूल नीति और सोच बनाना होगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को भले स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है, लेकिन अस्थायी सदस्य के तौर पर भी भारत की धमक दुनिया महसूस कर रही है। इस संस्था के गठन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच शांति, सुरक्षा और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना था। संयुक्त राष्ट्र के छह अहम अंगों में सुरक्षा परिषद भी एक है। दुनिया भर में शांति स्थापित करने में इस संस्था की भूमिका अहम होती है। इसमें अब कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से पांच स्थायी सदस्य के तौर पर-अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं, जिनके पास विशिष्ट वीटो पावर है जबकि शेष 10 सदस्यों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। पांच सीटें अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए, एक पूर्वी यूरोपीय देशों, दो लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों और दो पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य देशों को दी जाती हैं। हर दो साल पर पांच नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। किसी भी देश को सदस्य तब बनाया जाता है जब दो-तिहाई देश उसके पक्ष में मतदान करें।

बीते वर्ष जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता ने उसे नई दिशा दी थी। अचानक आई आपदा से निपटने के लिए किए गए उपायों से देश में कोविड का शुरुआती प्रभाव कम पड़ा। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग का आइडिया दुनिया को दिया था। उनके दूरगामी सोच का ही परिणाम था कि भारत को दो साल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सबसे अहम सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर आठवीं बार चुना गया। कोविड के दौर में इस तरह की जीत भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति को दर्शाने वाली रही। इसके लिए 192 देशों में से 184 देशों ने भारत के पक्ष में मतदान किया। इस जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच 'स' हैं, जिसने भारत की समग्र विदेश नीति को नई दिशा भी दी है। ये पांच 'स' हैं-सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और सार्वभौमिक समृद्धि। हालांकि सिर्फ कूटनीतिक अभियान ही नहीं, कोविड काल में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

देखा जाए तो अभी तकनीकी आधार पर भारत को अपने दो साल के कार्यकाल में दो बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का मौका मिलेगा, क्योंकि नियम के मुताबिक अंग्रेजी नाम के आधार पर सदस्य देशों को हर महीने अध्यक्षता का मौका मिलता है। इसमें दोराय नहीं कि मोदी सरकार इस मंच का देश और दुनिया के हित में भरपूर उपयोग करेगी। कुल मिलाकर यह भारत के लिए प्रफुल्लित होने का अवसर है।

(लेखक पब्लिक पालिसी के अध्येता हैं)

response@jagran.com

कर्मशील स्वभाव

अपने कार्य में व्यस्त रहने वाले को चिंता नहीं सताती कि कुछ व्यक्ति सदा उसमें बुराइयां और उसके कार्य में त्रुटियां तलाशते हैं। वह इस नकारात्मक प्रवृत्ति में उलझेगा तो उसके कार्य अवरुद्ध होंगे। कर्मवीर को ज्ञान होता है कि जिस अनुपात में कार्य संपादित किए जाएंगे, उसी अनुपात में दोषारोपण, छिद्रान्वेषण और शत्रुता बढ़ सकती है। सत्यनिष्ठा और सावधानी से निष्पादित कार्य में भी भूलचूक या कोई त्रुटि रह सकती है। अहम यह है कि पहली भूल से सबक लेते हुए उसकी पुनरावृत्ति न हो। एक ही भूल बार-बार घटित होने का अर्थ है, कार्य निष्ठा से नहीं किया गया। कार्य में जितनी लगन और निष्ठा होगी, परिणाम उतना ही संवरा, निखरा, परिपूर्ण और जनप्रिय होगा।

भूल वह है, जो अनायास या अनचाहे हो जाती है। वहीं अपराध सायास या योजनाबद्ध विधि से अंजाम दिया जाता है। दोनों की परिणति में वही अंतर है, जो मंदिर या श्मशान से निकलते धुएं की प्रकृति में। आपरेशन के दौरान डाक्टर जानबूझकर कैंची गलत नहीं चलाएगा। चूंकि डाक्टर भी मनुष्य है, लिहाजा उससे भी गलती हो सकती है।

कार्य के लिए समर्पित कर्मवीर कदाचित अभद्र या आपत्तिजनक आचरण कर बैठे तो वह आत्मग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में सुलगने लगेगा। वह अपने अनुचित व्यवहार को उचित ठहराने की चेष्टा कभी नहीं करेगा। उसे तो सुधार से स्वयं को बेहतर बनाते रहना है। जिसके प्रति उससे अन्याय हुआ, उसके समक्ष करुणा, विनय और नम्रता से प्रस्तुत होगा। प्राकृतिक विधान के अनुकूल उसका मृदु, सुलहपरक और सहयोगी स्वभाव उसे अनेक भावी दुविधाओं और कठिनाइयों से सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसके विपरीत अकर्मण्य, निर्लज्ज व्यक्ति तब तक अपने कृत्य को सही ठहराएगा जब तक वह चौतरफा घिर नहीं जाता। इस प्रक्रिया में असंतुष्ट और अशांत रहना उसकी नियति बन जाती है।

हरीश बड़थ्वाल

सजगता से ही संवरेगा बचपन

डा. मोनिका शर्मा

स्मार्ट गैजेट्स के सार्थक इस्तेमाल को लेकर नई पीढ़ी को अनुशासन का पाठ पढ़ाना जरूरी है

पिछले दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर में आनलाइन गेमिंग में 40 हजार रुपये हारने पर 13 साल के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। चिंतनीय है कि बच्चे आभासी खेलों के जाल में फंसकर कभी आत्महत्या कर रहे हैं तो कभी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं तो कभी अपराध की राह पकड़ ले रहे हैं। महानगरों से लेकर गांवों-कस्बों तक आभासी खेल बच्चों की असल जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। व्यावहारिक रूप से जिन चीजों का बच्चों के जीवन में कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए, वे उनके जीने-मरने की वजह बन रही हैं। ऐसी घटनाएं बच्चों की जिंदगी में स्मार्ट गैजेट्स, आनलाइन गेम्स और इंटरनेट की बढ़ती दखल के भी उदाहरण हैं।

वास्तविक तौर पर खेले जाने वाले खेल तो हमारी जिंदगी में हर तरह की सकारात्मकता लाते हैं, पर स्मार्ट गैजेट्स पर खेले जाने वाले आभासी खेल कई शारीरिक-मानसिक व्याधियों को न्योता दे रहे हैं। अवसाद और तनाव का कारण बन रहे हैं। ये हर उम्र के लोगों को अनदेखे-अनजाने चेहरों के जाल में फंसा रहे हैं। तकनीकी गैजेट्स इंसान की सहूलियत और संवाद के माध्यमों तक सीमित नहीं रहे हैं। इनके अजब-गजब इस्तेमाल की सनक ने नए खतरे पैदा कर दिए हैं। साइबर संसार की अनजान दुनिया बच्चों की समझ ही छीन रही है। समय बिताने के लिए मोबाइल पर खेले जाने वाले खेल जान देने या जीते जी समाज और खुद से कटकर जिंदगी को रीता करने का माध्यम बन गए हैं।

निःसंदेह ऐसी घटनाएं आनलाइन गेम्स और आभासी संसार के बढ़ते दखल के प्रति सचेत करती हैं। खासकर अभिभावकों के लिए यह गंभीरता से सोचने और गहराई से समझने का विषय बना गया है कि स्मार्ट गैजेट्स पर बच्चे मनोरंजन के नाम पर कैसे खेल खेल रहे हैं? उनका इस्तेमाल किन गतिविधियों के लिए कर रहे हैं? माता-पिता का सचेत होना जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बावजूद नए-नए खेल इंटरनेट की दुनिया में दस्तक देते रहते हैं। कोरोना काल में आनलाइन स्कूलिंग के चलते बच्चों का स्क्रीन का टाइम और बढ़ गया है। आपदा के दौर में यह चिंतनीय है कि बच्चे पूरा समय सिर्फ पढ़ाई को नहीं दे रहे हैं। नेशनल कमीशन फार प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट की रिपोर्ट के मुताबिक आनलाइन स्कूलिंग के दौर में बच्चे पढ़ाई के बजाय वर्चुअल दुनिया में ज्यादा ऊर्जा खपा रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों का चेतना जरूरी है। स्क्रीन की दुनिया में गुम बच्चों की जिंदगी में बड़ों का मार्गदर्शन और सार्थक संवाद आवश्यक है। आज के दौर में बच्चों को स्मार्ट गैजेट्स से दूर नहीं रखा जा सकता। ऐसे में अभिभावकों की सजगता बच्चों का जीवन सहेज सकती है। जरूरत और लत का अंतर बताते हुए स्मार्ट गैजेट्स के सार्थक इस्तेमाल को लेकर नई पीढ़ी को अनुशासन का पाठ पढ़ाना आवश्यक है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खिलाड़ियों को दें सुविधा

'खेल संस्कृति को संवारने का समय' शीर्षक से लिखे आलेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने कहा है कि भारत अगर भविष्य में ओलिंपिक में बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है तो इसके लिए देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। मालूम हो कि 1951 में पहले एशियाई खेलों में भारत 51 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा था। वहीं 1982 में नौवें एशियाई खेलों में भारत 57 पदक जीतकर पांचवें स्थान पर रहा था और अब टोक्यो ओलिंपिक में नीरज चोपड़ा ने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने सरकारों को देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति सोचने पर मजबूर कर दिया है। ओलिंपिक और अन्य खेलों में हमारे देश के खिलाड़ी मेहनत करके मेडल जीतते हैं। यह बताता है कि हमारे देश में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों की कमी नहीं है। कमी है तो सरकारों की सक्रियता की, जो खिलाड़ियों को आगे आने के लिए प्रेरित नहीं करती हैं या फिर उनका सहयोग नहीं करती हैं। कुछ संस्थाएं हैं तो, लेकिन पर्याप्त नहीं। कई तो युवाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण भी नहीं दे पा रही हैं। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को प्राइमरी स्कूलों से लेकर कालेज स्तर तक विद्यार्थियों का खेलों में भाग लेना अनिवार्य कर देना चाहिए। खेलों को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। इनमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के प्रति अगर सरकारें गंभीर होंगी तो हमारा देश हर खेल में नंबर वन बन जाएगा। इसके लिए प्रयास तुरंत शुरू करने होंगे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

चिंताजनक स्थिति

पाकिस्तान-बांग्लादेश के अभागे हिंदू नामक संपादकीय आलेख मे राजीव सचान ने खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों अथवा हिंदुओं की तेजी से घटती आबादी की पीड़ा को महसूस करते हुए उन्हें हिंदुस्तान में लाकर नागरिकता संशोधन बिल के तहत नागरिकता प्रदान कर मुख्यधारा में लाने की सिफारिश की है, ताकि उन देशों में मानसिक और शारीरिक अत्याचार से उन्हें महफूज रखा जा सके। यदि मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को देखा जाए तो केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, मलेशिया और अफगानिस्तान आदि में भी अल्पसंख्यकों यानी खासतौर पर वहां रहने वाले हिंदुओं का बुरा हाल है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को कट्टरपंथियों द्वारा जबरन बूचड़खानों में बदल दिया जा रहा है। उन देशों में इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार और कानून पर इतने हावी हैं कि वहां की सरकारें और कानून भी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचारों के लिए केवल खानापूर्ति ही करती नजर आती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटकर महज एक डेढ़ फीसद तक रह गई है। आए दिन वहां जबरन निकाह और घरों-मंदिरों अथवा पूजास्थलों को तोड़ने की खबरें आती ही रहती हैं। वहां की सरकारें महज खानापूर्ति के नाम पर कट्टरपंथियों के समक्ष मूकदर्शक बनी रहती हैं। यदि वहां की सरकारें मूकदर्शक न बनी रहें तो वहां इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। संवैधानिक धरातल पर देखें तो ये दोनों ही देश अपने धर्मनिरपेक्षता वादी रैवये को त्यागकर पूर्णतः इस्लामिक बन कर कट्टरता का ऐसा नंगा नाच कर रहे हैं कि वहां अल्पसंख्यकों की आबादी न के बराबर रह गई है। हालांकि इसी पीड़ा को महसूस करते हुए मौजूदा मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारत में अस्थाई तौर दूसरे देशों से आए या बहुत समय से अस्थाई तौर पर रह रहे बौद्ध, सिख, पारसी, हिंदू, जैन, ईसाइयों को बसाने की पहल की जा रही है, ताकि इन समुदाय के लोगों को देश की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ विपक्षी ताकतें इस पूरे प्रकरण को हिंदू मुस्लिम अलगाववाद के रूप मे देखती आ रही हैं जो कि बहुत ही भ्रमित, अफसोसजनक अथवा चिंताजनक स्थिति पैदा करने वाला रवैया कहा जा सकता है। विपक्षी दलों को यह रवैया छोड़कर मानवता को ध्यान में रखते हुए आचरण करना चाहिए।

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

... द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

2015 में पंचायती राज मंत्रालय में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) शुरू करते हुए 14वें और 15वें वित्त आयोग की ग्राम विकास अनुदान राशि को बढ़ाने की अनुशंसा पर भी अमल किया गया था।

आजकल

ओबीसी विधेयक पर सदन में शांति के मायने

संसद के मानसून सत्र में बुधवार को लोकसभा अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बार मानसून सत्र में कई बिल पारित हुए, लेकिन दुर्भाग्य से लोकसभा और राज्यसभा में पारित किसी भी बिल पर चर्चा नहीं हो सकी। केवल 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को अधिकार देने के संबंध में था, उस पर ही चर्चा हो सकी। चूंकि राजनीतिक रूप से यह विपक्षी दलों के लिए भी महत्वपूर्ण था तो वे इस विधेयक पर सदन चलाने के लिए सहमत हो गए, लेकिन अन्य अहम मसलों पर उसका असहयोग और हंगामा कई सवाल खड़े करने वाला रहा

गौरव कुमार
लोक नीति विश्लेषक

संसद के मानसून सत्र का समापन हो चुका है। मंगलवार को भारतीय संसदीय इतिहास की एक मिसाल देने वाली घटना हुई जिसके तहत लोकसभा का एकमात्र कार्य बिना किसी हंगामे के संपन्न हुआ। जबकि पूरे सत्र के दौरान कोई भी विधायी कार्य हंगामे के बिना संपन्न नहीं हुआ। सदन को विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित करते रहने की मजबूरी ने संसद के करोड़ों रुपये खर्च कराए और इस दौरान कोई उत्पादक कार्य नहीं हो सका। साथ ही इससे संसदीय परंपरा के प्रति एक नकारात्मक छवि का निर्माण भी हुआ। इस सत्र को कई मायने में गैर उत्पादक कहा जा सकता है। हालांकि विपक्षी हंगामे के कारणों को समझते हुए सरकार ने चर्चा के लिए पर्याप्त अवसर दिया, ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके।

यह बड़ी गंभीर स्थिति है जहां विधायी कार्य को बिना विस्तृत और परिपक्व चर्चा के साथ संपन्न करना पड़ा। विपक्ष लगातार पेगासस, कृषि कानून विरोधी आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दे पर कामकाज को बाधित करता रहा। किंतु जब मंगलवार को सूचीबद्ध 127वें संविधान संशोधन विधेयक की बारी आई तो सारे विपक्ष की जबान बंद हो गई और इस विधायी कार्य के दौरान सभी सदस्य ने अपनी सीट पर बैठ कर स्वस्थ परिचर्चा में भाग लिया। कचोटने वाली बात यह रही कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। यहां यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी करते हुए ओबीसी मुद्दे पर विपक्ष सरकार के पक्ष में आ गया।

सबसे प्रमुख बात यह है कि जैसे ही बात ओबीसी मुद्दे की आती है, सबके कान खड़े हो जाते हैं। सभी इस मुद्दे पर अपने वोट बैंक के आगे मजबूर हो जाते हैं। इस बार भी यही हुआ। विपक्षी पार्टियों का यह व्यवहार देश, समाज और संसदीय हित के अनुकूल नहीं लगता। यदि उन्हें सदन में हंगामा करना था, सरकार के विधायी कार्य को रोकना था तो ओबीसी बिल के दौरान भी यही करते, लेकिन उन्हें इस हित की चिंता नहीं, बल्कि अपने वोट बैंक की चिंता है।

इन तथ्यों के आलोक में देखा जाए तो ओबीसी के हित में बड़े और प्रभावी कदम उठाने में कांग्रेस की सरकार विफल रही है या अधिक रुचि नहीं दिखाई। सदन में दिखावे के लिए इस बिल के समर्थन में आना अपने आप में हास्यास्पद है। हालांकि यह सुखद है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि कम से कम समाज के किसी भी वर्ग के हित के लिए विपक्ष सरकार के सहयोग में खड़ा हुआ और संसदीय परंपरा के आदर्शों का सम्मान किया।

इसका एक अन्य पहलू भी है। सदन को बाधित करते हुए विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहा था, वे जरूरी थे, उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इसके लिए सदन की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करना और यह जताना कि वे इस मुद्दे पर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हास्यास्पद था। लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को उसके कुछ संसदीय अधिकार मिले हुए हैं। वे संसद में प्रश्नों के माध्यम से या महत्वपूर्ण विषय की पूर्व सूचना सभापति या अध्यक्ष को देकर चर्चा की मांग कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष के सांसदों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वास्तव में उनका मकसद ऐसा था ही नहीं। उनका मकसद जनता के बीच स्वयं को इस रूप में दिखाना था कि वे कितनी गंभीरता से देश के मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार इस पर चर्चा नहीं चाहती है। वे यह भूल जाते हैं कि जनता इन व्यवहारों को समझ रही है।

जहां तक इस संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता का प्रश्न है, तो वास्तव में देश को इसकी जरूरत थी और सरकार ने इसे महसूस किया, तभी इसे इस सत्र में लाया गया। दरअसल हमारा देश विविधताओं से भरा है। हर राज्य की अलग-अलग आर्थिक सामाजिक स्थिति है। वहां एक केंद्रीकृत व्यवस्था कारगर या प्रभावी नहीं होती है। इसलिए राज्य को इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि उनके प्रदेश की किन जातियों को किस वर्ग में रखा जाए और किनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में कानून की अस्पष्टता के कारण सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि कानून बनाकर इस अस्पष्टता को दूर करे और इसी उद्देश्य से यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। आज लगभग सभी प्रदेश में जातियों की श्रेणी का निर्धारण गंभीर समस्या है। इस विधेयक के रूप में इन समस्याओं की जड़ को खत्म करने की पहल की गई है जो प्रशंसनीय है। इस विधेयक के लोकसभा में आते ही विपक्ष ने इसे अपना हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता की नजर में यह हथियार काम नहीं आया और उन्हीं पर इसका उलटा वार हो गया। जनता के मन में यह स्वाभाविक प्रश्न है कि आखिर इस प्रकार के दिखावे की राजनीति क्यों? वर्तमान में जो विपक्ष में हैं, वास्तव में यदि उनकी पार्टी सही मायने में ओबीसी की हितैषी होती तो पिछड़े वर्गों की तमाम सामाजिक, आर्थिक समस्याएं खत्म हो गई होतीं। लेकिन इन समस्याओं को बरकरार रखकर इसे मुद्दा बनाया जाता रहा, ताकि इनकी आड़ में वोट का कारोबार हो सके। अब जब केंद्र सरकार तमाम ऐसी पहलें कर चुकी है जिसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कहा जाएगा, उस पर श्रेय लेने या दिखावा करने की होड़ क्यों है? क्या ओबीसी मुद्दा एकमात्र राजनीतिक हथियार रह गया है या इसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश है?

बात चाहे जो हो, इतना तय है कि देश को अब इन मुद्दों की जरूरत नहीं है। अब देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अब पक्ष और विपक्ष दोनों को पारंपरिक मुद्दों से आगे बढ़ कर विकसित श्रेणी के मुद्दों की तलाश करनी चाहिए और उस पर वोट बैंक की राजनीति के विषय में खुद को और जनता को तैयार करना चाहिए।

संसद का पूरा मानसून सत्र विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ गया जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। फाइल

विपक्ष के आचरण पर विचार करे देश

डा. गौरीशंकर राजहंस
पूर्व सांसद एवं पूर्व राजदूत

संसद का मानसून सत्र भले ही खत्म हो गया हो और बुधवार को उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों ने हंगामा करके संसद की सामान्य कार्यवाही को व्यापक तौर पर बाधित किया। विपक्ष के इस तरह के बर्ताव से तंग आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के नेता जानबूझकर हंगामा करके संसद नहीं चलने दे रहे। मालूम हो कि पिछले माह मानसून सत्र के आरंभ से ही संसद के दोनों सदनों में विपक्षी नेता निरंतर हंगामा करते रहे हैं। संसद में विपक्षी दलों की गतिविधियों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरह से तृणमूल के एक सांसद ने संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी के हाथ से कागज छीनकर उसे फाड़ डाला, वह एक तरह से जनता का अपमान था। संसद में कागज फाड़ना और उसके टुकड़े हवा में लहराना तथा विधेयकों को पारित किए जाने के तौर तरीके पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना संविधान, संसद और जनता का अपमान है। चूंकि लोकतंत्र में जनता ही सांसदों को चुनती है, लिहाजा जनसरोकारी मामलों को प्रधानता मिलनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने तृणमूल के एक नेता के इस बयान पर भी नाराजगी जताई जिन्होंने कहा कि इस हो-हल्ले के दौरान जो भी बिल पास किए गए, वे एक तरह से चाट-पापड़ी खाने की तरह से पास किए गए हैं।

भाजपा संसदीय दल की बैठक में अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा आरक्षण कोटा योजना में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और उच्च वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संसदीय दल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की इस घोषणा का ताली बजाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले से मजबूत हुई है और कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद इसमें सुधार की गति तेजी से बढ़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के अपने उच्चतम शिखर पर है। इतना ही नहीं, हाल में जीएसटी संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के सशक्तीकरण को प्राथमिकता दे रही है और इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देशभर में लाखों परिवारों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। यह राशन आगामी दिवाली तक दिया जाएगा।

कल ही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किए गए संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में प्रायः प्रतिदिन हंगामा हुआ। राज्यसभा में तो सभापति द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद विपक्ष ने अपना रवैया नहीं बदला। वित्त मंत्री सीतारमण को तो यहां तक कहना पड़ा कि विपक्ष का हंगामा एक हिंसक प्रदर्शन की तरह है।

इस बार का संसद का मानसून सत्र बेहद हंगामेदार रहा। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा जिस दिन सदन में हंगामा नहीं हुआ हो। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के बार बार अनुरोध करने के बावजूद विपक्षी दलों के नेताओं ने एक दिन भी सदन चलाने में सहयोग नहीं किया, बल्कि निरंतर व्यवधान पैदा करते रहे। हां, इस लिहाज से मंगलवार का दिन भी ऐतिहासिक ही कहा जा सकता है, जब सरकार द्वारा प्रस्तुत ओबीसी विधेयक पर विपक्ष ने भी अपनी शत प्रतिशत सहमति व्यक्त की। इस एक दिन के मामले को छोड़ दें तो शेष दिन जिस प्रकार सदन में निरंतर हंगामा होता रहा, उससे लगता है कि देर-सबेर इस देश में लोकतंत्र को गहरा धक्का लगेगा। समय आ गया है जब पूरा देश विपक्ष के इस प्रकार के आचरण पर गंभीरता से विचार करे।

खरी-खरी

राहत पैकेज के हकदार

योगेंद्र माथुर

टीवी पर सरकार के राहत पैकेज की घोषणा का समाचार सुनकर बेटे ने मुझसे पूछा, पापा ये सरकार इतनी बार राहत पैकेज की घोषणा करती है, हमें तो कभी कुछ मिलता ही नहीं?

किशोरवय बेटे के जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पर मन ही मन मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया, बेटा ये राहत पैकेज हमारे लिए नहीं होते हैं।

फिर किसके लिए होते हैं पापा? बेटे ने तत्काल दूसरा प्रश्न उछाला।

बेटा ये राहत पैकेज या तो कथित गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले कथित गरीबों के लिए होते हैं या फिर उन बड़े उद्योगपतियों के लिए, जिनके उद्योग कुछ दिन के लिए ही बंद होने से देश व सरकार का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।

पापा, हम किसी भी श्रेणी में नहीं आते क्या?

बेटा हम अमीर-गरीब के मध्य के वे 'बेचारे' लोग हैं जो किसी भी सरकार की 'मुआवजा दृष्टि' से बाहर होते हैं। हम लोगों को 'अपना कमाना, अपना खाना' होता है।

बेटे का प्रतिप्रश्न मुझे मेरे 'अस्तित्व' पर प्रश्न खड़ा करता हुआ प्रतीत हुआ। अति स्वाभिमानी, देशभक्त, राष्ट्रवादी, उदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए, मैंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है बेटा, हमारी भी गिनती होती है, सर्विस क्लास हुए तो 'प्रोफेशनल टैक्स पेयर' में, बिजनेसमैन हुए तो 'जीएसटी व इनकमटैक्स पेयर' में और 'मतदाता' की गिनती में तो हम आते ही हैं।

बेटा अब मुखर हो चला था। बोला, पापा ये तो सब देने ही देने वाली बातें हैं, हमें हासिल तो कुछ नही हो रहा। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है।

ऐसा लगा, किसी ने मेरे घायल मन के रिसते घाव पर नमक छिड़क दिया हो। मन के अंतरतम से निकली कराहती आवाज में मैंने कहा, बेटा भेदभाव, पक्षपात, घृणा, ईर्ष्या, उपेक्षा के हर कदम पर शिकार हम, कर्ज, पढ़ाई, रोजगार की चिंता के बोझ से दबे, ताने-उलाहने सुन-सुन कर यूं ही तिल-तिल मर रहे हैं। अब हमारे मरने के लिए बचा ही क्या है?

बेटे ने कोई और प्रश्न नहीं किया। वह समझ चुका था कि हम मध्यम वर्ग के लोगों की 'नियति' में राहत नाम की कोई चीज शामिल नहीं है।

ट्वीट-ट्वीट

संसद में ओबीसी विधेयक लाकर मोदी जी ने सारे विपक्ष को गिरगिट साबित कर दिया। विपक्षी इस पर बहस के लिए क्यों तैयार हो गए? क्या पेगासस मुद्दा नहीं रहा? कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई, तेल की कीमत जैसे किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की, लेकिन ओबीसी बिल पर राजी हो गए। मामला वोट की चोट का है, देश की परवाह नहीं।
डा. अजय आलोक@alok_ajay

राज्यसभा में हंगामे पर दुखी होने के बजाय सभापति एम. वेंकैया नायडू को हंगामा करने वाले सांसदों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वह एक मिसाल कायम करें। कांग्रेस सांसद बाजवा ने संसद में कितना अमर्यादित आचरण किया। फिर भी राहुल या प्रियंका की ओर से निंदा का एक शब्द तक नहीं फूटा। उनके मौन को क्या मिलीभगत मान लिया जाए?
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

कर्नाटक सरकार ने सरकारी आयोजनों में पुष्पमाला, शाल या स्मृति चिन्ह जैसे चलन बंद कर दिए हैं। यह बहुत ही प्रगतिशील कदम है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।
किरण मजूमदार शा@kiranshaw

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी घुसपैठ का वैसा ही विरोध होना चाहिए जैसा 1979 में विनाशकारी सोवियत अतिक्रमण का हुआ था। इसमें अंतरराष्ट्रीय भर्त्सना, सैन्य प्रतिरोध और आर्थिक प्रतिबंधों से भी परहेज न किया जाए।
क्रिस अलेक्जेंडर@calxandr

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या विपक्षी दलों की एकता आकार लेती हुई दिख रही है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या क्रिकेट को ओलिंपिक में शामिल किया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

होना चहिए था जहां जमकर सोच-विचार,
टूटी मर्यादा वहां टूटे सब आचार।
टूटे सब आचार सभी ने देखा ड्रामा,
कब तक झेले देश सांसदों का हंगामा??
नहीं सभापति सिर्फ सभी को आए रोना,
ऐसा होता देख नहीं जो चहिए होना!
- ओमप्रकाश तिवारी

शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा

संजय मिश्र
संपादक, नवदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश डायरी

मध्य प्रदेश में मिलावटी (जहरीली) शराब बेचने वालों का अंजाम तय कर दिया गया है। विधानसभा ने इस अपराध के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करते हुए सजा का स्तर फांसी तक तय कर दिया है। यह किसी से छुपा नहीं है कि राज्य में लंबे समय से चल रहा मिलावटी शराब का धंधा समय-समय पर जानलेवा साबित हुआ। पिछले डेढ़ साल में ही मिलावटी शराब से हुई 39 लोगों की मौत ने उनके स्वजनों को दुख तो दिया ही, सरकारी तंत्र पर भी सवाल खड़े किए। उज्जैन में 14 अक्टूबर 2020 को 12 लोगों की मौत हुई थी। विपक्षी दलों ने सरकार को जमकर घेरा। मुरैना जिले में 11 जनवरी 2021 को हुई घटना ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि सरकार ने सख्ती दिखाते हुए मुरैना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया था।

आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मजबूत कानून के जरिये इस धंधे पर चोट करने की रणनीति बनाई, जिस पर मंगलवार को विधानसभा ने ध्वनिमत से अपनी मुहर लगा दी। एक तरह से सरकार ने शराब में मिलावट करने वालों से निपटने की तैयारी कर उन लोगों की जिंदगी की कीमत पहचानी है, जो इसका शिकार होते हैं। मध्य प्रदेश में शराब का अवैध परिवहन खूब होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से घिरा होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में यह अवैध धंधा काफी फल-फूल रहा है। इन राज्यों के धंधेबाज सस्ती शराब की आपूर्ति के नाम पर मिलावट का खेल खेलते हैं। खतरनाक रसायनों से मिलाकर बनाई जाने वाली शराब तब अधिक घातक हो जाती है जब मिलावट एक सीमा से अधिक हो जाती है। प्रदेश के कई हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जाता है। जनजातीय समुदाय को जरूरत भर के लिए शराब बनाने की छूट का भी धंधेबाज अपने लिए अवसर की तरह उपयोग करते हैं। यही कारण है कच्ची भट्टियों में उबलते मौत के सामान पर नकेल कसने की मांग समय-समय पर उठती रही है। सियासत का रंग भी कई बार चढ़ा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कुछ माह पूर्व ही प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा उठाकर अपनी ही पार्टी को असमंजस में डाल दिया था। हालांकि चरणबद्ध आंदोलन करने की उनकी घोषणा किसी अंजाम तक नहीं पहुंची, लेकिन सरकार को इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा हो गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि हम नशाबंदी के पक्ष में हैं। किसी भी प्रकार का नशा घातक होता है। उनकी स्वीकारोक्ति के बावजूद शराब से राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व का मोह छोड़ना आसान नहीं था। फिर भी सरकार ने इस समस्या से निपटने की नए ढंग से तैयारी की है। कड़े प्रविधानों के साथ सरकार द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा से पारित हो गया है। राज्यपाल का हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।

मिलावटी शराब बेचने वालों को कड़ा दंड देने से ही इस पर पूर्ण नियंत्रण संभव। फाइल

मध्य प्रदेश ने विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व उत्तर प्रदेश में लागू कानून का भी अध्ययन किया और अलग-अलग प्रकार के अपराधों में सजा तय की। उत्तर प्रदेश में किसी की मौत होने या हालत गंभीर होने पर आरोपितों के लिए मौत या उम्र कैद की सजा का प्रविधान है। ऐसी ही व्यवस्था पंजाब में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश ने अपने कानून में किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति को बेहतर तरीके से परिभाषित किया है। इसके तहत मिलावटी शराब के सेवन से मृत्यु के मामले में आरोपित के विरुद्ध बार-बार दोषसिद्ध होता है तो उसे मृत्युदंड की सजा और कम से कम बीस लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

मादक द्रव्य में हानिकारक या अन्य मिलावट करने पर जुर्माना न्यूनतम तीन सौ रुपये के स्थान पर तीस हजार और अधिकतम दो हजार की जगह दो लाख रुपये होगा। आबकारी विभाग या पुलिस की जांच में बाधा पहुंचाने या उन पर हमला करने पर दो की जगह अब तीन साल का कारावास होगा। इस प्रविधान से यह अपराध गैर जमानती हो जाएगा। पहली बार मिलावटी शराब मिलने के अपराध से जुड़े मामलों में कारावास दो माह की जगह न्यूनतम छह माह और जुर्माना एक लाख रुपये से कम नहीं होगा। मिलावटी शराब से शारीरिक क्षति (जैसे आंखों की रोशनी जाना आदि) होने पर न्यूनतम चार माह की जगह दो वर्ष और अधिकतम आठ वर्ष के कारावास के साथ न्यूनतम दो लाख रुपये का जुर्माना होगा। मिलावटी शराब के सेवन से मृत्यु होने पर न्यूनतम दो वर्ष की जगह दस वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास व न्यूनतम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

उम्मीद की जानी चाहिए कि जहरीला कारोबार करने वालों में दहशत होगी और वे चंद रुपयों के लालच में लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद करेंगे। कानून बनाने के साथ बड़ी जिम्मेदारी इसे लागू करवाने वालों पर भी होगी।

मंथन

महामारी से निपटने में प्रभावी पंचायत

कोरोना रोधी टीकाकरण में तेजी आने और महामारी संबंधी प्रोटोकाल का पालन होने से संक्रमण पर लगाम लग रही है, पर इसकी तीसरी लहर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे में पंचायतों की भूमिका एक बार फिर प्रभावी होती दिख रही है

शिवांशु राय
सामाजिक मामलों के जानकार

कोरोना महामारी से निपटने में विभिन्न देशों में अनेक प्रकार की रणनीतियों को अपनाया गया है। ऐसे में भारत में भी विकेंद्रित व्यवस्था के तहत स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज संस्थाओं की सकारात्मक भूमिका साफ उभर कर सामने आई है। कोरोना महामारी के संक्रमण की भयावह दूसरी लहर में महामारी के ग्रामीण स्तर तक फैलने पर भी पंचायतों द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का आंकड़ा एकत्रित करने, मनरेगा के माध्यम से स्थानीय रोजगार के सृजन में सहयोग करने, मुफ्त राशन वितरण, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने, संक्रमितों या बाहर से आने वालों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था करने, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था, कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण के प्रति सभी लोगों को जागरूक और तत्पर करने जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

अनेक राज्यों ने तो स्थानीय स्वशासन के सहयोग से कोरोना महामारी के संक्रमण को विभिन्न प्रकार की कार्ययोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर नियंत्रित किया हैं। जैसे महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में 'मेरा गांव कोरोनामुक्त' जैसे संकल्पित अभियान से पंचायतों का सदुपयोग पूरे देश में नजीर बना तो कोरोना के दौरान 'काशी माडल' की पूरे देश में सराहना हुई जिसमें वाराणसी में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए तैयार रणनीति में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 'माइक्रो कंटेनमेंट जोन नीति' अपनाकर 'जहां बीमार वहीं उपचार' की व्यवस्था से पंचायतों का सहयोग सुनिश्चित कर महामारी को नियंत्रित किया गया। उल्लेखनीय है कि काशी माडल में ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट के समावेश के साथ जनसहभागिता की बड़ी भूमिका रही है। व्यापक नजरिये से देखा जाए तो ढाई लाख से अधिक पंचायतों के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है जो स्थानीय सरकार द्वारा कोविड महामारी से लड़ रहा है। यह हमारे देश में शक्तियों के विकेंद्रीकरण और संघवाद का सबसे नायाब उदाहरण हैं।

विभिन्न संस्थाओं और विशेषज्ञों द्वारा कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की चेतावनियों के बीच पंचायतों के समक्ष महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आ खड़ी होती हैं। आखिरकार कैसे बेहतर प्रबंधन क्षमता और सीमित संसाधनों के बीच प्रभावी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोका जाए? दरअसल पंचायतीराज संस्थाओं के कई निर्णयों और दायित्वों को राज्यों के अधीन होने के साथ साथ एवं अनेक राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को कई प्रणालीगत बाधाओं और संस्थागत चुनौतियों की वजह से अधिकांश अधिकारों को भी नहीं सौंपा गया है। बहुत से राज्यों में तो धन आवंटन, पंचायतों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी व्यापक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, लिहाजा यही कारण है कि आज भी पंचायतों के अधिकारों, व्यापकता, क्षमता, कार्यक्षेत्र और विकास कार्यों से संबंधित योजनाओं के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता और पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है। यहीं से भ्रष्टाचार की बुनियाद मजबूत होती चली जाती है।

हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू से ही स्थानीय स्वशासन को स्वावलंबी, सुदृढ़, सक्षम और सशक्त करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। साथ ही नियमन और निगरानी तंत्र को भी अधिक पारदर्शी और सबल बनाया गया है। वर्ष 2015 में पंचायती राज मंत्रालय में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की शुरुआत करने के साथ साथ 14वें और 15वें वित्त आयोग की ग्राम विकास अनुदान राशि को बढ़ाने की अनुशंसा पर भी अमल करना, बेहतर प्रबंधन, नियमन, निगरानी और पारदर्शिता को बनाने के लिए ग्राम सभाओं की प्रगति रिपोर्ट, लाभार्थियों की सूची और तमाम विकास कार्यों जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, सड़क, बिजली और अन्य कार्यों आदि की वार्षिक रिपोर्ट को आनलाइन कर जनता के लिए सुगम बनाना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन, स्वामित्व योजना की शुरुआत और ई-गवर्नेंस की दिशा में पंचायतों को जोड़ते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल एवं आडिट आनलाइन एप्लीकेशन को लांच किया गया। इससे ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता आने के साथ साथ जागरूकता, सुशासन और जवाबदेही का भाव पैदा होगा।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच विभिन्न ग्रामीण इलाकों में तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करना, पीएचसी के स्वास्थ्यकर्मियों को एक समग्रतापूर्ण, विस्तृत दृष्टिकोण तथा संक्रामक रोग नियंत्रण, निगरानी प्रणाली, रियल टाइम डाटा प्रबंधन, सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के संबंध में व्यावहारिक चिकित्सकीय समस्याएं, ग्रामीण परिवेश तथा विभिन्न सामाजिक आयामों की समझ और सामान्य रूप से कुछ प्रशासनिक समझ को विकसित करने की जरूरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर निगरानी प्रणाली, टेलीमेडिसिन की व्यवस्था, बुनियादी अवसंरचना का विकास, स्वास्थ्य उपकरण, टेस्टिंग किट, दवाएं और वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। गांव में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन पहलों से जोड़ना एवं पंचायतों को अपने क्षेत्र में इन सब कार्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदार बनाना बेहतर कदम हो सकता है।

राज्यों को एक बेहतर कार्ययोजना बना कर कोविड नियंत्रण में पंचायतों को मुख्य भूमिका में लाने की जरूरत है। फंड की उपलब्धता, पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने व नियमन प्रणाली को मजबूत बनाकर ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत कर हम तीसरी लहर से ज्यादा सहजता से निपटने में सक्षम हो सकते हैं।

पंचायतों के माध्यम से गांवों में स्वास्थ्य प्रणाली का ढांचा किया जाए विकसित। फाइल

29.25 करोड़ रुपये वर्ष 2019-20 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुनावी बांड के माध्यम से मिले। तृणमूल कांग्रेस को 100.46 करोड़ रुपये, द्रमुक को 45 करोड़ रुपये, शिवसेना को 41 करोड़ रुपये व राष्ट्रीय जनता दल को 2.5 करोड़ रुपये मिले।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 12 अगस्त, 2021

बंगाल

परीक्षा में सवाल पर विवाद

बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर पिछले छह माह से लगातार सवाल उठते रहे हैं। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मुद्दे पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच लगातार जुबानी जंग होती रही है। इस बीच बंगाल की चुनावी हिंसा को लेकर एक भर्ती परीक्षा में सवाल पूछे जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में नियुक्ति के लिए आठ अगस्त को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें दस नंबर का एक सवाल बंगाल की चुनावी हिंसा को लेकर पूछा गया था और 200 शब्दों में रिपोर्ट लिखने को कहा गया था। यह खबर सामने आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के नेता काफी क्षुब्ध हैं। वे इसकी निंदा करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार यूपीएससी परीक्षा को भी राजनीति के रंग में रंगना चाहती है? क्या यह सब राजनीति से प्रेरित नहीं है? वहीं तृणमूल की ओर से उठाए गए सवालों पर भाजपा ने भी परलटवार किया और पूछा कि तृणमूल सरकार ने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सिंगुर आंदोलन के इतिहास को क्यों शामिल कराया है? इसी से साबित होता है कि शिक्षा का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? क्या बंगाल में शिक्षा व्यवस्था है? सिंगुर को पाठ्यक्रम में शामिल कर राजनीतिकरण तो तृणमूल ने किया है। सिंगुर आंदोलन पाठ्यक्रम में शामिल कर ममता की तुलना मनीषियों से की गई है, ऐसा क्यों? यूपीएससी की इस परीक्षा में किसान आंदोलन और दिल्ली में आक्सीजन आपूर्ति की समस्या पर भी सवाल पूछे गए थे। ऐसे में विपक्ष को विवाद का एक और मुद्दा मिल गया है।

> सीएपीएफ में नियुक्ति के लिए आठ अगस्त को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें दस नंबर का एक सवाल बंगाल की चुनावी हिंसा को लेकर पूछा गया था

माकपा तो और भी एक कदम आगे बढ़ गई। माकपा नेता ने यूपीएससी प्रश्न पत्र की निंदा करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में ऐसी घटनाएं अभूतपूर्व हैं। जब से यह सरकार केंद्र की सत्ता में आई है, तब से उन्होंने संविधान के दायरे से बाहर एक के बाद एक संस्थाओं का इस्तेमाल किया है। इस मामले में भी संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए केंद्रीय परीक्षा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर यहां सवाल माकपाइयों से भी है कि उन्होंने बंगाल में 34 वर्षों के शासन में शिक्षा का क्या हाल कर रखा था? आज वे उपदेश दे रहे हैं। यह सत्य है कि शिक्षा को राजनीति से अलग रखना चाहिए। क्या भारतीय शिक्षा में मार्क्सवाद और लेनिनवाद को पढ़ाना सही था? क्या सिंगुर आंदोलन को पाठ्यक्रम में शामिल करना सही है? अगर यह सही नहीं है तो परीक्षा में ऐसे सवाल पूछना भी सही नहीं है।

उत्तर प्रदेश

जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत

इसमें शायद ही किसी को कोई संशय हो कि यदि उत्तर प्रदेश के विकास में बढ़ती आबादी एक बड़ी अड़चन है और यदि इस पर अंकुश न लगाया गया तो इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को उठाना होगा। बढ़ती आबादी पर अंकुश तभी लग सकेगा, जब लोग खुद अपनी सोच में बदलाव लाएं, लेकिन अलग-अलग वर्ग में बंटे समाज के लोगों की सोच में एकरूपता संभव नहीं प्रतीत होती। ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। चूंकि राज्य विधि आयोग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है, इसलिए जल्द ही विधिक औपचारिकताओं के बाद इसे मंजूरी भी मिल सकती है। इसके बाद लोग दो बच्चों के नियम के कानून से बंधे होंगे और भले ही तात्कालिक तौर पर इसका प्रभाव न दिखाई दे, लेकिन आने वाले दिनों में पूरे समाज पर इसका असर दिखाई देगा। वैसे भी पढ़े लिखे और जागरूक लोग आज भी दो बच्चों से अधिक की आकांक्षा नहीं रखते और कुछ तो एक बच्चे से ही संतुष्ट नजर आते हैं कि इसका पालन पोषण उचित ढंग से होगा और वह देश को एक परिपक्व युवा दे सकेंगे। इस कानून की प्रस्तावना के साथ ही एक बड़ा संदेश यह भी उभरकर

व्यावहारिक तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का समय। फाइल

> जनसंख्या नियंत्रण को लेकर खुद लोग कितने गंभीर और जागरूक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकांश लोगों ने अपने सुझाव में इसे लागू करने की सिफारिश की

सामने आया है कि वर्तमान में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत खुद ही महसूस करने लगी है। राज्य विधि आयोग ने कानून का मसौदा तय करने से पहले लोगों से सुझाव मांगे थे, जिस पर 8500 लोगों ने अपनी राय दी थी और इसमें लगभग आठ हजार लोगों का मानना था कि यह कानून जरूरी है। यानी कि कानून लागू होने से पहले ही जनभावनाएं इसके पक्ष में खड़ी नजर आ रही हैं। लोगों की गंभीरता का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि अधिकांश ने दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आरक्षण से वंचित किए जाने से लेकर मताधिकार छीनने तक की सिफारिशें की हैं। जिस प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ हो, वहां इतनी सख्ती की दरकार भी है।

हरियाणा

मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं

रोहतक के मदीना में एक परिवार ऐसा है जहां पति-पत्नी और एक बेटा तो भारतीय हैं, लेकिन बड़ा बेटा और बेटी पाकिस्तानी हैं। यह परिवार 2005 में पाकिस्तान से आकर यहां बसा था। इनमें से परिवार के कुछ सदस्यों को तो भारत की नागरिकता मिल गई, कुछ अभी इसके लिए प्रयास में लगे हैं। हरियाणा में ऐसे बहुत से हिंदू परिवार हैं, जो पाकिस्तान में होने वाले अत्याचारों से त्रस्त होकर यहां आकर बसे हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाए, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसे पूरा करना ही मुश्किल होता है। सरकार को इन पीड़ित लोगों के बारे में विचार करना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार होते हैं, उसके कारण वहां से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख पलायन कर भारत पहुंचते हैं। अपना सबकुछ छोड़कर यहां आए इन लोगों के लिए नियमों को कुछ शिथिल बनाने के बारे में भी विचार होना चाहिए। फतेहाबाद में रह रहे डिवायाराम पाकिस्तान में सांसद रह चुके हैं। उनके परिवार को इतना प्रताड़ित

शरणार्थियों के प्रति नरम रुख अपनाए सरकार। फाइल

किया गया कि वह जान बचाकर फतेहाबाद के गांव रतनगढ़ पहुंचे और यहां रह रहे हैं। वह सांसद थे, यहां मूंगफली बेचकर गुजर करते हैं, फिर भी प्रसन्न हैं। ऐसी ही पीड़ा पाकिस्तान से आकर हरियाणा में बसे लगभग हर हिंदू परिवार की है। त्रास देने वाली बात तो यह है कि इन दीन-हीन लोगों को भले ही नागरिकता न मिल पा रही हो, लेकिन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं हासिल हो जाती हैं। उनके राशन कार्ड बन जाते हैं। आधार कार्ड बन जाते हैं। दूसरी तरफ अन्याय से पीड़ित होकर पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को बहुत सी कठिनाइयां पेश आती हैं। प्रदेश सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें नागरिकता दिलाने में मदद करे और उनको सरकारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बारे में भी सोचे। ये भरोसा लेकर ही भारत आए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बारे में सोचें।

> पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को आत्मसात करना आवश्यक है, सरकार और समाज दोनों को उनकी सहायता करनी चाहिए

उत्तराखंड

खाली होते गांवों के प्रति बढ़ती चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश में एक बार फिर उत्तराखंड में खाली होते गांवों की चिंता झलकी है। सोमवार को किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त हस्तांतरित करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने टिहरी जिले के डडूर गांव के युवा किसान सुशांत उनियाल से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहाड़ की जवानी और पानी उत्तराखंड के काम आनी चाहिए। प्रधानमंत्री पहले भी कई बार प्रदेश के दौरे पर विभिन्न जनसभाओं में यह दोहरा चुके हैं। सर्वविदित है कि पलायन के दंश से जूझ रहे प्रदेश में कृषि की हालत दयनीय हो चुकी है। कभी प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कृषि क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी घटकर छह फीसद से भी कम हो गई है। वर्ष 2014 में यह आंकड़ा सात फीसद से अधिक था। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि राज्य गठन के बाद से अब तक करीब 77 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर में तब्दील हो चुकी है। हालांकि गैर सरकारी स्तर पर यह आंकड़ा एक लाख हेक्टेयर से भी अधिक बताया जा रहा है। जाहिर है पलायन की इसमें बड़ी भूमिका है।

> पहाड़ से पलायन से प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। राज्य सरकार हालात से निपटने की कोशिश कर रही है, पर यह तभी फलीभूत होगा, जब योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले

पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1702 गांव जनविहीन हो चुके हैं। इसमें सर्वाधिक प्रभावित जिले पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी हैं। इन जिलों में क्रमशः 517, 162 और 146 गांव पूरी तरह से खाली हैं। जाहिर है पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार ही है, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव ने हालात को जटिल बना दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा कर रहा उत्तराखंड केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। यही वजह है कि चारधाम आल वेदर रोड के साथ ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इन योजनाओं से प्रदेश में न केवल विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। पलायन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना काल में देश के विभिन्न भागों से करीब साढ़े चार लाख प्रवासी वापस आए। इनमें से दो लाख तो लौट गए, लेकिन शेष अभी गांवों में ही हैं। टिहरी के सुशांत उनियाल जैसे लोग अपने दम पर युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर भी मनरेगा और स्वरोजगार जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिल सके।

श्रद्धा का महासावन

शुभकारी हैं शिव

शिव संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है-'कल्याणकारी या शुभकारी'। भगवान शिव के साधक को मृत्यु, रोग और शोक का भय नहीं होता। यजुर्वेद में शिव की महिमा का मंडन शांतिदाता के रूप में किया गया है। शिव सृष्टि की स्थापना, पालन और विनाश के आधार हैं। इसी कारण भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर की होती है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिह्न। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परमपुरुष का प्रकृति के समन्वित चिह्न। भगवान शिव का रूप-स्वरूप जितना विचित्र है, उतना ही आकर्षक भी। इनकी जटाएं अंतरिक्ष व चंद्रमा मन का प्रतीक है। इनकी तीन आंखें हैं, इसीलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। ये आंखें सत्व, रज, तम (तीन गुणों), भूत, वर्तमान, भविष्य (तीन कालों), स्वर्ग, मृत्यु, पाताल (तीन लोकों) का प्रतीक हैं। सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है। इनका त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक तापों को नष्ट करता है, जबकि डमरू का नाद ही ब्रह्मस्वरूप है। शिव के गले की मुंडमाला मृत्यु को वश में करने का संदेश देती है। शिव शरीर पर व्याघ्र चर्म यानी बाघ की खाल पहनते हैं। व्याघ्र हिंसा और अहंकार का प्रतीक है, जो शिव के अधीन है। शरीर पर भस्म का लेप बताता है कि संसार नश्वर है। शिव का वाहन बैल है, जो धर्म का प्रतीक है। चार पैर वाले जानवर की सवारी कर महादेव संदेश देते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से मिलते हैं। शिव की कृपा प्राप्ति के लिए दूसरों के हित का कार्य करना चाहिए। भूखों को भोजन कराने, मजबूर की मदद करने वाले पर शिव की कृपा बरसती है।

स्वामी हरिचैतन्य ब्रह्मचारी
पीठाधीश्वर, टीकरमाफी आश्रम, प्रयागराज

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

श्रमिकों पर आज भी 'गिरमिटिया' की काली छाया, हो रहा शोषण

अरुण साथी, शेखपुरा

- कई राज्य तक दलालों का नेटवर्क, भेड़-बकरियों की तरह ले जाए जाते हैं श्रमिक
- सरकारी योजनाओं में स्थानीय स्तर पर मिलने लगा काम तो तिलमिला गए दलाल

गुलामी के दौर में गिरमिटिया श्रमिकों के शोषण की कहानी भले ही अतीत का दुःस्वप्न हो, पर परोक्ष रूप में आज भी वह काली छाया मौजूद है। सिर्फ पात्र बदल गए हैं। तब अंग्रेज थे, आज अपने ही बीच के लोग हैं। बिहार के शेखपुरा से ऐसा ही मामला सामने आया है। श्रमिकों को जब सरकारी योजनाओं में स्थानीय स्तर पर ही काम मिलने लगा तो दलाल तिलमिला गए। इन लोगों ने श्रमिकों पर दबाव बनाना शुरू किया। बाहर जाने से इन्कार करने पर उनके साथ मारपीट तक की जाती है। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने बुधवार को प्राथमिकी भी दर्ज की है। कितने ही मामले तो दबे रह जाते हैं।

बात नहीं मानने पर प्रताड़ना, तोड़ डाला पैर : ठीकेदारी की आड़ में इंसानों की खरीद-फरोख्त का एक सिस्टम बना लिया गया है। स्थानीय ठीकेदार श्रमिकों को कुछ अग्रिम राशि दे देता है कि उसे फलां ईंट भट्ठे पर काम करना है। फिर उसे बड़े ठीकेदार के माध्यम से कोलकाता, पंजाब, हरियाणा इत्यादि जगहों पर भेज दिया जाता है। श्रमिकों को मना करने की इजाजत नहीं है। उसे जाना ही होगा। ऐसे ही एक श्रमिक शेखपुरा जिले के पुनेसरा गांव निवासी सुरेश राम के पुत्र संतोष राम को घर से जबरन उठाकर ले जाया गया और मारपीट की गई। चूंकि नल जल योजना में उसे यहीं काम मिल गया था, सो बाहर जाने से मना कर दिया था। उसका पैर तोड़ दिया गया। थानाध्यक्ष जयशंकर मिश्र ने बताया कि इस मामले में नीरज साव और उसके भाई टुनटुन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

बेबस श्रमिकों का दर्द : मारपीट की इस एक घटना की पृष्ठभूमि में बेबस श्रमिकों का अंतहीन दर्द छिपा है। उन्हें बड़ी संख्या में बाहर ले जाया जाता है, पर सब कुछ मौखिक होता है। कानून के प्रविधान का कहीं कोई अनुपालन नहीं किया जाता है। यह नेटवर्क बिहार के गांवों से पंजाब, बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश इत्यादि के ईंट भट्ठा कारोबारियों से जुड़ा है। गणेश पूजा से लेकर दशहरा तक खास तौर से स्लम बस्तियों में श्रमिकों को ले जाने के लिए गाड़ियां लगी रहती हैं।

कद-काठी के हिसाब से पैसा : श्रमिकों की कीमत कद-काठी के हिसाब से तय की जाती है। उनके नाम पर 30-40 हजार रुपये तक की रकम कंपनियों से ली जाती है, पर छोटे-बड़े ठीकेदारों से होती हुई श्रमिक तक बमुश्किल 10-15 हजार रुपये पहुंचते हैं। जब वे गांव लौटते हैं तो सूदखोर इंतजार कर रहे होते हैं। गाली-गलौच और मारपीट आम बात है।

घर देते माली हालत की गवाही : इन श्रमिकों की माली हालत की गवाही इनके झोपड़ीनुमा घर देते हैं। इसमें दरवाजा नहीं होता, जब बाहर जाने लगते हैं तो खुले द्वार को ईंट-मिट्टी से बंद कर देते हैं। अखिल भारतीय खेत श्रमिक यूनियन के जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार कहते हैं कि श्रमिकों को दादन (अग्रिम) देकर एक तरह से बंधुआ बना लिया जाता है। जदयू के दलित प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष अशर्फी मांझी बताते हैं कि चिमनी मालिक से साल के अंत में सीजन खत्म होने पर हिसाब किताब करने के लिए ठीकेदार ही रहते हैं। दस से पंद्रह हजार बीमारी के नाम पर काट लिए जाते हैं। उनका कहना है कि श्रमिकों को कानूनी प्रविधानों के तहत पूरी सुविधा दी जानी चाहिए। जो खेल चल रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए।

चीन सीमा पर इंटरनेट सेवाओं की बदहाली पर हाई कोर्ट सख्त

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- उत्तराखंड के धारचूला में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं का बुरा हाल
- हाई कोर्ट ने बीएसएनएल को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की खराब मोबाइल व इंटरनेट सेवाओं से उपभोक्ताओं की दिक्कतों का हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सामरिक लिहाज से अहम व अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इस उच्च हिमालयी क्षेत्र से संबंधित याचिका पर बीएसएनएल को नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए अगली सुनवाई सप्ताह भर बाद नियत कर दी।

चीफ जस्टिस आरएस चौहान व जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में पिथौरागढ़ की मोनिका शर्मा के पत्र पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई हुई। मोनिका ने 23 जून को चीफ जस्टिस को पत्र भेजा था। इसमें कह गया था कि धारचूला क्षेत्र में बैंकिंग, डाक व अन्य सार्वजनिक सेवाएं संचार सुविधा पर ही निर्भर हैं। अधिकतर गांव बीएसएनएल की मोबाइल व इंटरनेट सेवा पर निर्भर हैं। कोविड के बाद से शिक्षक व विद्यार्थियों को अध्ययन-अध्यापन के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। धारचूला क्षेत्र में मोबाइल व इंटरनेट सेवा अधिकांश समय बाधित रहती है। बीएसएसएल के मुख्य महाप्रबंधक देहरादून, सीएमडी नई दिल्ली, दूर संचार मंत्रालय व लोक शिकायत पोर्टल पर समस्या दर्ज कराई गई, लेकिन दो साल बाद भी समाधान नहीं निकला, बल्कि हालात और खराब हो गए। शिकायत या ई-मेल की व्यक्तिगत रूप से किसी अधिकारी द्वारा जांच तक नहीं की गई। सीजीएम कार्यालय से भी जवाब नहीं मिलता।

पत्र में यह भी कहा है कि बीएसएनएल के पास हाइड्रो पावर कंपनी का बैकअप लिंक होता है, जिसे आप्टिकल फाइबर केबल ब्रेक के दौरान मोबाइल नेटवर्क प्रदान करने के लिए उपयोग करते हैं। कई माह से भुगतान नही होने से बैकअप लिंक काट दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से हजारों छात्र-छात्राएं आनलाइन पढ़ाई से वंचित हैं। बिजली वितरण व्यवस्था भी गड़बड़ाई है। जनहित याचिका में भारत सरकार के संचार व ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, बीएसएनएल के सीजीएम और पावर ग्रिड के सीएमडी को पक्षकार बनाया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया को बता रहा झारखंड माडल की सफल कहानी

राज्य ब्यूरो, रांची

- स्वास्थ्य विभाग की तत्कालीन सचिव निधि खरे की रणनीति से एक महीने में डेंगू और चिकनगुनिया पर पा लिया था नियंत्रण

डेंगू और चिकनगुनिया दिल्ली और दूसरे महानगरों में हर साल मासूमों की जान लेता है, लेकिन झारखंड ने इस बीमारी पर महज कुछ ही दिनों में लगाम लगा दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के रणनीतिकारों के बीच इन दिनों झारखंड माडल की चर्चा हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में डेंगू पर विस्तार से लिखा है। इसे डब्ल्यूएचओ ने अपने जर्नल में सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रकाशित किया है।

इसके माध्यम से बताने की कोशिश हो रही है कि अगर सरकारी अमला मुस्तैदी से काम करे तो बड़ी से बड़ी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। बात 2018 की है, जब रांची में अचानक डेंगू ने कहर बरपाना शुरू किया था। जिस पर तत्काल प्रयास से काबू पा लिया गया। जिस झारखंड माडल की तारीफ हो रही है, उसकी रणनीतिकार स्वास्थ्य विभाग की तत्कालीन प्रधान सचिव निधि खरे थीं। डेंगू का फैलते ही उन्होंने फौरन धरातल पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसका बेहतरीन नतीजा देखने को मिला और महज कुछ ही दिनों में बीमारी को महामारी बनने पर रोक लगा दी गई।

जनप्रतिनिधियों को भी अभियान से जोड़ा

डेंगू पर नियंत्रण के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जोड़ा गया और व्यापक जागरण अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड स्तर के जनप्रतिनिधि को इससे जोड़ा, जो स्थानीय लोगों से ज्यादा संपर्क में रहते हैं। इसके कारण और निदान दोनों बताने में वे मददगार साबित हुए। स्वास्थ्य विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों को इनके साथ मिलकर काम करने को कहा गया। इनसे मिले इनपुट पर प्रभावित क्षेत्रों में टीम भेजकर ब्लड सैंपल लेने की व्यवस्था की गई, जिससे बीमार लोगों को समय पर इलाज मिल पाया। इससे बीमारी का फैलाव रुक गया।

बेहतर समन्वय से मिली जीत : आपदा के समय बहुत बार सरकारी विभाग एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, जिसका नुकसान आम आदमी को होता है। झारखंड में महत्वपूर्ण विभागों की प्रधान सचिव रह चुकी निधि खरे इस बात को बेहतर ढंग से जानती थीं, इसलिए डेंगू का मामला सामने आने के बाद उन्होंने बगैर समय गंवाए काम शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को पूरे राज्य में अलर्ट पर रखा गया। बेहतर जांच व्यवस्था बनाई। रिम्स सहित सभी प्रमुख अस्पतालों को जांच रिपोर्ट जल्द देने और सही उपचार के लिए ब्लूप्रिंट दिया गया। उन्होंने नगर विकास विभाग से समन्वय स्थापित किया और स्थानीय निकायों और सभी जिलों के डीसी को एडवाइजरी जारी कर जरूरी कदम उठाने को कहा।

उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कृषि एवं पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, नगर विकास, सूचना एवं जनसंपर्क, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, पथ निर्माण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया। राज्य में शायद ऐसा पहली बार था कि इतने विभागों को एक साथ जोड़कर अभियान चलाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में जल्द ही डेंगू पर काबू पा लिया गया। इससे लोगों का भी बड़ी राहत मिली। यह माडल डब्ल्यूएचओ के रणनीतिकारों को अच्छा लगा।

ऊधमसिंहनगर के खटीमा क्षेत्र में 'सुरई जंगल सफारी जोन'

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में भी अब सैलानी वन्यजीवन का करीब से दीदार कर सकेंगे। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटी तराई पूर्वी वन प्रभाग की खटीमा रेंज के सुरई रिजर्व फारेस्ट में 'जंगल सफारी जोन' बनाने की तैयारी है। इसका खाका खींच लिया गया है। इस जोन में सफारी के लिए 27 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जाएगा। वन विभाग के मुखिया प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) राजीव भरतरी समेत अन्य विभागीय अधिकारी इसका जायजा लेने सुरई रवाना हो गए हैं।

कार्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व के पर्यटक जोन सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हैं। परिस्थितियां सामान्य होने पर अकेले कार्बेट में ही प्रतिवर्ष दो-तीन लाख पर्यटक पहुंचते हैं। इस रिजर्व पर पर्यटकों का दबाव भी है। इसे देखते हुए ही सरकार कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगे पाखरो में टाइगर सफारी स्थापित करने जा रही है। वहां टाइगर बाड़े समेत अन्य निर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहे हैं। अब इस कड़ी में सुरई टूरिज्म जोन का नाम भी जुड़ने जा रहा है। वन्यजीव विविधता के लिए प्रसिद्ध सुरई रिजर्व फारेस्ट को पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में पीलीभीत टाइगर रिजर्व का बफर जोन घोषित किया गया था।

देश के 1.28 लाख स्थानों पर ध्वजारोहण करेगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

संजय कुमार, रांची

- आजादी के 75वें वर्ष पर शहर की बस्तियों से लेकर गांवों तक में होंगे विविध कार्यक्रम, ध्वज वंदन दिया गया है अभियान का नाम

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने आजादी के 75वें वर्ष को यादगार बनाने के लिए 15 अगस्त को देश में एक लाख 28 हजार 365 स्थानों पर ध्वजारोहण का निर्णय लिया है। शहर की बस्तियों से लेकर गांवों तक में इसका आयोजन होगा। सभी स्थानों पर परिषद के एक-एक कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। ध्वजारोहण संबंधित स्थल के ही कोई प्रमुख व्यक्ति करेंगे। इस पूरे अभियान का नाम ध्वज वंदन दिया गया है। इसके तहत एक वर्ष तक पूरे देश में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि भोपाल में हुई राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि आजादी के महोत्सव को यादगार बनाना है। जहां तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र की बात है तो झारखंड के 3375 और बिहार के 5500 स्थानों पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम होंगे।

निधि त्रिपाठी ने कहा कि अगले एक वर्ष तक पूरे देश में जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और भारत माता की पूजा की जाएगी। सभी राज्यों में वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। पूर्व सैनिकों के साथ-साथ सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवार के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं, जगह-जगह गोष्ठियां आयोजित कर भविष्य का भारत कैसा हो, इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं सैकड़ों कार्यकर्ता : ध्वज वंदन कार्यक्रम को सफल बनाने में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे हैं। पिछले दिनों पूरे देश में अभाविप के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन की तैयारियों पर अलग से एक सप्ताह का समय दिया। झारखंड में 167 कार्यकर्ताओं ने इसमें शिरकत की। इन कार्यक्रमों को देखते हुए 10 गांवों पर एक कार्यकर्ता को गठनायक बनाया गया है, जबकि एक जिला के लिए एक पालक अधिकारी बनाए गए हैं। एक कार्यकर्ता एक गांव में एक तिरंगा लेकर पहुंचेंगे। सभी स्थानों के लिए एक तिरंगा किट तैयार किया गया है। सभी स्थानों पर ध्वजारोहण से पहले प्रभातफेरी निकाली जाएगी। योजना की रोज समीक्षा की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में समर्पण कर चुके नक्सली करेंगे तिरंगे की शान में कदमताल

मिथलेश देवांगन, राजनांदगांव : आजादी की 75वीं वर्षगांठ इस बार खास होगी। दरअसल, छत्तीसगढ़ में समर्पण कर चुके नक्सलियों का दस्ता परेड दल में तिरंगे की शान में कदमताल करते हुए नजर आएगा। यह पहली दफा है, जब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली बतौर पुलिस सिपाही तिरंगे को सलामी देंगे। नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 44 नक्सली हिंसा छोड़कर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आरक्षक के रूप में बुनियादी प्रशिक्षण ले रहे हैं। 15 अगस्त के लिए परेड के अभ्यास में पूर्व नक्सलियों का दल जोश के साथ कदमताल कर रहा है। मार्चपास्ट व तिरंगे की सलामी को लेकर इनमें उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन म्युनिसिपल स्कूल मैदान में होगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के अधीक्षक इरफान उल रहीम खान ने कहा कि आजादी दिवस समारोह को लेकर पूर्व नक्सलियों में खासा उत्साह है। इनका एक दल आजाद मार्च पास्ट में शामिल होगा।

83 फीसद प्रभावी है कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के खिलाफ स्पुतनिक वैक्सीन। यह जानकारी रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने बुधवार को दी। खास बात यह है कि पहले इस वैरिएंट के खिलाफ वैक्सीन के ज्यादा प्रभावी होने की बात कही गई थी।

काबुल की तरफ तेजी से बढ़ रहा तालिबान

अफगान संकट ▶ आठवीं प्रांतीय राजधानी पर तालिबान काबिज, 11 प्रांतों में सेना के साथ चल रहा संघर्ष

मजार-ए-शरीफ पर कब्जे को लेकर भीषण लड़ाई, अफगान राष्ट्रपति पहुंचे

काबुल, रायटर: अफगानिस्तान पर तालिबान तेजी से काबिज होता जा रहा है। अब वह राजधानी काबुल की ओर बढ़ रहा है। उसने छह दिनों में आठवीं प्रांतीय राजधानी कब्जा कर लिया है। तालिबान ने पुल-ए-खुमरी और फैजाबाद को अपने नियंत्रण में ले लिया है। पुल ए खुमरी काबुल से सवा दो सौ किमी दूर है।

तालिबान ने पिछले 24 घंटे में बगलान प्रांत की राजधानी पुल ए खुमरी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बदख्शान की राजधानी फैजाबाद को भी नियंत्रण कर लिया। बदख्शान प्रांत की सीमा ताजिकिस्तान, पाकिस्तान व चीन से लगी हुई है। यह अफगान सरकार के लिए बड़ा धक्का है। उसकी चिंता पुल-ए-खुमरी पर कब्जे के बाद बढ़ गई है। इस शहर पर कब्जे के बाद काबुल जाने वाले राजमार्ग पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है।

तालिबान अब अफगानिस्तान में पूरी तरह इस्लामिक कानूनों को लागू करना चाहता है। यूरोपीय यूनियन के अधिकारी के अनुसार, अभी 11 प्रांतीय राजधानियों पर भीषण संघर्ष चल रहा है। तालिबान ने काबुल के उत्तर के उन क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया है, जहां से काबुल के लिए बिजली की सप्लाई की जा रही है। कंधार पर भीषण संघर्ष चल रहा है। यहां पर हवाई हमले में 10 आतंकी मारे गए। कंधार में भीषण हिंसा के चलते यहां से 30 हजार परिवारों का पलायन हो गया है।

बल्ख प्रांत के मजार-ए-शरीफ को तालिबान के चारों तरफ से घेरने के बाद इस शहर में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पहुंच गए। उनके साथ उनके सुरक्षा और राजनीतिक सलाहकार मोहम्मद मोहाकिक भी थे। यहां अशरफ गनी ने सुरक्षा के संबध में एक बैठक भी की। इसमें बल्ख के गवर्नर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इधर रूस की मीडिया ने दावा किया है कि तालिबान ने ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगी सीमा के क्षेत्रों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। वहीं रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 439 तालिबान आतंकियों को मार गिराया गया है। 77 आतंकी घायल हुए हैं।

ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लगी सीमा के क्षेत्रों में तालिबान का कब्जा

अफगानिस्तान में तालिबान धीरे-धीरे तमाम प्रांतों पर कब्जा करता जा रहा है। वहां के अंदरूनी हालात के बहुत ही तेजी से बदलने से वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। बुधवार को उत्तरी प्रांतों की सुरक्षा की स्थिति जानने के लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी मजार-ए-शरीफ पहुंचे। रायटर

तालिबान के खौफ से कार्यवाहक वित्त मंत्री काबुल से भागे

एएनआइ के अनुसार अफगानिस्तान के कार्यवाहक वित्तमंत्री खालिद पायंदा ने अपने पद से इस्तीफा देकर अफगानिस्तान छोड़ दिया है। स्थानीय मीडिया ने कहा है कि अब पायंदा अफगानिस्तान नहीं लौटेंगे। उन्होंने इस्तीफे की जानकारी ट्विटर पर भी दी है। उन्होंने कहा, वह व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। माना जा रहा है कि वह तालिबान के खौफ से इस्तीफा देकर भागे हैं। स्थानीय मीडिया का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति पैलेस के दबाव में इस्तीफा दिया है।

सेनाध्यक्ष बदले गए

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, तालिबान के लगातार प्रांतीय राजधानी पर कब्जे के दौरान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मौजूदा सेनाध्यक्ष को बदल दिया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हिबतुल्लाह अलीजई ने जनरल वली अहमदजई के स्थान पर सेनाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इंटरनेट मीडिया पर पाक को कोस रहे लोग

एएनआइ के अनुसार, हिंसा बढ़ने के साथ ही अफगान नागरिक इंटरनेट मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वह पाकिस्तान को देश में जारी संघर्ष का जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर कोस रहे हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग का मुद्दा टाप ट्रेंडिंग में है।

तालिबान एक से तीन माह में कब्जा कर सकता है काबुल पर

एएनआइ ने वाशिंगटन पोस्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिकन एजेंसियों का अनुमान है कि तालिबान एक से तीन माह में काबुल पर कब्जा कर सकता है। खुफिया विभाग का कहना है कि जून के बाद से अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान के समर्थन में हालात बदले हैं। अफगानिस्तान में अब हर स्थितियां गलत दिशा में जा रही हैं। इधर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी का कहना है कि राष्ट्रपति जो बाइडन मानते हैं कि जरूरी नहीं कि तालिबान का कब्जा काबुल पर हो जाए।

10 दिन में चार हजार लोगों का इलाज किया रेडक्रास ने

एएनआइ के अनुसार, हिंसा में हजारों लोग घायल हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था रेडक्रास सोसायटी ने कहा है कि अगस्त माह के दस दिनों में 4 हजार से ज्यादा घायल लोगों का अब तक उनके द्वारा इलाज किया गया है। जुलाई माह में 13 हजार ऐसे घायलों का इलाज किया, जो हथियारों से घायल हुए थे।

हिंसा के बीच दोहा में चल रही उच्चस्तरीय बैठक

एएनआइ के अनुसार, हिंसा और तालिबान की बढ़त के बीच दोहा में तीन दिवसीय उच्चस्तरीय बैठक भी शुरू हो गई है। इस बैठक में अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला और तालिबान नेताओं के साथ ही संयुक्त राष्ट्र, कतर, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, चीन, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अमेरिका के विशेष दूत जालिमे खलीलजाद भी बैठक में मौजूद हैं। ये सभी युद्ध विराम और हिंसा समाप्त करने पर वार्ता करेंगे।

बाइडन बोले, अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के फैसले पर पछतावा नहीं

वाशिंगटन, आइएएनएस: अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि उन्हें सेना वापसी के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। अफगान सेना को खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। बाइडन ने अफगानिस्तान के सभी नेताओं से एक जुट होने की अपील करते हुए कहा कि वे अपने देश के लिए लड़ें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने बीस साल में अरबों डालर खर्च कर अफगानिस्तान की पूरी सहायता की। उनके लिए अपने सैनिकों की शहादत दी। यही नहीं अफगान सेना के तीन लाख सैनिकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही हथियार मुहैया कराए। अभी भी वह उनकी बराबर सहायता कर रहे हैं। यहां तक कि उनको हवाई सहायता भी दी जा रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में सेना वापसी के प्लान में परिवर्तन करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अगस्त के अंत तक अमेरिकी सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से वापसी कर रही है। यहां से 95 फीसद सेना की वापसी हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने 1 मई को सेना वापसी की घोषणा की थी। उसी के बाद से तालिबान ने हिंसा तेज कर दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफगास्तिान से झाड़ा पल्ला। एपी

अफगान मुद्दे पर आज दोहा में बैठक, भारत भी लेगा हिस्सा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दोहा बैठक से शांति की राह निकलने की उम्मीद कम, लगातार मजबूत होता जा रहा है तालिबान

अफगानिस्तान में दो और प्रांतों और अफगान सेना की मदद के लिए भेजे गये एक भारतीय एमआई-24 हेलीकाप्टर पर तालिबान के कब्जे की सूचनाओं के बीच गुरुवार को दोहा में होने वाली बैठक के लिए भारत की तैयारी पूरी है। हालांकि भारतीय पक्ष अंदरखाने यह स्वीकार करने लगा है कि हालात वहां पहुंच गए हैं जहां दोहा या किसी और बैठक का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक तालिबान के हिंसक आक्रमण को रोकने के लिए कोई निर्णायक फैसला न हो।

अफगान में अपने हितों के खिलाफ माहौल जाते देख भारत की रणनीति यही रहेगी कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी तालिबान पर शांति समझौता करने के लिए एकजुट हो कर दबाव बनाये। कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा है कि जिस तेजी से तालिबान अफगानिस्तान में एक के बाद एक शहरों को कब्जे में ले रहा है उसे देखते हुए इस बात के आसार कम ही हैं कि वह शांति समझौते के लिए तैयार होगा। सिर्फ पिछले पांच दिनों में नौ प्रांतों पर अफगानिस्तान का कब्जा होने की सूचना है। हालात की गंभीरता देख भारत ने मजार-ए-शरीफ स्थित अपने मिशन में काम करने वाले सभी अधिकारियों और उनके परिवार को वापस बुला लिया है। भारत सरकार की तरफ से भेजे गए एक विशेष विमान से तकरीबन 50 लोग नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारत ने यह फैसला तालिबानी सैनिकों के मजार-ए-शरीफ की सीमा पर पहुंचने के बाद किया। अब भारत की उपस्थिति मोटे तौर पर राजधानी काबुल में रह गई है। जिस तेजी से अफगानिस्तान सरकार के सैनिक तालिबान लड़ाकों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं उसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय बिरादरी मानने लगी है कि काबुल पर भी उनका कुछ हफ्तों में कब्जा हो जाएगा। दोहा में अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान के बीच पिछले दो दिन से वार्ता हो रही है। इस क्रम में गुरुवार को एक और अहम क्षेत्रीय वार्ता होगी जिसमें भारत, तुर्की, इंडोनेशिया व कुछ दूसरे देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारत के कूटनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि इस बैठक को देखते हुए ही तालिबान ने पिछले एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा शहरों पर कब्जा जमाने की कोशिश की है ताकि वह यह दिखा सके कि अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर उसका शासन है।

अगर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी तालिबान पर दबाव बनान में सफल होती है तो वह ज्यादा क्षेत्र के अपने कब्जे में होने की बात करके सौदेबाजी कर सकता है। हालांकि भारतीय पक्षकार जिस तरह से अफगानी सेना ने कई शहरों में आसानी से अपने गोले बारूद फेंक कर भाग खड़े हुए हैं उससे ज्यादा चिंतित है। सनद रहे कि दुनिया के कुछ अन्य देशों के अलावा भारत ने भी बड़े स्तर पर अफगानी सैनिकों व सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित किया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर पक्का फैसला होने बाद से तालिबान ने वहां कई सारे प्रांतों पर हमले शुरू कर दिये हैं। गुरुवार को यह सूचना है कि उत्तरी अफगानिस्तान के नौ प्रांतों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान पर अंकुश लगाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की तरफ से अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की जा सकी है। दूसरी तरफ रूस और चीन भी अब पाकिस्तान की मदद करते दिख रहे हैं ताकि पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो सके। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने दैनिक जागरण को बताया है कि अफगानिस्तान को लेकर हमारे रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। दोहा बैठक के दौरान भी हम अफगानिस्तान के लोगों के नेतृत्व में ही समाधान निकालने का मुद्दा उठाएंगे और वहां लोकतांत्रिक परंपराओं, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी की बात करेंगे।

यौन उत्पीड़न के दोषी न्यूयार्क गवर्नर ने दिया इस्तीफा

न्यूयार्क टाइम्स से

- 11 महिलाओं ने की थी शिकायत, जांच में सही मिलीं
- 14 दिन में प्रभावी हो जाएगा एंड्रयू कुओमो का इस्तीफा

न्यूयार्क : सरकारी जांच में 11 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के दोषी न्यूयार्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने आखिर पद पर बने रहने की जिद छोड़ दी और इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 14 दिन में प्रभावी हो जाएगा। उनके स्थान पर लेफ्टीनेंट गवर्नर कैथी होचुल को न्यूयार्क का गवर्नर बनाया जा रहा है। न्यूयार्क के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली वह पहली महिला होंगी।

गवर्नर कुओमो ने इस्तीफा देते समय अपने कार्यालय के माध्यम से टिप्पणी की कि परिस्थितियों को देखते हुए मेरी सरकार के लिए सबसे बड़ी मदद यही होगी कि मैं इस्तीफा दे दूं।

इस्तीफा देने से पहले कुओमो ने अपने कार्यालय के स्टाफ के सामने 21 मिनट का भाषण दिया और उसमें कहा कि उन्होंने किसी भी महिला का अनादर नहीं किया है और न ही करेंगे। इससे पहले उनकी वकील रीटा ग्लैविन ने कहा कि कुओमो के खिलाफ माहौल बनाने के लिए मीडिया दोषी है। उन्होंने जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस जांच में उन लोगों को शामिल नहीं किया, जो इन आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं।

ज्ञात हो कि गवर्नर कुओमो के खिलाफ राज्य की अटार्नी जनरल लेटीटिआ जेम्स महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के अलग-अलग समय पर लगाए आरोपों की जांच कर रही थीं। इन आरोपों को जांच में सही पाया गया। एक सप्ताह पहले जांच रिपोर्ट आने के बाद भी एंड्रयू कुओमो आरोपों को नकारते हुए पद पर बने रहने की जिद पर अड़े हुए थे। उनको राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी पद से हटने के लिए कहा था। एंड्रयू कुओमो का न्यूयार्क के गवर्नर पद पर यह तीसरा कार्यकाल था।

यौन उत्पीड़न के दोषी न्यूयार्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो का फाइल फोटो। एएफपी

कनाडा ने भारत से सीधी उड़ानों पर 21 सितंबर तक प्रतिबंध बढ़ाया

टोरंटो, प्रेट्र : कनाडा ने कोरोना के चलते भारत से सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कनाडा ने अप्रैल में भारत में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर वहां से आने-जाने वाली सभी डाइरेक्ट विमानों पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद से उड़ानें बहाल करने की तारीख कई बार टाली जा चुकी है।

कनाडा के परिवहन मंत्री उमर अलगबरा ने मंगलवार को ट्वीट किया, 'कनाडा के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी सुरक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद हमने कनाडा और भारत के बीच सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध को 21 सितंबर, 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है।'

ब्रिटेन के विवि में रिकार्ड 3,200 भारतीय छात्रों का प्रवेश

- पिछले वर्ष की तुलना में यह संख्या 19 प्रतिशत ज्यादा है
- ट्रैवेल बैन हटने से हुआ दोनों पक्षों को फायदा

लंदन, प्रेट्र: ब्रिटिश विश्वविद्यालयों ने आगामी शैक्षिक सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिकार्ड 3,200 भारतीय छात्रों का प्रवेश स्वीकृत किया है। पिछले वर्ष की तुलना में यह संख्या 19 प्रतिशत ज्यादा है।

यूनिवर्सिटीज एंड कालेजेज एडमीशन सर्विस द्वारा स्वीकृत आवेदनों के ये आंकड़े तब सामने आए हैं जब ब्रिटेन ने भारत को कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए यात्रा प्रतिबंध सूची ट्रैवेल बैन लिस्ट) से बाहर किया है। कुछ शर्तों के साथ भारतीय अब ब्रिटेन जा सकेंगे। अब ब्रिटेन जाने वाले छात्रों को दस दिन का क्वारंटाइन पीरियड सरकारी व्यवस्था वाले स्थान पर नहीं बिताना होगा। इसके स्थान पर छात्र अपनी सुविधा वाले स्थान पर दस दिन का क्वारंटाइन पीरियड गुजारेंगे।

फाइल फोटो /इंटरनेट मीडिया

यूके यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल की डायरेक्टर विवियन स्टर्न के अनुसार, भारत के रेड लिस्ट से बाहर आने से भारतीय छात्र बिना किसी कठिनाई के ब्रिटेन आ सकेंगे। वे अपनी यूनिवर्सिटी की जानकारी में रहते हुए कहीं भी रह सकेंगे। यूके यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल ब्रिटेन के 140 से ज्यादा विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करती है। स्टर्न ने कहा, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। भारतीय छात्रों ने उनमें पढ़ने के लिए बहुत संयम दिखाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें उसका लाभ दें।

रेड लिस्ट से एमबेर लिस्ट में भारत को डाले जाने से अब आने वाले भारतीयों के लिए कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अपेक्षित होगी। ब्रिटेन में आकर छात्रों को जानकारी वाले स्थान पर दस दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। पांचवें दिन कोरोना टेस्ट कराने पर यदि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें क्वारंटाइन से छूट मिल जाएगी।

एक सप्ताह में अमेरिका में 94 हजार से अधिक बच्चे हुए संक्रमित

न्यूयार्क, आइएएनएस: पिछले एक सप्ताह के दौरान अमेरिका में 94,000 से अधिक बच्चे संक्रमित हुए हैं। द अमेरिकन एकेडमी आफ पीडियाट्रिक्स (एएपी) के मुताबिक कुल कोरोना संक्रमितों में 15 फीसद बच्चे हैं। राहत की बात यह है कि संक्रमित बच्चे ना केवल कम गंभीर बीमार हैं बल्कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। संक्रमण के चलते जिन बच्चों की मौत हुई है, वह कुल बीमार बच्चों का 0.03 फीसद है। पांच अगस्त तक लगभग 43 लाख बच्चे संक्रमित हुए हैं।

एएपी की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई की शुरुआत से बच्चों के संक्रमित होने की दर बढ़ रही है। इसके पीछे बड़ी वजह स्कूलों को फिर से खोला जाना है। सेंटर फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक 5 से 11 और 11 से 15 वर्ष के बच्चे प्रति एक लाख की संख्या में 50 वर्ष से अधिक आयुवर्ग की तुलना में ज्यादा बीमार हो रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ के निदेशक डा. फ्रांसिस कोलिंस ने कहा, जब से महामारी शुरू हुई है, उस समय से यह पहली बार है जब सबसे अधिक बच्चे कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हैं। उन प्रांतों में स्थिति ज्यादा खराब है, जहां पर मास्क को लेकर सख्ती नहीं बरती जा रही है। अब तक अमेरिका में 12 साल से अधिक उम्र के 60 फीसद बच्चों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। जबकि लगभग 70 फीसद बच्चों को एक खुराक मिल चुकी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीके को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।

तीन करोड़ 60 लाख से ज्यादा हुई संक्रमितों की संख्या : समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक डेल्टा वैरिएंट के चलते अमेरिका में संक्रमण बेकाबू होता दिख रहा है। मंगलवार तक वहां कुल मरीजों की संख्या तीन करोड़ 60 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं महामारी से जान गंवाने वालों की तादाद 6,18,044 हो गई है। जान हापकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक कुल कोरोना मरीजों के जहां 18 फीसद मामले अकेले अमेरिका में हैं वहीं दुनियाभर में कोरोना से जान गंवाने वाले 14 फीसद लोगों यहीं के हैं। बता दें कि अब तक दुनियाभर में महामारी से 43 लाख लोगों की मौत हो चुकी है।

अमीर और गरीब देशों के बीच टीकाकरण की खाई खत्म करें

जेनेवा : समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक अधिकारी ने अमीर और गरीब देशों के बीच टीकाकरण के अंतर पर गंभीर चिंता जताई है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के वरिष्ठ सलाहकार डा. ब्रूस आयलवर्ड ने कहा कि यह 20 बड़े देशों के नेताओं, दवा कंपनियों के सीईओ और नीति निर्माताओं पर निर्भर है कि वह इस खाई को खत्म करें। उन्होंने कहा, अब तक दुनियाभर में चार अरब टीके लगाए गए हैं। इनमें से केवल एक फीसद टीके ही अफ्रीका महाद्वीप में लगाए गए हैं।

जल्द ही तीन दवाओं का परीक्षण करेगा डब्ल्यूएचओ

जेनेवा : डब्ल्यूएचओ जल्द ही अन्य बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली तीन दवाओं का परीक्षण कर यह जानने का प्रयास करेगा कि ये कोरोना के इलाज में मददगार है या नहीं। डब्ल्यूएचओ ने कहा, दवाओं का परीक्षण वैश्विक तौर पर चल रहे शोध के अगले चरण में किया जाएगा। जिन दवाओं का परीक्षण किया जाएगा, उसमें मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आर्टेसुनेट, कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाली इमैटिनिब व इंफ्लिक्सिमाब हैं। इन दवाओं का प्रयोग इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में किया जाता है।

- पिछले चौबीस घंटों के दौरान ब्राजील में जहां 1,211 लोगों की मौत हुई है वहीं 34,885 लोग संक्रमित हुए हैं। इस दक्षिण अमेरिकी देश में संक्रमण की एक नई लहर दिखाई पड़ रही है।
- समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक दक्षिण कोरिया में भी संक्रमण बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। पिछले चौबीस घंटों के दौरान वहां 2,223 मरीजों का पता चला है। महामारी की शुरुआत से लेकर यह पहली बार है जब एक दिन में संक्रमितों की संख्या दो हजार के आंकड़ों को पार कर गई है।
- समाचार एजेंसी रायटर के मुताबिक रूस में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से 799 लोगों की मौत हुई है। जबकि 21,571 नए संक्रमितों का पता चला है।
- समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक पिछले चौबीस घंटों के दौरान पाकिस्तान में 81 लोगों की मौत हुई और 4,850 लोग संक्रमित हुए हैं।

15 अगस्त को टाइम्स स्क्वायर पर फहरेगा सबसे बड़ा तिंरगा

- 75वें स्वतंत्रता दिवस अमेरिका के भारतीयों में भी जबर्दस्त उत्साह
- तिरंगे के रंगों से जगमगाएगी एंपायर स्टेट बिल्डिंग

न्यूयार्क, प्रेट्र : भारत में स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ को लेकर जबर्दस्त उत्साह है और जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं। यही नहीं दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी स्वतंत्रता दिवस पर तैयारियां कर रहे हैं। इस दिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होंगे। इस बार अमेरिका में रहने वाले भारतीय टाइम्स स्क्वायर पर सबसे बड़ा तिरंगा फहराएंगे।

भारतीय प्रवासियों के संगठन फेडरेशन आफ इंडियन एसोसिएशन (एफआइए) न्यूयार्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। टाइम्स स्क्वायर के बिल बोर्ड पर स्वतंत्रता दिवस का 24 घंटे प्रदर्शन होगा। इसके अलावा अमेरिका में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 15 अगस्त को एंपायर स्टेट बिल्डिंग को भारतीय तिरंगे के तीनों रंगों की रोशनी से सजाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस का समापन हडसन नदी में एक बड़े क्रूज पर शानदार रात्रि भोज के साथ संपन्न होगा। इसमें अमेरिकी सरकार के शीर्ष अधिकारी, विशेष अतिथि और भारतीय समुदाय के लोग शामिल होंगे।

प्रवासियों के संगठन एफआइए ने टाइम्स स्क्वायर पर पिछले साल भी तिरंगा फहराया था। संगठन के चेयरमैन अंकुर वैद्य ने बताया कि पिछले साल पहली बार टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया था। अब यह परंपरा जारी रखने का फैसला किया गया है। इस बार टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा भारत के न्यूयार्क में महावाणिज्य दूत रंधीर जैसवाल फहराएंगे। यह तिरंगा छह फीट चौड़ा और दस फीट लंबा होगा। पोल की ऊंचाई 25 फीट रहेगी।

चीन में कनाडा के उद्यमी को 11 साल की सजा

- हुआवे मामले में कनाडा पर दबाव बनाने को लगे थे जासूसी के आरोप
- कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा, यह सजा अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य है

दाडोंग, एपी : चीन की अदालत ने कनाडा के एक उद्यमी माइकल स्पेवोर को जासूसी के मामले में 11 साल की सजा सुनाई है। कनाडा में गिरफ्तार हुआवे कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वानझोउ को सौंपने के लिए दबाव बनाने की खातिर गिरफ्तार तीन कनाडाई नागरिकों में एक हैं स्पेवोर।

चीन ने 2018 में कनाडा में मेंग वानझोउ की गिरफ्तारी के बाद तीन कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तार किया था। मेंग पर अमेरिका में ईरान पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के मामलों में आपराधिक कार्रवाई चल रही है। चीन कनाडा पर मेंग को सौंपने का दबाव बना रहा है। कनाडा की अदालत मेंग को अमेरिका को सौंपने के मामले में अंतिम सुनवाई करने वाली है।

स्पेवोर को 11 साल की सजा सुनाने से पहले दूसरे कनाडाई नागरिक की ड्रग तस्करी के मामले में फांसी की सजा पर दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। इस कनाडाई नागरिक को पहले जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मेंग के मामले में दबाव बनाने के लिए उसकी सजा को फांसी की सजा में बदल दिया गया। स्पेवोर की सुनवाई के दौरान चीन में कनाडा के दूत डोमिनिक बार्टन भी मौजूद थे। चीन ने मेंग के मामले में कनाडा के पूर्व राजनयिक माइकल कोवरिंग को भी 2018 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनकी भी सुनवाई चल रही है। वहीं, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने स्पेवोर को सजा देने की निंदा करते हुए कहा, यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य है।

ईस्टर धमाका मामले में 25 के खिलाफ आरोपपत्र

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका में वर्ष 2019 में ईस्टर बम धमाकों में 25 संदिग्धों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। संदिग्धों पर कुल 23,270 आरोप लगाए गए हैं। चर्चों और होटलों में किए गए शृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में 11 भारतीयों समेत कुल 270 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति कार्यालय ने बुधवार को कहा कि मंगलवार को हत्या की साजिश, हमले में सहायता और उकसाने, हथियार एवं गोलाबारूद एकत्र करने और हत्या का प्रयास समेत आतंकवाद रोकथाम अधिनियम (पीटीए) के तहत आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं।

इस्लामिक स्टेट (आइएस) से जुड़े स्थानीय इस्लामी कट्टरपंथी समूह नेशनल तावहीद जमात (एनटीजे) ने श्रीलंका में 21 अप्रैल, 2019 को ईस्टर के मौके पर तीन चर्चों कई लग्जरी होटलों में शृंखलाबद्ध विस्फोट किए थे। इन हमलों में 500 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। आत्मघाती बम विस्फोट मामले में श्रीलंकाई पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।

पाकिस्तान कंगाल, जनता भुखमरी के कगार पर

- इमरान की गलत नीतियां, महंगाई और महामारी ने आम जनता की कमर तोड़ी

इस्लामाबाद, आइएएनएस: पाकिस्तान में आम जनता के स्थिति बेहद खराब हैं। गरीबी तेजी से बढ़ रही है। महंगाई आसमान छू रही है। हालात ऐसे हैं कि आम परिवार की आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ दो वक्त के खाने में ही खर्च हो रहा है।

इमरान खान के नेतृत्व में चल रही सरकार की गलत नीतियों के कारण आर्थिक कंगाली तेजी से बढ़ने के बाद अब कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर गई है। जरूरी वस्तुओं की कीमतें इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है कि तमाम वस्तुएं गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति का प्रभाव सीधे निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों पर पड़ रहा है। खाद्य मुद्रास्फीति दहाई के अंक पर है। पाकिस्तान उन देशों की सूची में आ गया है, जहां एक परिवार की पूरी आमदनी का पचास फीसद हिस्सा खाने पर ही खर्च होता है। निम्न आय वर्ग के परिवार गरीबी, भुखमरी और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक खाद्य असुरक्षा वाले परिवार 2019-20 में 100 में 16.4 हो गए हैं। जबकि पिछले साल 100 में 15.9 परिवार इस श्रेणी में थे। इन स्थितियों में पाक में बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही है। भुखमरी के इन हालातों के चलते वहां अपराध भी तेजी से बढ़ गए हैं।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसे विश्वबैंक और विभिन्न देशों से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है।

हड़ताल से थमे ट्रेनों के पहिए...

जर्मनी में ट्रेन चालकों की देशव्यापी हड़ताल से अधिकांश ट्रेने स्टेशनों पर खड़ी हो गई हैं। इससे पैसेंजर और मालगाड़ियों का आवागमन ठप हो गया है। ट्रेन ड्राइवर्स यूनियन के दावा है कि जब तक उनकी वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। उधर, गर्मी की छुट्टी पर जाने वाले लोगों को हड़ताल की वजह से अपने प्रोग्राम रद करने पड़े हैं। रसद और आपूर्ति व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। एपी

भारत की रानियों ने कही दिल की बात

टोक्यो ओलिंपिक में जहां भारतीय महिला हाकी टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने का कारनामा किया तो वहीं पीवी सिंधू ओलिंपिक में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय और पहली महिला एथलीट बनीं। दोनों अभी भी बहुत कुछ करना चाहती हैं। उन्होंने दैनिक जागरण से अपने दिल की बात कही।

मुझे पदक न जीतना हमेशा कचोटता रहेगा : रानी रामपाल

भारतीय पुरुष हाकी टीम ने जहां टोक्यो ओलिंपिक में 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए कांस्य पदक जीता। वहीं महिला हाकी टीम ने भी चौथे स्थान पर रहते हुए सभी देशवासियों का दिल जीता। हालांकि महिला हाकी कप्तान रानी रामपाल का दिल इस बात से खुश नहीं है कि वह चौथे स्थान पर रही बल्कि उनका मानना है कि उनके दिल में हमेशा यह बात कचोटती रहेगी कि हम पदक के इतने करीब आकर उससे वंचित रह गए। टोक्यो से लौटने पर **रानी रामपाल** से **शुभम पांडेय** ने खास बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश :

रानी से सवाल

● **ओलिंपिक में पदक के इतने करीब आकर चूक जाना। कौन सा अहसास ज्यादा बड़ा है आपके लिए? चौथे स्थान पर आना या पदक से चूक जाना?**

-देखिए इस बात का दर्द हमारे अंदर हमेशा बना रहेगा कि पदक के हम काफी करीब थे। 2016 रियो में हमारे पास ओलिंपिक खेलों के अनुभव की कमी थी इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे लेकिन टोक्यो में हमें पहले से ही ओलिंपिक में खेलने के अनुभव का फायदा हुआ। पदक का ना जीतना काफी कचोट रहा है क्योंकि हम बहुत ही करीब थे। एक खिलाड़ी के जीवन में ऐसे पल आते रहते हैं और उसे बहुत जल्द सबकुछ भुलाकर आगे बढ़ना होता है। जैसे आप एक मैच की हार को भुलाकर अगले मैच में उतरते हैं।

सिंधू से सवाल

● **इस समय आपके घर में क्या माहौल है। मम्मी का मेन्यू चल रहा है क्या?**

-मैं बाहर जा रही हूं। जो मन कर रहा है वह खाना खा रही हूं। मम्मी घर पर बहुत खाना बनाती हैं। परिवार के साथ समय व्यतीत कर रही हूं। अभी मैं मंदिर भी गई थी और पूजा भी की।

● **अभी एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें आप साड़ी पहनकर पूजा करने के लिए जा रही हैं। एक अलग सिंधू नजर आ रही है?**

-मैं अक्सर मंदिर जाती रहती हूं। मुझे तिरुपति जाना पसंद है। अभी जो वीडियो वायरल हुआ था वह केरल के मंदिर का था। मैं सभी भगवान में विश्वास रखती हूं और सभी की पूजा करती हूं। भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा रहना चाहिए। मैं पदक लेकर आई हूं तो बहुत खुश हूं। मुझे जब भी मौका मिलता है मंदिर जाती हूं।

मुझे मंदिर जाना पसंद है : पीवी सिंधू

टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू इन दिनों अपने घर में आराम कर रही हैं। वह ओलिंपिक में दो पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं और 15 अगस्त को दिल्ली आने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मंदिर जाना पसंद है और जब मौका मिलता है मैं ऐसा करती हूं। **पीवी सिंधू** से **अभिषेक त्रिपाठी** ने खास बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश-

साक्षात्कार

● **ओलिंपिक में जाने से पहले भी रानी आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि हमारी टीम का फिटनेस स्तर अब यूरोपियन टीमों को हराने के लिए सक्षम है। क्या यही कारण है कि सेमीफाइनल तक का सफर तय कर सके?**

जी हां, जैसा की आपने कहा कि हमारी टीम की फिटनेस का स्तर काफी शानदार हो चुका है और पिछले पांच सालों में हमने इस चीज के ऊपर काफी काम किया। हमारी टीम का प्रदर्शन काफी उच्च स्तर का रहा है। क्योंकि शुरू के तीन मैच हारना और उसके बाद वापसी करते हुए सेमीफाइनल तक जाना। अंतिम के भी जो दो मैच हम हारे हैं। उसमें भी टीम ने ज्यादा गलतियां नहीं की हैं। मेरे विचार से हमारा दिन नहीं था और पदक जीतने से चूक गए।

● **ओलिंपिक में शुरू के तीन मैच हारने के बाद भी सेमीफाइनल तक का सफर तय करना। ऐसा क्या हुआ था उस समय की तीन हार के बावजूद टीम में एक नया जोश और उत्साह देखने को मिला?**

-पहले तीन मैच हारने के बाद माहौल काफी गमगीन हो गया था। टीम के खिलाड़ियों से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक सभी काफी निराश थे और कोच शोर्ड मारिन ने भी कहा कि आप किस तरह हाकी खेल रहे हैं। मैं आपके साथ काफी सालों से काम कर रहा हूं। इस तरह की हाकी खेलने का आपका अंदाज नहीं है। खासतौर पर ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ टीम ने जिस तरह मैच छोड़ दिया था। उस चीज से सब काफी निराश थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने प्रेरित भी किया और मैंने भी अपनी टीम से कहा था कि जो हो गया उसे भुला दीजिए और हमें अच्छी हाकी खेलनी है। नतीजे की परवाह नहीं करनी है।

● **ओलिंपिक से पहले आपके कोच मरीन ने कहा था कि उनका लक्ष्य इस टीम को क्वार्टर फाइनल तक लेकर जाना है लेकिन आप लोग सेमीफाइनल तक खेलें और अब वह टीम को छोड़कर भी जा रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?**

-देखिए ओलिंपिक में कोई भी टीम जब खेलने जाती है न तो उसका प्रमुख लक्ष्य क्वार्टरफाइनल ही होता है। क्योंकि उसके बाद खेल पूरी तरह से खुल चुका होता है और सबको एक-दूसरे के खेल की पूरी तरह से जानकारी हो चुकी होती है। अब वह जा रहे हैं तो हमें उनकी काफी याद आएगी लेकिन उन्होंने एक साल पहले ही बता दिया था कि वह ओलिंपिक के बाद नहीं रुकेंगे। अगर कोरोना न होता तो वह पिछले साल ही चले गए होते। हम उनके फैसले का सम्मान भी करते हैं। अपने परिवार से दूर रहकर दूसरे देश में काम करना इतना आसान नहीं होता है। उनके सानिध्य में टीम ने काफी कुछ सीखा है, जिसे हम आगे भी जारी रखना चाहेंगे।

● **कोच ने शुरू की तीन हार के बाद एक फिल्म दिखाकर टीम को प्रेरित किया था। उसका नाम क्या आपको मालूम है। किस तरह की मूवी थी, जिससे प्रेरित होकर टीम ओलिंपिक में पदक के इतने करीब पहुंच सकी?**

-सच बात तो यह है कि मुझे भी उस फिल्म का नाम नहीं पता है। उस मूवी में बस यही दिखा रहे थे कि एक एथलीट होता है, वह खुद को वर्तमान की स्थिति में रखने के लिए एक कमरे में बंद कर लेता है। इस तरह की वह फिल्म थी, मुझे बस उस मूवी से यही समझ आया कि कोच मरीन हमसे वर्तमान में रहने की बात कर रहे हैं और पिछली तीन हार को भुलाने के लिए उन्होंने यह सब कुछ किया। इस मूवी के बाद वाकई टीम प्रेरित हुई और हम सबने आगे अच्छी हाकी खेली।

कोच शोर्ड मारिन के साथ भारतीय महिला हाकी कप्तान रानी रामपाल ● फाइल फोटो, प्रेट्र

● **विश्व चैंपियनशिप में पांच पदक, एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स और अब ओलिंपिक में दो पदक। अब तक सिंधू ने क्या पाया है और आगे का लक्ष्य क्या है?**

-विश्व चैंपियनशिप से पदक लेकर आना, वो भी पांच बार मायने रखता है। एशियन गेम्स में, कामनवेल्थ गेम्स में और ओलिंपिक में दूसरी बार पदक लेकर आना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हर साल हर समय मैं अपने खेल में निखार लाती गई और बहुत सीखी भी हूं। हार-जीत तो लगी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अभी मैं आराम कर रही हूं और इस पल का आनंद ले रही हूं। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं और उसके लिए तैयारी करनी है। अभी बहुत टूर्नामेंट हैं। अगले साल एशियन गेम्स व कामनवेल्थ गेम्स हैं तो उसके लिए भी तैयारी करनी हैं।

> उम्मीद है कि मैं पेरिस में भी पदक लेकर आऊंगी। उससे पहले भी मुझे बहुत टूर्नामेंट खेलने हैं। अक्टूबर से कुछ टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं। कामनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स हैं, उसमें भी अच्छा करूंगी।

● **आपसे पदक की उम्मीद थी और आपने वो किया भी। भारतीय पुरुष हाकी टीम ने 41 साल बार पदक जीता। महिला हाकी टीम का भी अच्छा प्रदर्शन रहा और नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। एक भारतीय एथलीट होने पर कितना गर्व हो रहा है?**

-मैं सभी एथलीटों का धन्यवाद करती हूं जो पदक लेकर आए हैं और जो भी अच्छा खेले। कई वर्षों के बाद पुरुष हाकी टीम कांस्य पदक लेकर आई। मैं महिला टीम को भी बधाई देती हूं, वे सेमीफाइनल तक पहुंचीं। उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी लेकिन हार-जीत तो होती रहती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हमें अपना 100 प्रतिशत देना है। मुझे विश्वास है कि वो लोग जान लगाकर खेले थे, लेकिन बस पदक से चूक गए। सारे एथलीटों ने बहुत अच्छा खेला। पदक जीतना और हारना, ये होता रहता है। गोल्फ में भी अदिति अशोक चौथे स्थान पर रही थीं। वह उनका दिन नहीं था। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना ही बड़ी बात है इसलिए मैं प्रत्येक खिलाड़ी को बधाई देती हूं। नीरज ने तो माहौल ही बदल दिया।

● **जैसे क्रिकेटर के कुछ खास बल्ले होते हैं, नीरज का भी एक खास भाला है, वैसे क्या आपका भी कोई पसंदीदा रैकेट है?**

-हमारा खेल कुछ अलग है। हम छह-सात रैकेट लेकर जाते हैं। खेलते समय कभी-कभी स्ट्रिंग चला (तार टूटना) जाता है, तो दूसरे रैकेट से खेलना पड़ता है। ऐसे में कोई खास रैकेट तो नहीं लेकिन पदक जीतने के बाद मैं हमेशा वह रैकेट रख लेती हूं।

● **अब तो रैकेट का भंडार लग गया होगा क्योंकि आपने बहुत पदक जीते हैं?**

-जी आप सही कह रहे हैं (जोर से हंसते हुए)।

● **घर में किस तरह का माहौल रहता है। क्या मम्मी कहती हैं कि इतना समय मुझसे दूर रहती हो, अभी यहीं रहो या ये खाओ, या फिर गेम पर बात होती है?**

-बहुत दिन के बाद घर वापस आई थी। कोरोना के समय में मम्मी-पापा बहुत चिंतित थे और बोल रहे थे कि अपना ध्यान रखो। शारीरिक दूरी का ध्यान रखो क्योंकि पता नहीं था कि कोविड कैसे आएगा और क्या होगा। भारत से टोक्यो जाना और वहां खेलना, वे थोड़े से चिंतित थे लेकिन पदक लाने के बाद सभी लोग खुश थे। इसका जश्न भी मनाया था।

> मोदी जी ने ओलिंपिक जाने से पहले प्रत्येक खिलाड़ी का बहुत हौसला बढ़ाया था और मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करती हूं। उन्होंने मेरे माता-पिता से भी बात की थी। मुझे बोला भी था कि पदक लेकर आने के बाद आइसक्रीम खाएंगे। पदक आने के बाद भी उन्होंने फोन करके बधाई दी थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बधाई दी थी। 15 अगस्त को मोदी जी से मिलने के लिए हम दिल्ली जाएंगे। उम्मीद है हम आइसक्रीम खाएंगे।

● **मैंने ओलिंपिक का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल देखा। क्वार्टर फाइनल में एक अलग तरह की सिंधू नजर आ रही थी लेकिन सेमीफाइनल में ताई जी यिंग के सामने अलग सिंधू थे। आपसे स्मैश नहीं लग रहे थे?**

-ताई बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं। मैं उनके खिलाफ तैयार थी। हम दोनों एक-दूसरे के खिलाफ हमेशा से 100 प्रतिशत देते हैं। ओलिंपिक से पहले हम दोनों शीर्ष फार्म में थे। पहला गेम बहुत अच्छा था। गेम 18-18 से बराबरी पर था और शायद उसका शटल नेट से लगकर मेरी तरफ गिर गया। वह किस्मत वाली थी। मैंने सोचा कि शायद मैं पहला गेम जीतती तो दूसरा गेम अलग होता, लेकिन बस वह उनका दिन था। मैंने भी 100 प्रतिशत कोशिश की थी लेकिन वह मेरा दिन नहीं था। 18-18 की बराबरी पर अगर मैं दो अंक ले लेती तो कुछ अलग होता।

● **सेमीफाइनल में कुछ ऐसा हो रहा था कि आप शाट मार रही थी तो शटल या तो कोर्ट के बाहर जा रही थी या नेट से लगने के बाद आपकी तरफ गिर रही थी जिससे ताई को अंक मिल रहे थे?**

- पहले गेम की तुलना में दूसरे गेम में नुकसान ज्यादा था। मैच भी थोड़ा तेज था। शटल कोर्ट से बाहर जा रही थी। पहला गेम जीत लेती तो दूसरा अलग हो जाता। मैंने बहुत नियंत्रण किया था। हां, लेकिन उस दौरान बेजा गलतियां ज्यादा हो रही थीं।

● **रियो ओलिंपिक के फाइनल में कैरोलिना मारिन के सामने भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था। बड़े मुकाबलों में क्या ज्यादा दबाव रहता है आप पर?**

-विश्व के टाप-10 खिलाड़ी उच्च स्तर के होते हैं। ओलिंपिक में सब लोग शीर्ष फार्म में रहते हैं और अपना 100 प्रतिशत देते हैं। बहुत कुछ इस बात पर तय होता है कि उस दिन कौन अच्छा खेलता है और कौन नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक खिलाड़ी अच्छा खेलता है और एक पर दबाव रहता है। दबाव तो हर किसी पर रहता है।

● **आपके कोच पार्क की काफी तारीफ हो रही है। उनके साथ कैसा तारतम्य रहता है और आपके गेम पर उसका कितना असर पड़ा है?**

- मैं पार्क के साथ एक साल से ज्यादा समय से अभ्यास कर रही हूं। वह बहुत उत्साह बढ़ाते हैं। उन्होंने हिंदी में 'आराम से' बोलना सीखा था। जब मैं खेलती हूं और अंक जा रहे होते हैं तो वह बोलते हैं कि आराम से, रिलेक्स। उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की थी। उनका भी एक सपना था कि ओलिंपिक से पदक लेकर आना है और वह पूरा हुआ। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। कोरोना के समय में उन्होंने मेरा गेम में काफी सुधार किया था। स्किल और तकनीक के ऊपर बहुत काम किया था। मैं उनका धन्यवाद करती हूं। खुशी कि बात है कि हम दोनों मेहनत करके देश के लिए पदक लाए।

● **पार्क और आपके पूर्व कोच पुलेला गोपीचंद के स्टाइल में क्या अंतर है। आपको किसका स्टाइल आरामदायक लगता है। इनके प्लस पाइंट क्या हैं?**

-हर कोच और खिलाड़ी की अलग-अलग स्किल और तकनीक रहती है। हर कोच अलग सोचता है। यह अच्छा है कि अलग-अलग तरह के कोचों से अलग-अलग स्किल और तकनीक सीखने को मिलती है। जब से मैंने बैडमिंटन शुरू खेलना शुरू किया तब से अब तक बहुत कोच रहे। मूल्यो भी थे, किम भी थे, अब पार्क हैं। तो बहुत कोच थे। मैं हर कोच का धन्यवाद करती हूं कि मैं उनसे कुछ न कुछ सीखी जरूर हूं।

एक नजर में

शाकिब और स्टेफनी बने जुलाई के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

दुबई: बांग्लादेश के आलराउंडर शाकिब अल हसन और वेस्टइंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में आइसीसी का जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। शाकिब के शानदार प्रदर्शन से बांग्लादेश ने जिंबाब्वे के खिलाफ टी-20 व वनडे सीरीज जीती थी। वहीं, वेस्टइंडीज ने स्टेफनी टेलर की अगुआई में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में हराया। (प्रेट्र)

डब्ल्यूटीसी अंक कटे

दुबई: आइसीसी ने नाटिंघम में पहले टेस्ट मैच में धीमी ओवर गति के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों पर मैच शुल्क का 40 प्रतिशत जुर्माना लगाने के अलावा उनके आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के दो-दो अंक भी काट दिए हैं। इन दोनों टीमों ने नियत समय में दो-दो ओवर कम किए थे, जिसके बाद आइसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्राड ने उन पर यह जुर्माना लगाया। (प्रेट्र)

बुमराह की शीर्ष 10 में वापसी

दुबई: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में वापसी की है लेकिन कप्तान विराट कोहली (791 अंक) बल्लेबाजी रैंकिंग में पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट उनकी जगह चौथे स्थान पर काबिज हो गए हैं। शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड कप्तान केन विलियमसन 901 अंकों के साथ विराजमान हैं। (प्रेट्र)

श्रेयस अय्यर फिट

नई दिल्ली : भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) ने प्रतिस्पर्धी मैचों में वापसी करने के लिए पूरी तरह से फिट घोषित कर दिया है और वह आइपीएल के 19 सितंबर से शुरू होने वाले दूसरे चरण में खेलने के लिए तैयार हैं। (प्रेट्र)

इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट आज से, शार्दुल-ब्राड बाहर, एंडरसन का खेलना भी संदिग्ध

हार का तिलिस्म तोड़ने उतरेगा भारत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : भारतीय टीम गुरुवार को लाड्र्स के मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में हार के तिलिस्म को तोड़ना चाहेगी। भारतीय टीम अभी तक यहां पर सिर्फ दो टेस्ट मैच ही जीत पाई है। हालांकि इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। दुनिया के धुरंधर बल्लेबाज होने के बावजूद भारतीय टीम नाटिंघम में पहले टेस्ट में बड़ा स्कोर नहीं बना पाई थी। इस समय दोनों टीमें संकट में हैं क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर चोटिल हैं तो दूसरी ओर इंग्लैंड के दो धुरंधर स्टुअर्ट ब्राड और जेम्स एंडरसन के भी चोट लगी हैं।

शार्दुल हैमस्ट्रिंग के कारण दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। ब्राड पिंडली की मांसपेशियों के फटने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। एंडरसन भी मांसपेशियों में दर्द से परेशान हैं उनका खेलना भी संदिग्ध है। इंग्लैंड ने ब्राड की जगह तेज गेंदबाज साकिब महमूद को बैकअप के तौर पर पहले ही बुला लिया था।

शतक को तरसते भारतीय बल्लेबाज : बारिश के कारण ड्रा छूटे पहले टेस्ट मैच में भारत जीत की अच्छी स्थिति में था लेकिन उसका पहली पारी का 278 रन का स्कोर अपेक्षानुरूप नहीं था। भारत के तीन प्रमुख बल्लेबाज कप्तान कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे इस पारी में नाकाम रहे थे। रहाणे के मेलबर्न में लगाए गए शतक को छोड़ दिया जाए तो ये तीनों पिछले दो वर्षों से बड़ी पारियां नहीं खेल पाए हैं। कोहली और पुजारा इस बीच अपनी अच्छी शुरुआत को शतक में नहीं बदल पाए हैं। मयंक अग्रवाल अब फिट हैं लेकिन केएल राहुल ने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करके शीर्ष क्रम में अपनी जगह पक्की की है। पुजारा और रहाणे भले ही अपनी सर्वश्रेष्ठ फार्म में नहीं हैं लेकिन उन्हें चोटिल होने की स्थिति में ही बाहर रखा जा सकता है।

लाड्र्स में टीम संयोजन भी चिंता का विषय : लाड्र्स की पिच हमेशा से अपनी एक तरफ ढलान के कारण तेज गेंदबाजों के मुफीद रही है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जैसे संकते दिए हैं उसमें यही लगता है कि वह शार्दुल की जगह किसी तेज गेंदबाज को ही रखेंगे। ऐसे में इशांत शर्मा या उमेश यादव में से किसी को मौका मिलेगा।

पिच का व्यवहार : भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड 2018 की तरह इस बार भी पिच पर घास रखना चाहेगा क्योंकि तब भारतीय बल्लेबाजी दो दिन में ढह गई थी और आलराउंडर क्रिस वोक्स इंग्लैंड की जीत के नायक बने थे।

इंग्लैंड की बल्लेबाजी है कमजोर कड़ी : इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है। कप्तान जो रूट ने पहली पारी में अर्धशतक और दूसरी पारी में शतक जमाया था। ब्राड के नहीं होने के कारण उनको और परेशानी होगी। अगर एंडरसन नहीं खेले तो टीम की हालत और खराब होगी। ऐसे में मार्क वुड, मोईन अली और साकिब महमूद में से किसी दो को मौका मिल सकता है।

लाड्र्स में अभ्यास करते भारतीय टीम के खिलाड़ी ● फाइल फोटो, एपी

20 विकेट लेने जरूरी : कोहली

लंदन, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अंतिम एकादश में शार्दुल की जगह दूसरे खिलाड़ी को शामिल करने पर कहा, 'रोहित और राहुल पहले टेस्ट में अच्छा खेले। हम बल्लेबाजी इकाई के रूप में काफी सहज थे। हमें नहीं लग रहा कि अगर शार्दुल नहीं खेलता है तो हमारे पास एक बल्लेबाज कम रहेगा। निश्चित तौर पर हमें सोचना होगा कि हम 20 विकेट कैसे चटकाएंगे और किसी भी ऐसे खिलाड़ी को शामिल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो बल्ले से कुछ रन बनाए।'

भारत vs इंग्लैंड

मैच	18
जीता भारत	2
हारा भारत	12
ड्रा	4

टीमें

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, पुजारा, मयंक, रहाणे (उपकप्तान), हनुमा, रिषभ पंत (विकेटकीपर), आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मुहम्मद शमी, मुहम्मद सिराज, उमेश यादव, केएल राहुल, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), अभिमन्यु ईश्वरन, पृथ्वी शा, सूर्यकुमार यादव में से।

इंग्लैंड: जो रूट (कप्तान), एंडरसन, बेयरस्टो, डोम बेस, मोईन, रोरी बर्न्स, बटलर, जैक क्राली, सैम कुर्रन, हसीब, लारेंस, जैक लीच, ओली पोप, राबिंसन, साकिब महमूद, डोम सिब्ली, मार्क वुड में से।

454 रन टेस्ट की एक पारी में भारत ने 1990 में लाड्र्स में बनाए थे। कप्तान कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम की बल्लेबाजी अगर यादगार प्रदर्शन करती है तो इस रिकार्ड को भी तोड़ सकती है

7 विकेट सबसे अधिक अभी तक भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने वर्ष 2014 के लाड्र्स टेस्ट की एक पारी में लिए थे

184 रन के साथ लाड्र्स में सबसे अधिक रनों की पारी खेलने वाले वीनू मांकड इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। इसे भरतीय बल्लेबाज तोड़ना चाहेंगे

12 विकेट इशांत लाड्र्स में तीन टेस्ट में ले चुके हैं। अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो वह एक विकेट लेते ही कुंबले से आगे निकल जाएंगे। बेदी (4 मैच 17 विकेट) और कपिल देव (4 मैच 17 विकेट) उनसे आगे रहेंगे

28 विकेट एंडरसन ने भारत के खिलाफ चार टेस्ट मैचों में लाड्र्स में लिए हैं

> ब्राड और एंडरसन के बिना उतरना टीम के लिए बड़ा नुकसान है। ब्राड और एंडरसन ने मिलकर 1000 से अधिक विकेट लिए हैं। चोट और बीमारी चलती रहती हैं। आपको टीम के भीतर सामंजस्य बिठाना होता है। हम पेशेवर क्रिकेट खेल रहे हैं। **जानी बेयरस्टो,** इंग्लिश क्रिकेटर

खेल डायरी

राफेल नडाल टोरंटो टूर्नामेंट से बाहर

टोरंटो, एपी : राफेल नडाल बायें पांव की चोट के कारण नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हट गए हैं, जिससे उनकी यूएस ओपन की तैयारियों को झटका लगा है। 20 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन नडाल के स्थान पर फेलिसियानो लोपेज को इस हार्डकोर्ट टूर्नामेंट के ड्रा में शामिल किया गया है। लोपेज क्वालीफाईंग में हार गए थे। नडाल ने कहा, 'मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं टेनिस खेलने का पूरा आनंद लूं। लेकिन इस दर्द के साथ मैं उसका आनंद नहीं उठा सकता।' वहीं अन्य टेनिस खिलाड़ी रूस के डेनिल मेदवेदेव ने कजाखस्तान के एलेक्सांद्र बुबलिक को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर इस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में प्रवेश किया।

विलियम्स बहनें व केनिन सिनसिनाटी टूर्नामेंट से बाहर : सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स और सोफिया केनिन मंगलवार को सिनसिनाटी ओपन (वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन) टेनिस टूर्नामेंट से हट गईं। सेरेना और केनिन चोटिल हैं लेकिन वीनस विलियम्स के हटने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। सेरेना ने दायें पांव में चोट के कारण 29 जून को विंबलडन में अपने पहले दौर के मैच से हटने के बाद कोई मैच नहीं खेला है।

41 साल बाद ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हाकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह अपनी मां के गले में पदक डालकर गोद में सो गए ● ट्विटर

पीएसजी से जुड़े मेसी नेमार संग खेलेंगे

पेरिस, एपी : शुरू से लेकर अब तक स्पेनिश क्लब बार्सिलोना की तरफ से खेलने वाले लियोन मेसी मंगलवार को फ्रांसीसी फुटबाल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) से जुड़ गए, जहां वह अपने दोस्त और स्टार ब्राजीली स्ट्राइकर नेमार के साथ खेलते नजर आएंगे।

अर्जेंटीना के 34 वर्षीय फारवर्ड खिलाड़ी मेसी ने मंगलवार को पीएसजी के साथ दो साल का करार किया। इसमें तीसरे साल का विकल्प भी रखा गया है। मेसी ने रविवार को बार्सिलोना से विदाई ली थी। अब उनका कुल वेतन 35 मिलियन यूरो (लगभग तीन अरब रुपये) होगा। मेसी पीएसजी के लिए 30 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते दिखाई देंगे। इस नंबर की जर्सी से उन्होंने वर्ष 2004 में पेशेवर फुटबाल बार्सिलोना के लिए खेलना शुरू किया था। पीएसजी में 10 नंबर जर्सी के साथ पहले से ही नेमार खेलते हैं। मेसी के आने से पीएसजी के पास अब दुनिया का सबसे मजबूत आक्रमण हो गया है। उसके आक्रमण में अब मेसी, नेमार, अर्जेंटीना के एंजेल डि मारिया और फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर काइलन एमबापे शामिल हैं। पीएसजी शनिवार को स्ट्रासबर्ग के खिलाफ मैच से पहले पार्क डेस प्रिंसेस स्टेडियम में 50,000 दर्शकों के सामने मेसी का परिचय कराएगा।

पीएसजी के लिए चैंपियंस लीग ट्राफी जीतना चाहते हैं मेसी : पीएसजी से जुड़ने के बाद लियोन मेसी ने कहा कि वह एक और चैंपियंस लीग ट्राफी जीतने के लिए सही जगह पहुंच गए हैं और उन्होंने पीएसजी से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण नेमार के साथ मिलकर खेलना बताया। मेसी ने कहा, 'मेरा लक्ष्य और सपना एक और चैंपियंस लीग ट्राफी को हाथों में उठाना है और मुझे लगता है कि मैं इसे हासिल करने के लिए सही जगह पर हूं। जब आप टीम पर नजर डालते हो तो आप वास्तव में उनके साथ खेलना चाहते हो क्योंकि यहां काफी संभावनाएं हैं। हम सभी का एक ही लक्ष्य है। नेमार ने वास्तव में बहुत कुछ किया है और मेरा यहां आने के लिए वह महत्वपूर्ण कारण था।' पीएसजी चैंपियंस लीग जीतने के लिए बेताब है। वह 2020 के फाइनल में बायर्न म्यूनिख से हार गया था। मेसी ने बार्सिलोना को चार चैंपियंस लीग ट्राफी दिलवाई हैं।

> यह बात पूरी तरह से गलत है कि बार्सिलोना से मेसी के जुदा होने में मेरा हाथ है। बार्सिलोना के सीईओ फेरान रिवर्टर और मैं पुराने दोस्त नहीं हैं। मेरी पिछले सप्ताह ही दो बार मुलाकात हुई है। लेकिन तब तक मेसी पर फैसला लिया जा चुका था।
> **फ्लोरेंटिनो पेरेज,** अध्यक्ष, रीयल मैड्रिड क्लब

पीएसजी में अपनी 30 नंबर की नई जर्सी दिखाते लियोन मेसी। वह अर्जेंटीना में 10 नंबर की जर्सी पहनते थे ● एएफपी

इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अगर यहां पर थोड़े से लापरवाह होते हैं, तो फिर आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। इंटरनेट की दुनिया में आजादी के साथ सुरक्षित भी रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना होगा...

फोटो : इमेजेज बाजार

इंटरनेट की दुनिया ऐसे फील करें आजादी

टेक गाइड

आजकल अधिकतर लोग इंटरनेट मीडिया, आनलाइन एजुकेशन, रिमोट वर्क, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग आदि के लिए इंटरनेट पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं। मगर अभी भी बहुत से ऐसे इंटरनेट यूजर्स हैं, जो इस माध्यम का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं या अगर जानते भी हैं, तो वे यहां पर लापरवाह तरीके से सर्फिंग करते हैं। यदि इंटरनेट इस्तेमाल करने के दौरान बुनियादी बातों का पालन नहीं करते हैं, तो इसका फायदा साइबर ठग उठा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के कई तरीके मौजूद हैं। आप इंटरनेट के बेसिक रूल्स को अपना लेते हैं, तो फिर यहां पर आजादी के साथ सर्फिंग कर सकते हैं।

गोपनीय डाटा रखें आफलाइन : आजकल लोग अपनी संवेदनशील जानकारियों को ईमेल्स, फोन-पीसी आदि पर सेव करके रखते हैं। मगर संवेदनशील डाटा को आनलाइन के बजाय आफलाइन सेव कर रखते हैं, तो यह आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस तरह कभी भी साइबर क्रिमिनल आपकी जानकारी तक नहीं पहुंच सकते। पीसी-फोन आदि पर महत्वपूर्ण जानकारियों को सेव करना भले ही अधिक सुविधाजनक हो, लेकिन आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल आदि को आफलाइन सेव करना ही ज्यादा बेहतर हो सकता है। हालांकि जब आपको महत्वपूर्ण फाइल्स आदि को साझा करनी हो, तो ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही, भेजने से पहले फाइल को एनक्रिप्ट करने के लिए एएक्स क्रिप्ट, क्रिप्टो एक्सपर्ट, वेराक्रिप्ट जैसे साफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। इससे फाइल्स की सिक्योरिटी को लेकर चिंता से मुक्त हो सकते हैं।

कहीं भी साइनइन करने से बचें : कई बार जब आप अलग-अलग साइट पर विजिट करते हैं, तो साइनइन करने के लिए कहा जाता है। इसमें आपको फोन नंबर, फेसबुक, गूगल एकाउंट, ट्रूकालर आदि से भी साइनइन करने के विकल्प मिलते हैं। कई बार तो लोग बिना सोचे-समझे साइनइन बटन पर प्रेस कर देते हैं। ऐसा करने से अपनी प्राइवेसी को आनलाइन एक्सपोज कर सकते हैं। इसलिए केवल विश्वसनीय वेबसाइट पर ही साइनअप करें। अगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि कोई वेबसाइट विश्वसनीय है या नहीं? इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट की एड्रेस बार के शुरुआत में पैडलाक की जांच कर लें। यदि यह है, तो इसका मतलब है कि कनेक्शन एनक्रिप्ट किया गया है।

पासवर्ड के प्रति गंभीरता दिखाएं: आमतौर पर जब आनलाइन एकाउंट को सिक्योर रखने की बात आती है, तो लोग पासवर्ड के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं होते। उन्हें लगता है कि यदि स्ट्रांग या फिर यूनिक तरीके का पासवर्ड होगा तो फिर उसे याद कैसे रखेंगे। इसलिए लोग आसान पासवर्ड की तरफ रुख करते हैं, लेकिन यह आपके एकाउंट को असुरक्षित बनाता है, जहां पर आपकी बहुत-सी महत्वपूर्ण जानकारियां स्टोर होती हैं। पासवर्ड जितना जटिल और मजबूत होगा, आपका एकाउंट भी उतना अधिक सुरक्षित होगा। मजबूत पासवर्ड में कम से कम 12 कैरेक्टर होने चाहिए। शब्दों के साथ अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण भी होना चाहिए। यूनिक पासवर्ड के लिए आनलाइन पासवर्ड जनरेटर में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। यदि पासवर्ड को याद रखने में समस्या आती है, तो फिर पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही, पासवर्ड की मजबूती की जांच नार्डपास व यूआइसी एकेडमिक की वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं।

2फैक्टर आथेंटिकेशन का करें उपयोग: यह आपके एकाउंट के लिए अतिरिक्त सिक्योरिटी प्रदान करता है। जब आप 2 फैक्टर आथेंटिकेशन के साथ एकाउंट को साइनइन करते हैं, तो आपको न केवल सही पासवर्ड दर्ज करना होगा, बल्कि आपके फोन पर एक कोड भी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करने पर भी एकाउंट को ओपन कर पाएंगे। इसलिए अगर किसी को पासवर्ड का पता चल भी जाता है, तो वह आपके एकाउंट को ओपन नहीं कर पाएगा। मोबाइल पर आए सिक्योरिटी कोड के बिना एकाउंट को ओपन करना संभव नहीं होगा। इसका इस्तेमाल वाट्सएप, जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एकाउंट आदि के साथ भी कर सकते हैं।

संदिग्ध आनलाइन लिंक से बचें : जब आनलाइन सर्च करते हैं, तो फिर आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि कुछ खास तरह की आनलाइन सामग्री से बचना चाहिए। इनमें संदिग्ध लिंक, स्पैम मेल, आनलाइन क्विज, मुफ्त आफर या अवांछित विज्ञापन आदि शामिल हैं। इन्हें पहचानना आसान है। सभी आपसे क्लिक करने या फिर ओपन करने का आग्रह करेंगे। यदि संदिग्ध ईमेल अटैचमेंट है, तो टेक्स्ट में फाइल का उल्लेख नहीं होगा। इसके अलावा, हमेशा आथराइज्ड प्लेटफार्म से ही एप्स या फिर दूसरी चीजों को डाउनलोड करें।

पीसी-मोबाइल को अपडेट रखः यह महत्वपूर्ण है कि आप आपरेटिंग सिस्टम और एप्स के लेटेस्ट वर्जन का ही उपयोग करें। डेवलपर्स प्रोडक्ट को सेफ बनाने के लिए लेटेस्ट थ्रेट की मानिटरिंग करने के बाद सुरक्षा पैच जारी करते हैं। इसलिए साफ्टवेयर को अपडेट करते रहें।

इंटरनेट मीडियाः जब इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर कुछ शेयर करते हैं, तो इसे सभी देख सकते हैं। इसलिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर क्या शेयर कर रहे हैं, इसको लेकर सतर्क रहें। अगर प्राइवेसी सेटिंग्स कमजोर हैं, तो आप खुद को आनलाइन खतरों के लिए असुरक्षित बना रहे हैं। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि इस पोस्ट को सार्वजनिक करना है या नहीं, तो आडियंस के लिए फ्रेंड्स का चयन करें, पब्लिक का नहीं। अपनी टाइमलाइन पर दूसरों की पोस्ट को डिसेबल करें। इस तरह अगर आप इंटरनेट पर प्राइवेसी को मजबूत कर लेते हैं, तो फिर यहां पर आजाद व सुरक्षित तरीके से सर्फिंग करने में दिक्कत नहीं होगी।

अमित निधि

बच्चों को भी सिखाएं इंटरनेट सेफ्टी

कंटेंट शेयर करने के फैमिली रूल्स : पूरी फैमिली के लिए एक नियम बनाएं और बच्चों को बताएं कि किस तरह के कंटेंट को आनलाइन शेयर करना है और किसे नहीं। खासकर तस्वीरें और व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि घर का पता, फोन नंबर आदि आनलाइन नहीं शेयर किए जाने वाली सूची में टाप पर होने चाहिए।

फिशिंग को पहचानना सिखाएं : बच्चों को फिशिंग का पता लगाने में मदद करें। बच्चे को बताएं कि अजनबियों द्वारा एकाउंट की जानकारी मांगने या अजीब अटैचमेंट वाले मैसेज, लिंक्स या ईमेल से कैसे बचें।

मजबूत पासवर्ड बनाना : बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे अलग-अलग सिंबल और कैरेक्टर्स के मेल से प्रभावी पासवर्ड तैयार किया जा सकता है। साथ ही, उन्हें यह भी बताएं कि पासवर्ड को किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।

सकारात्मक संवाद के लिए करें प्रोत्साहित : अपने बच्चों को आनलाइन भी विनम्रता से व्यवहार करने का महत्व समझाएं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे खुद अपने लिए चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल यानी आफलाइन की दुनिया में होता है।

डिजिटल फुटप्रिंट : आजकल डाटा चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। बताएं कि आनलाइन दुनिया में डिजिटल फुटप्रिंट को कैसे कम कर सकते हैं।

टिप्स ऐंड ट्रिक्स

वाट्सएप से डाउनलोड करें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट

कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। सरकार इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। इसी साल कोरोना वायरस की सही जानकारी देने के लिए वाट्सएप चैटबाट लांच किया था। जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, वे अब MyGov कोरोना हेल्पडेस्क वाट्सएप चैटबाट के माध्यम से अपने कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे। जानते हैं डाउनलोड करने का चरणबद्ध तरीका...

कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से पहले वाट्सएप लिस्ट में MyGov कोरोना हेल्पडेस्क चैटबाट को जोड़ना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर +91-9013151515 को अपनी कांटैक्ट लिस्ट में जोड़ लें। बेहतर होगा कि इसे MyGov WA चैटबाट के रूप में सेव करें। इससे सर्च करने में आसानी होगी। चैटबाट के माध्यम से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लिया हुआ होना चाहिए।

वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के स्टेप्स

- अपने स्मार्टफोन में वाट्सएप को ओपन करें। फिर वाट्सएप सर्च बार से MyGov चैटबाट वाले नंबर को ओपन करें।
- अब चैट विंडो में डाउनलोड सर्टिफिकेट टाइप करें। वाट्सएप पर अपना कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मैसेज भेजें।
- फिर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा। यहां आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपका नाम कोविन प्लेटफार्म पर एक अलग फोन नंबर के साथ रजिस्टर्ड है, तो फिर चैटबाट आपको अपने नंबर से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की अनुमति नहीं देगा। उस स्थिति में आपको वह नंबर दर्ज करना होगा, फिर उसी पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा।
- चैट विंडो में ओटीपी दर्ज करें। यदि रजिस्टर्ड नंबर से कई सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, तो चैटबाट प्रत्येक सदस्य के सर्टिफिकेट को अलग-अलग डाउनलोड करने का विकल्प दिखाएगा।
- अब वाट्सएप चैट विंडो में उस सदस्य का चयन करें, जिसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं।
- इसके बाद चैटबाट आपके डिवाइस पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का पीडीएफ भेजेगा, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं।

फीचर डेस्क

हैवी फाइल्स ऐसे करें शेयर

फाइल शेयरिंग प्लेटफार्म

जब आप मोबाइल या फिर पीसी से फाइल शेयर करने की सोचते हैं, तो अधिकतर प्लेटफार्म पर फाइल साइज की एक लिमिट होती है। आप उससे बड़ी फाइल को शेयर नहीं कर सकते हैं या फिर आपको पेड वर्जन के लिए जाना पड़ता है। लेकिन कुछ प्लेटफार्म हैं, जहां पर फाइल चाहे कितनी भी हैवी क्यों न हो आप उसे बड़ी आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं।

सेंड एनीवेयरः फाइल ट्रांसफर के लिए यह यूजफुल सर्विस है। चाहे कितनी भी बड़ी फाइल क्यों न हो, उसे बड़ी आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। यहां पर फाइल साइज की कोई लिमिट नहीं है यानी आप इमेज, वीडियो, आडियो व अन्य डाक्यूमेंट्स आसानी से शेयर कर पाएंगे। इस प्लेटफार्म की खास बात यह है कि फाइल को मूल साइज में भेजने की क्षमता है। यह उन लोगों के लिए विकल्प हो सकता है, जो फाइल की क्वालिटी से समझौता किए बिना शेयर करना चाहते हैं। यह फाइल भेजने और रिसीव करने के लिए छह डिजीट सिक्योरिटीज कीज प्रदान करता है। सिक्योर लिंक 48 घंटों के लिए वैध होता है। इसकी मदद से अपनी फाइलों को एक से अधिक लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। हालांकि फाइल को शेयर करने के लिए स्ट्रांग इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यह फ्री और पेड दोनों ही वर्जन में उपलब्ध है। यह एंड्रायड, आइओएस, मैकओएस, विंडोज, लिनक्स और वेब को सपोर्ट करता है।

स्नैपड्रापः यह फाइल शेयरिंग का आसान तरीका है। स्नैपड्राप की खास बात यह है कि फाइल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे आसानी से शेयर कर पाएंगे। इसका यूजर इंटरफेस एपल के एयरड्राप के मिलता-जुलता है। अच्छी बात यह है कि फाइल शेयरिंग के लिए अधिक कान्फिगरेशन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इस्तेमाल करने के लिहाज से उपयोगी है। हालांकि यह केवल एक वेब एप है, इसलिए फाइल शेयर के दौरान इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है।

ईएलएप नियरबाय शेयरिंगः यह क्रास-प्लेटफार्म को सपोर्ट करता है। यूजर इंटरफेस सिंपल है। इसकी मदद से एंड्रायड, आइओएस, विंडोज और मैकओएस के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं। इसे डिवाइस से कनेक्ट करना आसान होता है। इसकी मदद से 100 एमबी तक की फाइल को ट्रांसफर कर पाएंगे।

फीचर डेस्क

इंस्टाशेयर

इंस्टाशेयर सभी तरह की फाइल को सपोर्ट करता है। यहां फाइल शेयर और रिसीव करना आसान है। यहां भी फाइल साइज की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ तस्वीरें साझा कर रहे हैं या फिर अपने सहयोगी को एक बड़ा प्रोजेक्ट भेज रहे हैं। यहां बिना किसी परेशानी के फाइल शेयर कर पाएंगे। यह फाइल को तेज गति से ट्रांसफर करता है। पर आपको ध्यान रखना होगा कि यह केवल सात दिनों का ही फ्री ट्रायल प्रदान करता है। यह विंडोज, एंड्रायड, आइओएस और मैकओएस को सपोर्ट करता है।

एप बताएगा फोन में पेगासस है या नहीं

अगर आप आइफोन यूजर हैं, तो आपके लिए अब पेगासस स्पाईवेयर का पता लगाना आसान हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की डिजिडीएनए ने अपने आइओएस डिवाइस मैनेजर आइमैजिंग को स्पाईवेयर डिटेक्शन फीचर के साथ अपडेट किया है। इसकी मदद से अब पेगासस का पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि कंपनी ने एमनेस्टी के मोबाइल वेरिफिकेशन टूलकिट की मदद से इस फीचर को डेवलप किया है। मैक पीसी पर आइमैजिंग वेबसाइट से साफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इसे एमवीटी की फंक्शनैलिटी पर ही बनाया गया है जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पिछले महीने एक ओपन-सोर्स डेवलपमेंट के रूप में जारी किया था। फिलहाल यह केवल आइओएस डिवाइस के लिए डिजाइन किया गया है।

टेक अपडेट/लांच

नोकिया सी 20प्लस

नोकिया सी 20प्लस फोन भारत में लांच हो गया है। यह बजट फोन है। फोन में 6.5 इंच एचडी प्लस डिस्प्ले है। यह एंड्रायड 11 (गो एडिशन) पर चलता है। फोन में आक्टा-कोर यूनिसोक एससी 9863ए प्रोसेसर दिया गया है। यह दो जीबी और तीन जीबी रैम वैरियंट में उपलब्ध है। इंटरनल स्टोरेज 32जीबी है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें आठ एमपी का प्राइमरी कैमरा व दो एमपी का डेप्थ कैमरा है। सेल्फी के लिए पांच एमपी का कैमरा है। फोन में 4,950एमएएच की बैटरी दी गई है। 2 जीबी रैम + 32 जीबी स्टोरेज की कीमत 8,999 रुपये, जबकि 3 जीबी + 32 जीबी स्टोरेज की कीमत 9,999 रुपये है।

गैजेट रिव्यू

माइक्रोमैक्स इन 2बी

यह माइक्रोमैक्स का बजट फोन है। फोन के रियर पैनल पर ग्लासी मैट लुक है, इसलिए अंगुलियों के निशान नहीं दिखते। इस सेगमेंट के अधिकांश फोन की तरह इसमें 60हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। व्यूइंग एंगल ठीक है। हालांकि वाइडवाइन एल1 सर्टिफिकेशन नहीं है। फोन में 400 निट्स तक ब्राइटनेस है। वैसे, फोन सस्ता नहीं दिखता है। बिल्ड क्वालिटी बेहतर है। फोन यूएसबी-सी पोर्ट के साथ भी आता है, जिसे इस सेगमेंट में देखना हमेशा अच्छा लगता है। फिंगरप्रिंट सेंसर तेज और सटीक है। फोन के साथ अच्छी बात यह है कि बिना ब्लोटवेयर के स्टाक एंड्रायड जैसा अनुभव मिलता है। फोन 4 और6 जीबी रैम वैरियंट के साथ आता है। स्टोरेज 64 जीबी है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। फोन में यूनिसोक टी610 प्रोसेसर है, जो डेली टास्क के हिसाब से अच्छा परफार्म करता है। फोन में एंट्री लेवल गेम भी चला सकते हैं। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 13एमपी और सेकंडरी 2एमपी का डेप्थ कैमरा है। अगर अच्छी रोशनी हो तो फोन से बेहतर तस्वीरें मिलती हैं। 5एमपी का फ्रंट कैमरा भी रोशनी में ठीक-ठाक सेल्फी लेता है। कम रोशनी में तस्वीरें और बेहतर हो सकती थीं। 5,000एमएएच की बैटरी एक दिन आराम से साथ निभाती है। 4जीबी रैम वैरियंट की कीमत 7,999 रुपये है, जो इसे इस रेंज में एक अच्छा बजट डिवाइस बनाती है।

तकनीक और गैजेट से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए https://www.jagran.com/technology-hindi.html? **पर विजिट करें।**
अपनी राय हमें जरूर बताएं : feature@jagran.com

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थितिः 12 अगस्त, 2021 गुरुवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी का राशिफल।
आज का राहुकालः दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक।
आज का दिशाशूलः दक्षिण।
आज का पर्व एवं त्योहारः श्री गणेश चतुर्थी व्रत, दूर्वागणपति।
भद्राः दोपहर 03:25 बजे तक।

मेषः धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। व्यावसायिक योजना सार्थक होगी। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी।

वृषः किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। भाई-बहन से विवाद न करें। अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। रचनात्मक कार्यों में मन लगाएं।

मिथुनः शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कर्कः उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। गृह कार्य में व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुद्धि कौशल से किए गए कार्य में सफलता मिलेगी।

सिंहः किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी।

कन्याः पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

तुलाः शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक प्रयास सार्थक होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी।

वृश्चिकः आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन मन खिन्न रहेगा। उच्च अधिकारी या घर के मुखिया का सहयोग रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

धनुः व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। महिला अधिकारी से सहयोग लेने में सफल होंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

मकरः महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष में सुधार होगा।

कुंभः भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।

मीनः स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। संबंध मधुर होंगे।

कल 13 अगस्त का पंचांग

कल का दिशाशूलः पश्चिम।
कल का पर्व एवं त्योहारः नाग पंचमी, कालसर्प शांति पूजन।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी 13 घंटे 43 मिनट तक, तत्पश्चात् षष्ठी हस्त नक्षत्र 08 घंटे तक, तत्पश्चात् चित्रा नक्षत्र साध्य योग 13 घंटे 46 मिनट तक, तत्पश्चात् शुभ योग कन्या में चंद्रमा तत्पश्चात् तुला में।

वर्ग पहेली-1665

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
[illegible]

ऊपर से नीचे
[illegible]

कल का हल

जागरण सुडोकू-1665

7			3		6			2
					4		9	
	5			2		3		
8			6				5	
5	4			8	1	9		3
		1	9				6	
1		5		9		7		6
	6				2			4
4			1	6		5		

कल का हल

5	3	1	6	4	8	2	9	7
9	8	6	1	2	7	5	4	3
7	2	4	5	9	3	6	1	8
3	4	5	7	1	9	8	2	6
8	1	9	3	6	2	7	5	4
2	6	7	8	5	4	1	3	9
4	9	8	2	7	5	3	6	1
1	7	2	9	3	6	4	8	5
6	5	3	4	8	1	9	7	2

मौसम

कल पढ़ें

हुमा की हिम्मत

महामारी के बीच हुमा कुरैशी को फिल्म बेल बाटम के लिए प्रपोजल आया, तो उनके मन में भी कोरोना को लेकर डर था, लेकिन वह फिल्म को शूट करने के लिए स्काटलैंड गईं ताकि उन्हें देखकर बाकी लोगों का भी हौसला बढ़े। उनसे बातचीत के अंश...

भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत

1765 में आज ही मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के लार्ड राबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद (मौजूदा प्रयागराज) में अकबर के किले में संधि हुई थी। इसके तहत भारत में उसे प्रशासनिक अधिकार मिले। इससे पहले यह सिर्फ व्यापारिक कंपनी थी।

नासा ने अपना पहला संचार उपग्रह कक्षा में स्थापित किया

1960 में आज ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इकोाए को फ्लोरिडा से सफलतापूर्वक लांच किया था। यह दुनिया का दूसरा संचार उपग्रह था। इससे पहले रूस स्पुतनिक संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापिक कर चुका था। संचार क्रांति में इन उपग्रहों ने अहम भूमिका निभाई।

इसरो की स्थापना में विक्रम साराभाई ने निभाई थी भूमिका

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का जन्म आज ही 1919 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने इसरो की स्थापना के लिए सरकार को राजी किया था। उन्होंने तिरुअनंतपुरम के थुंबा गांव से 21 नवंबर, 1963 को एक छोटा राकेट लांच किया। बाद में इस प्रक्षेपण स्थल का नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रखा गया। देश की कई अहम संस्थाओं की स्थापना में योगदान रहा। 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण (मरणोपरांत) मिला। 1971 में उनका निधन हो गया।

इधर-उधर की

18.45 सेकेंड में यूट्यूबर ने पिया दो लीटर सोडा

वाशिंगटन, एजेंसी : जहां चाह, वहां राह। इंसान अगर अपने सपने को पूरा करने में जुट जाए तो असंभव काम भी आसान सा दिखता है। अमेरिका के न्यूयार्क के एरिक बुकर इसके पर्याय बन चुके हैं। दरअसल, शौकिया यूट्यूबर एरिक ने महज 18.45 सेकेंड में दो लीटर सोडा पीकर गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। गिनीज बुक ने अपनी वेबसाइट पर उनके इस कारनामे को बताया और कहा, एरिक हमेशा से ऐसा रिकार्ड बनाना चाहते थे और उन्होंने पूरा कर लिया। एरिक ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिये गिनीज बुक को धन्यवाद दिया और कहा, मेरा सपना पूरा हो गया। अब इनका सोडा पीकर रिकार्ड बनाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शख्स का गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। इंटरनेट मीडिया

बेपानी नहीं है चांद, मिल गया प्रमाण

बड़ी उपलब्धि ▶ आइआइआरएस के विज्ञानियों ने चंद्रयान-दो के अर्बिटर के आंकड़ों का किया विश्लेषण

चंद्रमा पर पूर्व के अनुमान से कहीं अधिक पानी की मौजूदगी

जागरण संवाददाता, देहरादून

चंद्रयान मिशन में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब हमारे विज्ञानी पुख्ता रूप से यह कहने की स्थिति में हैं कि चांद पर पानी है। चंद्रयान के आर्बिटर के इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्टोमीटर (आइआइआरएस) की ओर से भेजे गए आंकड़ों व चित्रों के विश्लेषण में चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल (वाटर मालीक्यूल्स या पानी के अणु) व एचटूओ (पानी) के प्रमाण मिले हैं। यह अध्ययन चांद के रहस्य को जानने में जुटे विश्वभर के विज्ञानियों के लिए भी बड़ी उम्मीद बनता दिख रहा है।

2019 में लांच किए गए चंद्रयान मिशन में यान के लैंडर व रोवर चांद की सतह पर उतरते समय क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन आर्बिटर अब भी चांद के ऊपर घूम रहा है। आर्बिटर के इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्टोमीटर से जो आंकड़े मिल रहे हैं, उसका विश्लेषण देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ रिमोट सेंसिंग (आइआइआरएस) समेत देश के विभिन्न विज्ञानी कर रहे हैं। आइआइआरएस के निदेशक प्रकाश चौहान के मुताबिक, चांद पर पानी के संकेत 29 डिग्री नार्थ से लेकर 62 डिग्री नार्थ के बीच मिले हैं। जिस क्षेत्र में सूरज की रोशनी पड़ती है, वहां पानी के संकेत मिल रहे हैं। पानी की उपलब्धता की दिशा में स्पेस वेदरिंग अहम भूमिका निभा रही है। यह वह प्रक्रिया होती है, जब सौर हवाएं चांद की सतह पर टकराती हैं। साथ ही इस प्रक्रिया कुछ अन्य कारक भी विभिन्न रासायनिक बदलाव कर पानी की उम्मीद को जन्म देते हैं।

चंद्रयान के आर्बिटर से भेजी गई चांद की सतह की तस्वीर। साभार- आइआइआरएस

निदेशक प्रकाश चौहान के मुताबिक, पूर्व में चंद्रयान-एक मिशन के दौरान की पानी के संकेत मिले थे। हालांकि, तब पानी की अधिक उपलब्धता का अनुमान नहीं था। वर्तमान अध्ययन से पता चलता है कि चांद में पानी की उपलब्धता 800 से 1000 पीपीएम (पाट्र्स पर मिलियन) पाई गई है। आर्बिटर के आइआइआरएस से प्राप्त हो रहे आंकड़ों का निरंतर विश्लेषण किया जा रहा है। उम्मीद है कि निकट भविष्य में चांद के तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठ पाएगा। वहीं, चंद्रयान-तीन मिशन के अगले साल लांच होने की उम्मीद है। ऐसे में नए मिशन के लिए पहले से तमाम बातें ऐसी होंगी, जिन पर खोज को केंद्रित किया जा सकता है।

अध्ययन में ये विज्ञानी भी रहे शामिल : ममता चौहान, प्रभाकर वर्मा, सुप्रया शर्मा, सताद्रु भट्टाचार्य, आदित्य कुमार डागर, अमिताभ, अभिषेक एन पाटिल, अजय कुमार पराशर, अंकुश कुमार, नीलेश देसाई, रितु करिधल व एएस किरन कुमार।

आकाशगंगा का अद्भुत नजारा...

कुवैत के उत्तरी रेगिस्तान अल-सलमी में रात के वक्त आकाशगंगा (मिल्की वे) के बेहद खूबसूरत नजारे का दीदार करती युवती। इसे देखकर महसूस हो रहा है मानो आकाश धरती पर उतर आया हो। प्रदूषण मुक्त आसमान देखने पर जो रिबननुमा चीज दिखाई देती है, उसे ही मिल्की वे कहा जाता है। इसमें असंख्य तारें और ग्रह मौजूद हैं। अब तक विज्ञानियों ने जितने भी ग्रहों की खोज की है वे सभी आकाशगंगा में मौजूद हैं। यह अनेक रहस्य अपने गर्भ में छिपाए हुए है। एएफपी

पहली बार भू-स्थिर कक्षा में स्थापित होगा स्वदेशी उपग्रह

चेन्नई, आइएएनएस : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार सुबह देश के पहले जियो इमेजिंग सेटेलाइट-1 (जीआइएसएटी-1) को अपने जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल (जीएसएलएवी) एफ-10 से लांच करने की उलटी गिनती शुरू कर दी। इसे अर्थ आब्जर्वेशन सेटेलाइट (ईओएस)-03 नाम दिया गया है। यह देश का पहला ऐसा सेटेलाइट होगा, जिसे भू-स्थिर (जियोस्टेशनरी) कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यानी यह पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति से अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा, जिससे वह पृथ्वी के ऊपर स्थिर प्रतीत होगा और चिह्नित इलाकों पर लगातार नजर रख सकेगा।

ईओएस-03 को 51.70 मीटर लंबे और 416 टन वजनी जीएसएलवी-एफ10 के जरिये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लांच पैड से गुरुवार सुबह लांच करने की योजना है।

- ईओएस-03 के लांच की उलटी गिनती शुरू
- चिह्नित इलाकों पर लगातार रख सकेगा नजर
- 18 मिनट में जीटीओ में स्थापित हो जाएगा

इसरो गुरुवार सुबह देश के पहले जीआइएसएटी-1 को अपने जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल (जीएसएलएवी) एफ-10 से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लांच पैड से लांच करेगा। एएनआइ

ईओएस-03 का वजन 2,268 किलोग्राम है और यह करीब 18 मिनट में जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर आर्बिट (जीटीओ) में स्थापित हो जाएगा। जीटीओ से इसे अपनी प्रोपल्शन प्रणाली के जरिये भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। जीआइएसएटी-1 को दरअसल पांच मार्च, 2020 को लांच किया जाना था, लेकिन लांच के कुछ घंटों पहले इसरो ने कुछ तकनीकी वजह बताते हुए मिशन को स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद कोरोना व देशव्यापी लाकडाउन की वजह से मिशन विलंबित हो गया। इसके बाद जीआइएसएटी-1 को मार्च, 2021 में लांच करने की योजना बनाई गई, लेकिन सेटेलाइट की बैट्री में दिक्कत की वजह से लांच को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा था। बैट्री बदले जाने के बाद सेटेलाइट को लांच करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तभी कोरोना की दूसरी लहर ने देश को चपेट में ले लिया। इसरो बता चुका है कि जीआइएसएटी-1 निश्चित अंतराल पर एक बड़े क्षेत्र की तात्कालिक तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। इससे प्राकृतिक आपदाओं, प्रासंगिक घटनाओं व अल्पकालिक घटनाओं की तत्काल निगरानी भी संभव हो सकेगी। इसरो के मुताबिक, जीआइएसएटी-1 के बाद सितंबर में 1,800 टन वजनी ईओएस-4 या आरआइएसएटी-1ए को लांच किया जाएगा। यह रडार इमेजिंग सेटेलाइट दिन और रात दोनों में तस्वीरें लेने में सक्षम होगा और बादल इसमें बाधा नहीं बनेंगे। इसे पीएसएलवी से लांच किया जाएगा और देश की सुरक्षा में इसकी अहम भूमिका होगी।

फेसबुक ने अपने डेटिंग एप में नया फीचर जोड़ा

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : वर्चुअल डेटिंग को अधिक रोचक और उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अपने डेटिंग एप में आडियो डेट्स सहित कुछ नए फीचर जोड़े हैं। अमेरिकन टेक्नोलाजी न्यूज एंड मीडिया नेटवर्क वर्ज के मुताबिक, आडियो डेट्स यूजर को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने का मौका देता है, जो उससे मेल खाते हैं। जब आप किसी के साथ बात करने का प्रयास करेंगे तो दूसरे व्यक्ति को एक आमंत्रण प्राप्त होगा। यदि वह व्यक्ति आमंत्रण स्वीकार कर लेता है तो दोनों व्यक्ति आपस में चैट कर पाएंगे। फेसबुक यूजर को दो और फीचर की भी सुविधा देने जा रहा है, जिसके मार्फत वे अपने जैसे मेल खाते व्यक्ति से संपर्क कर सकेंगे। पहला फीचर है 'मैच एनीवेयर'। इसके जरिये ऐसे लोगों से संपर्क किया जा सकता है जो एक जगह रुककर काम नहीं करते हैं।

कोरोना काल में बच्चों और किशोरों में बढ़ी मानसिक दिक्कत

कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

कनाडा के कैलगरी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि कोरोना काल के दौरान बच्चों और किशोरों में मानसिक दिक्कतें बढ़ी हैं। यह अध्ययन दुनियाभर के 29 अलग-अलग शोध से एकत्र किए गए डाटा पर आधारित है, जिसमें 80,879 किशोरों को भी शामिल किया गया था। मेडिकल जर्नल जेएएमए पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित निष्कर्षों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक स्तर पर चार में से एक किशोर जहां अवसाद की समस्या से जूझ रहा है, वहीं पांच में से एक किशोर में एंजाइटी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट और शोध के प्रमुख लेखक डा. निकोल रेसिन के मुताबिक, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि समय के साथ यह लक्षण बढ़ते जाते हैं। मेटा विश्लेषण में पूर्वी एशिया के 16, यूरोप के चार, उत्तरी अमेरिका के छह, मध्य और दक्षिण अमेरिका से दो-दो और पश्चिम एशिया से दो अध्ययनों को शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय की क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट डा. शेरी मैडिगन के मुताबिक, बच्चों और किशोरों में मानसिक दिक्कतों की एक बड़ी वजह प्रतिबंधों और लाकडाउन के चलते उनका सामाजिक रूप से पूरी तरह कट जाना है। यह भी देखा जाता है कि अगर प्रतिबंध बढ़ाए जाते हैं तो इस तरह की दिक्कतों में इजाफा होता है। मैडिगन ने कहा कि बच्चों और किशोरों को इन मानसिक दिक्कतों से निकालने के लिए हम तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। -आइएएनएस

स्क्रीन शॉट

सनी देओल के साथ थ्रिलर फिल्म बनाएंगे आर बाल्की

अभिनेता सनी देओल के बीते कई दिनों से फिल्मकार आर बाल्की के साथ फिल्म करने की खबरें आ रही थीं। बुधवार को पा, की एंड का और पैडमैन जैसी फिल्मों के निर्देशक आर बाल्की ने इस फिल्म का आधिकारिक एलान किया। यह एक थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें सनी के साथ दक्षिण भारतीय अभिनेता दुलकर सलमान, अभिनेत्री पूजा भट्ट और श्रेया धनवंतरि भी अहम भूमिकाओं में होंगी। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आधारित और मनोरंजक फिल्में बना चुके आर बाल्की इस फिल्म में पहली बार थ्रिलर जानर में हाथ आजमाएंगे। हालांकि, फिल्म के नाम और पृष्ठभूमि के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस फिल्म के बारे में जारी बयान में आर बाल्की ने कहा, 'कई महीनों के इंतजार के बाद मेरे लिए किसी भी प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करना बहुत उत्साहजनक है। खासतौर पर एक ऐसी जानर की फिल्म को बनाना, जिसको पहले कभी न किया हो, इस अनुभव को और भी उत्साहजनक बनाता है। यह फिल्म काफी दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी। अब मैं इस फिल्म की शूटिंग पूरी करके एडिट रूम में इसे देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं सनी के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूं। मुझे खुशी है कि वह स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह फिल्म उनकी फिल्मोग्राफी में चार चांद लगाएगी।' वहीं, पूजा के बारे में आर बाल्की का कहना है, 'पूजा हमारी इंडस्ट्री की सबसे वर्सेटाइल अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह बहुत स्पष्ट व्यक्तित्व की महिला हैं और कैमरे के सामने ही काम करने के लिए पैदा हुई हैं।'

पहली बार सनी देओल को निर्देशित करेंगे आर बाल्की। इंस्टाग्राम

कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र में अभी भी थिएटर बंद रखे गए हैं। अगले हफ्ते रिलीज हो रही अक्षय कुमार की फिल्म बेल बाटम की कमाई पर भी इसका सीधा असर पड़ा सकता है।

बंद सिनेमाघरों से फिल्म पर पड़ेगा असर

एक के बाद एक कई फिल्मों का ऐलान और शूटिंग भले ही हो रही है, लेकिन अब भी कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज की बाट जोह रही हैं। कई राज्यों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ थिएटर खोल दिए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब भी सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म बेल बाटम को 19 अगस्त को थिएटर में रिलीज करने का ऐलान किया है। यह फिल्म दूसरे फिल्ममेकर्स का हौसला कहीं न कहीं बढ़ाएगी, लेकिन महाराष्ट्र में थिएटर का अब भी न खुलना अक्षय के लिए चिंता का विषय है। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिल्मों का 30 प्रतिशत बिजनेस महाराष्ट्र से होता है। ऐसे में महाराष्ट्र में थिएटर्स के बंद रहने से फिल्म की कमाई पर असर पड़ेगा। अब भी फिल्म की रिलीज में कुछ दिन बाकी है, उम्मीद है यहां भी थिएटर्स खुल जाएंगे। हम फिलहाल ऐसे दौर में हैं, जहां आगे क्या होगा, वह कहा नहीं जा सकता है। डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज हो रही फिल्मों को लेकर अक्षय का मानना है कि ऐसा नहीं है कि डिजिटल प्लेटफार्म पर फिल्म रिलीज होने से सिनेमा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। डिजिटल प्लेटफार्म और सिनेमा दोनों अपनी-अपनी जगह पर कायम रहेंगे। हमारा काम है, अपना काम करते रहना। चार-पांच दिनों में मैं अपनी अगली फिल्म के लिए लंदन रवाना हो जाऊंगा। प्रोटोकाल के हिसाब से हम सब दोनों वैक्सीनेशन लगाकर जाएंगे।

19 अगस्त को सिनेमाघर में रिलीज हो रही है बेल बाटम • इंस्टाग्राम

लता और अमिताभ समेत 15 दिग्गजों की आवाज में रिलीज होगा हम हिंदुस्तानी गाना

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर अक्सर राष्ट्रभक्ति से संबंधित अलग-अलग गाने रिलीज किए जाते रहे हैं। हाल ही में अभिनेता टाइगर श्राफ ने अपनी आवाज में वंदे मातरम म्यूजिक वीडियो रिलीज किया, उसके बाद 13 अगस्त को हम हिंदुस्तानी गाना रिलीज होने के लिए तैयार है। अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी और उनके बेटे प्रियांक शर्मा के धमाका रिकार्ड म्यूजिक लेबल के अंतर्गत बने इस गाने में हिंदी सिनेमा के 15 कलाकारों ने अपनी आवाज दी है।

इन कलाकारों में अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सोनू निगम, अल्का याज्ञनिक, शब्बीर कुमार, कैलाश खेर और पद्मिनी कोल्हापुरी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ-साथ सोनाक्षी सिन्हा, श्रद्धा कपूर, अंकित तिवारी, तारा सुतारिया, श्रुति हासन, सिद्धांत कपूर और जन्नत जुबेर जैसे कलाकारों ने भी अपनी आवाज दी है। यह गाना महामारी की इन मुश्किल परिस्थितियों में सभी को एकता और अखंडता का संदेश देता है। इस गाने को कशिश कुमार ने लिखा है तथा इसको संगीतबद्ध किया है दिलशाद शब्बीर शेख ने। गाने के बारे में निर्माता प्रियांक शर्मा का कहना है, 'इस गाने में पहली बार एक साथ आ रहे इतने सारे लीजेंडरी एक्टर्स और गायक निश्चित रूप से देश और दुनिया के लिए हमारी भावनाओं को एकजुट करेंगे। इसके साथ ही वे इस गाने के माध्यम से प्यार और उम्मीद फैलाने का संदेश भी देंगे।'

कल रिलीज होगा यह गाना। सौ. टीम धमाका रिकार्ड्स

सत्यजित राय को इंडियन फिल्म फेस्टिवल आफ मेलबर्न में दिया जाएगा ट्रिब्यूट

इस साल सत्यजित राय की जन्मशताब्दी पर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें अपने-अपने तरीके से ट्रिब्यूट दिया है। सिनेमा में उनके योगदान का जश्न अब इंडियन फिल्म फेस्टिवल आफ मेलबर्न (आइएफएफएम) भी मनाएगा। सत्यजित राय को ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी फिल्मों को सिनेमाघरों और आनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिये आस्ट्रेलियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। यह फेस्टिवल सिनेमाघरों में 12 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा, जबकि आनलाइन 15 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा। सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों में अप्पू ट्रायोलाजी पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार होंगी। आनलाइन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों में चारूलता, नायक, महापुरुष, महानगर जैसी कई फिल्में, डाक्यूमेंट्री फिल्म ए रे आफ लाइट शामिल हैं। उनकी डाक्यूमेंट्री सीरीज में बतौर संगीतकार और कंपोजर भी उनके सफर को दिखाया जाएगा। दैनिक जागरण से बातचीत में आइएफएफएम की फेस्टिवल डायरेक्टर मितू भौमिक लैंग कहती हैं कि सत्यजित राय का सिनेमा आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को उजागर करके हमारे समाज का एक आकर्षक चित्र पेश करता है। उनकी सरलता, काम करने की शैली और रचनात्मक चीजों के लिए जुनून को दुनिया भर के सिनेप्रेमी पसंद करते हैं। हम आइएफएफएम में उनकी जन्म शताब्दी मनाने के लिए उनकी फिल्मों को पेश करते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

वर्षों किरदार के लुक में रहे रित्विक

कुछ किरदारों से कलाकारों का इतना जुड़ाव हो जाता है कि वह उनके लिए अपना सारी ऊर्जा लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ अभिनेता रित्विक धनजानी ने भी अपनी आगामी वेब सीरीज कार्टल के लिए किया है। इस सीरीज को बनने में लगभग तीन साल का वक्त लगा है। इन तीन सालों में रित्विक अपने किरदार के लुक में ही रहे हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में रित्विक ने बताया कि शो के किरदार में मैं तीन साल रहा हूं। मेरे कलर वाले बाल थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। इस लुक की वजह से मैंने कई प्रोजेक्ट्स को ना कहा। मुझे अपने इस किरदार से इतना प्यार हो गया था कि अगर यह किरदार वास्तविक जीवन में होता तो मैं उससे शादी कर लेता। मेरा किरदार मुंबइया भाषा में बात करता है। मेरे आसपास ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग रहे हैं। मेरे निर्माता ने एक सज्जन आदमी से मुझे मिलवाया। उनका लहजा और व्यक्तित्व कड़क था। उन्हें देखकर लगा कि यह मेरा किरदार होगा। मैंने चुपके-चुपके उनकी आवाज रिकार्ड करनी शुरू की। उनको पता नहीं है कि मैं उनकी आवाज रिकार्ड करता था। इतने कलाकारों के बीच काम करने को लेकर रित्विक को कोई इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती है। वह कहते हैं कि हर किरदार एक कड़ी है, जिससे जुड़कर स्क्रिप्ट बनती है। मैं अपना 200 प्रतिशत देता हूं, ऐसे में स्क्रीन टाइम को लेकर इनसिक्योरिटी होने का सवाल ही नहीं उठता है। कार्टल शो 20 अगस्त से ओटीटी पर स्ट्रीम होगा।

करीब तीन साल में बनकर तैयार हुआ कार्टल शो • इंस्टाग्राम

किशोर कुमार की बायोपिक बनेगी

इन दिनों हिंदी सिनेमा में बायोपिक फिल्मों की बहार है। एक तरफ आज जहां कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक फिल्म शेरशाह अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रही है, वहीं आगामी दिनों में शाबाश मिट्ठू, गंगूबाई काठियावाड़ी, सरदार उधम सिंह और थलाइवी जैसी कई बायोपिक कतार में हैं। इसी क्रम में बीते कई दिनों से गायक और अभिनेता किशोर कुमार की बायोपिक की भी खबरें आ रही थी। पहले फिल्मकार अनुराग बासु इस बायोपिक को बनाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। अब किशोर कुमार की बायोपिक उनके बेटे और गायक अमित कुमार बनाएंगे। अमित ने एक इंटरव्यू के दौरान यह रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि वह, उनके भाई सुमित कुमार और उनका परिवार किशोर कुमार की बायोपिक को लेकर पहले से ही योजना तैयार कर चुका है। इस बायोपिक का निर्देशन स्वयं अमित ही करेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा से यही चाहता था कि उनकी (किशोर कुमार) बायोपिक हम ही बनाएं। आखिर उनके परिवार से बेहतर उन्हें कौन जानता है?' अमित के मुताबिक, इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने में कम से कम एक साल का वक्त लगेगा। वह शूटिंग की शुरुआत अपने ही परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू से करेंगे। लव स्टोरी, हम पांच और कभी खुशी कभी गम फिल्मों के गाने गा चुके अमित कुमार इससे पहले 1989 में फिल्म ममता की छांव में का निर्देशन कर चुके हैं।

कई फिल्मों के गाने भी गा चुके हैं अमित • इंस्टाग्राम

जतिन सियाल होंगे पिता के किरदार में। सौ. टीम सोनी लिव

पारिवारिक रिश्तों पर बनी है पाटलक

शहरी जीवन में हर कोई अपने आप में ही इतना बिजी है कि उसे दूसरों के लिए क्या खुद के लिए भी वक्त नहीं है। वहां एक-दूसरे से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म भी अब पारिवारिक शोज ला रहा है। सोनी लिव का नया शो पाटलक भी पारिवारिक बांडिंग को दिखाएगा। इस शो की कहानी में परिवार का मुखिया चाहता है कि वह अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार को अपने पास रखे। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर बीमार होने का नाटक करता है, ताकि उसकी बेटी और दो शादीशुदा बेटे उसके साथ रहने आ जाएं। शो में जतिन सियाल पिता का किरदार निभा रहे हैं, वहीं अभिनेत्री किटू गिडवाणी उनकी पत्नी के किरदार में होंगी। दैनिक जागरण से बातचीत में जतिन कहते हैं कि पाटलक की शूटिंग करना मेरे लिए दिलचस्प अनुभव रहा है। हर परिवार में जब भी सभी लोग साथ में आते हैं तो वे पल बहुत खास होते हैं। कई यादें हमेशा के लिए बन जाती हैं। जल्दी ही यह शो सोनी लिव पर रिलीज होगा।

शिवगामी देवी के किरदार की तैयारी में जुटी हैं वामिका

डिजिटल प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स के लिए बन रही वेब सीरीज बाहुबली: बिफोर द बिगनिंग को अब नए सिरे से शूट किया जा रहा है। फिल्मकार एस एस राजमौली निर्देशित फिल्म बाहुबली में बाहुबली की मां शिवगामी देवी के किरदार पर केंद्रित इस वेब सीरीज में पहले अभिनेत्री मृणाल ठाकुर शिवगामी का किरदार निभा रही थी। साल 2018 में उन्होंने इस वेब सीरीज की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन प्रोजेक्ट में ज्यादा समय लगने और समय की अनुपलब्धता के कारण मृणाल ने यह वेब सीरीज छोड़ दी थी। उसके बाद अभिनेत्री वामिका गब्बी को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया और अब इस शो की दोबारा शूटिंग की जा रही हैं। खबरें हैं कि एस एस राजामौली के प्रोडक्शन में बन रहे इस शो में के लिए वामिका कड़ी मेहनत कर रही हैं। इस बात को और भी ज्यादा बल मिलता है वामिका के हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट से। जिसमें वह तलवारबाजी का जमकर अभ्यास करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, 'अपने शाट्स के बीच मैं कभी आराम नहीं करती हूं।' वामिका इस फिल्म में शिवगामी देवी के निडर और न्यायप्रिय व्यक्तित्व को प्रदर्शित करेंगी। सिक्सटीन और मौसम जैसी फिल्मों की अभिनेत्री वामिका इससे पहले वेब सीरीज ग्रहण में नजर आई थी। देवा कट्टा और प्रवीण सत्तारु के निर्देशन में बन रहे इस शो में वामिका के साथ तमिल और तेलुगु अभिनेत्री नयनतारा भी अहम भूमिका में हैं।

तलवारबाजी करती दिखेंगी वामिका गब्बी • पीआर टीम